



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-8] रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 जून, 2007 ई0 (आषाढ़ 02, 1929 शक सम्वत्) [संख्या-25

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	121-124	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	315-391	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	—	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	15-16	975
स्टोर्स पर्वेज-स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड-पत्र आदि	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

विधायी एवं संसदीय कार्य

अधिसूचना

11 जून, 2007 ई०

संख्या 3321(ऊर्जा)/I-2007-02(3)/4/2004-चूँकि, उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 की धारा 6 के अधीन उत्तरांचल शासन उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में लागू विधि को आदेश द्वारा निरसन अथवा संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन एवं उपान्तरण कर सकता है जो आवश्यक व समीचीन हों;

तथा, चूँकि, उत्तरांचल विद्युत (अनन्तिम निर्धारण आदेश के तामील की रीति) नियम, 2005 उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 की धारा 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में लागू है;

अतः, अब, उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 52, वर्ष 2006) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तराखण्ड, उत्तरांचल विद्युत (अनन्तिम निर्धारण आदेश के तामील की रीति) नियम, 2005 को उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्वधीन लागू रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

उत्तराखण्ड विद्युत (अनन्तिम निर्धारण आदेश के तामील की रीति) नियम, 2005 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007

1-संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ-

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्युत (अनन्तिम निर्धारण आदेश के तामील की रीति) नियम, 2005 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2-"उत्तरांचल" के स्थान पर "उत्तराखण्ड" पढ़ा जाना-

उत्तरांचल विद्युत (अनन्तिम निर्धारण आदेश के तामील की रीति) नियम, 2005 में जहां-जहां शब्द "उत्तरांचल" आया है, वहां वहां शब्द "उत्तराखण्ड" पढ़ा जाएगा।

आज्ञा से,

इन्दिरा आशीष,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3321 (Urja)/I/2007-02(3)/4/2004, dated June 11, 2007 for general information :

NOTIFICATION

June 11, 2007

No. 3321 (Urja)/I/2007-02(3)/4/2004--WHEREAS, Under section 6 of the Uttaranchal (Alteration of Name) Act, 2006, the Uttarakhand Government may, by order, make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as necessary or expedient;

AND, WHEREAS, the **Uttaranchal Electricity (Manner of Service of Provisional Assessment Order) Rule, 2005** is in force in the State of Uttarakhand Under Section 6 of the Uttaranchal (Alteration of Name) Act, 2006;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by section 6 of the Uttaranchal (Alteration of Name) Act, 2006 (Act No. 52 of 2006), the Governor is pleased to direct that the **Uttaranchal Electricity (Manner of Service of Provisional Assessment Order) Rule, 2005** shall have applicability to the State of Uttarakhand Subject to the provisions of following Order:-

UTTARAKHAND ELECTRICITY (MANNER OF SERVICE OF PROVISIONAL ASSESSMENT ORDER) RULE, 2005 ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2007

1. Short title and Commencement--

(1) This Order may be called the Uttarakhand Electricity (Manner of Service of Provisional Assessment Order) Rule, 2005 Adaptation and Modification Order, 2007.

(2) It shall come in to force at once.

2. "Uttarakhand" to be read instead of "Uttaranchal"--

In the Uttarakhand Electricity (Manner of Service of Provisional Assessment Order) Rule, 2005 wherever the expression "Uttaranchal" occurs it shall to be read as "Uttarakhand."

By Order,

INDIRA ASHISH,
Secretary.

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

14 जून, 2007 ई०

संख्या 76 II/I-2007-05-26/2007-चूँकि, उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 की धारा 6 के अधीन उत्तरांचल शासन उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन अथवा संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन एवं उपान्तरण कर सकता है जो आवश्यक व समीचीन हों;

तथा, चूँकि, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दंड) नियमावली, 1977) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002, उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 की धारा 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में लागू है;

अतः, अब, उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 52, वर्ष 2006) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दंड) नियमावली, 1977) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 को उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन लागू रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दंड) नियमावली, 1977] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007

1-संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ--

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दंड) नियमावली, 1977] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2-"उत्तरांचल" के स्थान पर "उत्तराखण्ड" पढ़ा जाना--

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बिजली के तार और ट्रांसफार्मर (चोरी का निवारण और दंड) नियमावली, 1977) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में जहाँ-जहाँ शब्द "उत्तरांचल" आया है, वहाँ वहाँ शब्द "उत्तराखण्ड" पढ़ा जाएगा।

आज्ञा से,

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 76 II/I-2007-05-26/2007, dated June 14, 2007 for general information :

NOTIFICATION

June 14, 2007

No. 76 II/I-2007-05-26/2007—WHEREAS, under section 6 of the Uttaranchal (Alteration of Name) Act, 2006, the Uttarakhand Government may, by order, make such adaptation and modification of the law by way of repeal or amendment as necessary or expedient;

AND, WHEREAS, the **Uttaranchal [The Uttar Pradesh Electric Wire and Transformers (Prevention and Punishment) Rule, 1977] Adaptation and Modification Order, 2002** is in force in the State of Uttarakhand under Section 6 of the Uttaranchal (Alteration of Name) Act, 2006;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Uttaranchal (Alteration of Name) Act, 2006 (Act No. 52 of 2006), the Governor is pleased to direct that the **Uttaranchal [The Uttar Pradesh Electric Wire and Transformers (Prevention and Punishment) Rule, 1977] Adaptation and Modification Order, 2002** shall have applicability to the State of Uttarakhand subject to the provisions of following Order:—

THE UTTARAKHAND [THE UTTAR PRADESH ELECTRIC WIRE AND TRANSFORMERS (PREVENTION AND PUNISHMENT) RULE, 1977] ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2007

1. Short title and Commencement—

(1) This Order may be called the **Uttarakhand [The Uttar Pradesh Electric Wire and Transformers (Prevention and Punishment) Rule, 1977] Adaptation and Modification Order, 2007**.

(2) It shall come in to force at once.

2. "Uttarakhand" to be read instead of "Uttaranchal"—

In the "Uttaranchal (The Uttar Pradesh Electric Wire and Transformers (Prevention and Punishment) Rule, 1977] Adaptation and Modification Order, 2002 wherever the expression "Uttaranchal" occurs, it shall to be read as "Uttarakhand."

By Order,

SHATRUGHNA SINGH,
Secretary.



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 जून, 2007 ई0 (आषाढ़ 02, 1929 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

80 वसन्त विहार, फेज-1, देहरादून

अधिसूचना

अप्रैल 05, 2007 ई0

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग विनियम, 2007 (वितरण कोड) विनियम, 2007

सं0 एफ(9)13/आर जी/यूईआरसी/2007/19-विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 व वितरण व फुटकर आपूर्ति लाइसेन्स के खण्ड 18 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित्त सभी शक्तियों से सक्षम हो कर, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:-

अध्याय 1-सामान्य

1.1 सक्षिप्त नाम, प्रारम्भ व निर्वचन :

- (1) इन विनियमों का नाम "उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (वितरण कोड) विनियम, 2007" होगा।
- (2) ये विनियम सभी वितरण प्रणाली सहभागियों, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, पर लागू होंगे:-
 - (क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी,
 - (ख) वितरण प्रणाली से जुड़े खुली पहुंच वाले उपभोक्ता,
 - (ग) वितरण प्रणाली से जुड़े अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी,
 - (घ) अन्तःस्थापित उत्पादक, व
 - (ङ) बड़े उपभोक्ता।

यह विनियम दिनांक 14.04.2007 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के विवाद (आख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य है।

- (3) ये विनियम, सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- (4) ये विनियम, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के साथ पठित विद्युत नियम, 1956 व इस संबंध में किसी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी विनियमों के उपबन्धों के अनुरूप, न कि उनसे भिन्न रूप, से निर्वाचित व क्रियान्वित होंगे।

1.2 परिभाषाएं :

- (1) वितरण कोड में, जब तक कि विषय वस्तु या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, या उससे असंगत न हो, निम्नलिखित शब्दों व अभिव्यक्तियों का अभिप्राय निम्नलिखित होगा:-
- (क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम सं0 2003 का 36);
- (ख) "अनुबंध" से अभिप्राय है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता द्वारा एक अनुबन्ध में शामिल होना;
- (ग) "उपकरण" से अभिप्राय है, विद्युत उपकरण तथा इसमें सभी यंत्र, फिटिंग्स व विद्युत वितरण प्रणाली से संबंधित उप साधन व उपयंत्र सम्मिलित हैं;
- (घ) "सी.बी.आई.पी." से अभिप्राय है, केन्द्रीय सिंचाई व ऊर्जा बोर्ड;
- (ङ) "सी.ई.ए." से अभिप्राय है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण;
- (च) "सर्किट" से, अभिप्राय है, विद्युत शक्ति भेजने के उद्देश्य हेतु विद्युत चालक की व्यवस्था व प्रणाली या प्रणाली की एक शाखा संरचित करना;
- (छ) "आयोग" से अभिप्राय है, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग;
- (ज) "विद्युत चालक" से अभिप्राय है, विद्युत चालित करने हेतु उपयोग में लाये जाने वाले व विद्युत प्रणाली से जुड़े कोई वायर, केबल, छड़, ट्यूब रेल या प्लेट;
- (झ) "संयोजित भार" से अभिप्राय है, ऊर्जा का उपयोग करने वाले सभी उपकरण जिनमें उचित रूप से वायरिंग की गई हो तथा अनुज्ञप्तिधारी की ऊर्जा वितरण प्रणाली से संयोजित हो, जिनमें उपभोक्ता के अहाते में सुवाह्य उपकरण भी सम्मिलित हैं, की विनिर्माता की रेटिंग का पूर्णयोग। इनमें स्पेयर प्लग, सॉकेट्स का भार, अग्निशमन के उद्देश्य हेतु अनन्य रूप से संस्थापित भार सम्मिलित नहीं होगा। पानी व कमरा गर्म करने या कमरा ठंडा करने में उपकरणों के भार में से जो अधिक हो, उसका भार प्रचलित अवधि (ठंडा करने के उपयोग हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर व गर्म करने के उपयोग हेतु 01 अक्टूबर से 31 मार्च) के अनुसार हिसाब में लिया जायेगा;
- संयोजित भार की परिभाषा का उपयोग केवल सीधे चोरी या ऊर्जा के बेईमानीपूर्वक निकाले जाने या ऊर्जा के अनाधिकृत उपयोग के मामले में आकलन के उद्देश्य से किया जायेगा;
- (ञ) "नियन्त्रक व्यक्ति" से अभिप्राय है, सीमा पार सुरक्षा हेतु तकनीकी क्षमता व उत्तरदायित्व योग्य व्यक्ति के रूप में पहचाना गया व्यक्ति;
- (ट) "डी.सी.आर." से अभिप्राय है, वितरण कोड समीक्षा;
- (ठ) "डी.सी.आर.पी." से अभिप्राय है, वितरण कोड समीक्षा पैनल;
- (ड) "अन्तः स्थापित" से अभिप्राय है, अन्तर्राज्यीय विद्युत प्रणाली से सीधा विद्युत संयोजन होना;
- (ढ) "अतिरिक्त उच्च वोल्टता (ई.एच.टी.)" से अभिप्राय है, भारतीय विद्युत नियम, 1956 के अधीन अनुज्ञेय प्रतिशत दर परिवर्तन की शर्त पर, सामान्य स्थिति के अन्तर्गत 33000 वोल्ट्स व उससे अधिक वोल्टेज;
- (ण) "जी.एस.एस." से अभिप्राय है, ग्रिड सब स्टेशन;
- (त) "उच्च वोल्टता (एच.टी.)" से अभिप्राय है, भारतीय विद्युत नियम, 1956 के अधीन अनुज्ञेय प्रतिशत दर परिवर्तन की शर्त पर सामान्य स्थितियों के अंतर्गत 650 वोल्ट्स एवं 33000 वोल्ट्स के मध्य वोल्टेज;
- (थ) "भारतीय मानक (आई.एस.)" से अभिप्राय है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित मानक व विशिष्टियां;
- (द) "इन्टर फेस प्वाइंट" से अभिप्राय है वह प्वाइंट जिस पर उपयोग करने वाले की विद्युत प्रणाली, अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से संयोजित होती है;

- (घ) "निम्न वोल्टता (एल.टी.)" से अभिप्राय है, विद्युत नियम के अधीन अनुज्ञेय प्रतिशत दर परिवर्तन की शर्त पर, सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत फेज व न्यूट्रल के मध्य 230 वोल्ट्स या किन्हीं दो फेज के मध्य 400 वोल्ट्स की वोल्टेज;
- (न) "पावर फैक्टर" से अभिप्राय है, सक्रिय ऊर्जा (के.डब्ल्यू.) एवं प्रकट ऊर्जा (के.वी.ए.) का अनुपात;
- (प) "पी.टी.डब्ल्यू." से अभिप्राय है, कार्य का अनुज्ञा पत्र;
- (फ) "आर.ई.सी." से अभिप्राय है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम;
- (ब) "पारेषण प्रणाली" से अभिप्राय है, एक पावर स्टेशन से एक सबस्टेशन को या दूसरे पावर स्टेशन को या सबस्टेशनों के मध्य या, विद्युत के पारेषण के संबंध में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग किये जाने वाले या उसके स्वामित्व वाली वितरण प्रणाली कोई संयंत्र व उपकरण व मोटर्स के साथ किसी बाहरी अन्तःसंयोजन उपकरण से अन्तःसंयोजन तक विद्युत पारेषण के उद्देश्य से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके स्वामित्व में व/या उसके द्वारा परिचालित अतिरिक्त उच्च वोल्टता (जनरेटर अन्तः संयोजन सुविधा को छोड़कर) पर परिचालित अतिरिक्त उच्च वोल्टता लाईन्स समावेशित प्रणाली, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली का कोई भाग सम्मिलित नहीं है;
- (म) "उपयोग कर्ता" से अभिप्राय है, ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली का उपयोग कर रहा हो, जिस पर यह कोड लागू हो या जिसके साथ विद्युत सीमा समानता हो। कोई अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व उत्पादक इकाई जोकि वितरण प्रणाली से संबंधित हो, इस शब्द में सम्मिलित है;
- (म) इन विनियमों में उपयोग किये गये सभी शब्द व अभिव्यक्तियाँ, जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं की गई हैं, उन पर वही अर्थ होगा जोकि उक्त अधिनियम में उनके लिये समनुदिष्ट हैं।

1.3 उद्देश्य :

- (1) यह सुनिश्चित करना कि वितरण प्रणाली दक्षतापूर्ण, समन्वित व मितव्ययी रूप से चलाई व विकसित की जाये तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी व सभी वितरण प्रणाली भागीदार, अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से संबंधित बाध्यताओं का अनुपालन करें।
- (2) वितरण कोड नियमों के एकल समूह को, वितरण तंत्र का उपयोग करने के लिये एक साथ लाता है तथा निम्नलिखित प्रदान करता है :-
- (क) अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली तथा वे जो इससे जुड़े हुए हैं, या जुड़ना चाहते हैं, के मध्य सक्रिय संबंध दृष्टिकोण;
- (ख) परिचालन, अनुरक्षण, विकास की सुगमता तथा मितव्ययी व भरोसेमंद ऊर्जा वितरण तंत्र की योजना।

1.4 वितरण कोड की परिधि :

- (1) यू.पी.सी.एल. वितरण व खुदरा आपूर्ति लाईसेंस यह उपबंधित करता है कि वितरण कोड संयोजनों, परिचालनों व वितरण प्रणाली से संबंधित सभी तकनीकी पहलुओं को समावेशित करेगा जिसमें वितरण प्रणाली के परिचालन व उपयोग जहां तक वे सुसंगत हैं, वितरण प्रणाली से संबंधित विद्युत लाइनें व विद्युत संयंत्र व उपकरण सम्मिलित हैं तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा :-
- (क) तकनीकियों को विनिर्दिष्ट करते हुए संयोजन शर्तों में समावेश के साथ वितरण योजना, अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से जुड़े या जुड़ने के इच्छुक किसी व्यक्ति द्वारा अनुपालन किये जाने वाले परिचालन व अभिकल्पना का मानदण्ड तथा आपूर्ति क्षेत्र में वितरण लाईन व सेवा लाईन बिछाने के लिये अपेक्षित योजना को विनिर्दिष्ट करते हुए योजना मोड्स, अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली की योजना व विकास में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदित किये जाने वाले तकनीकी व अभिकल्पना मानदण्ड व प्रक्रियाएं, तथा
- (ख) सामान्य व असामान्य दोनों परिचालन स्थितियों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली की सुरक्षा व आपूर्ति की गुणवत्ता व सुरक्षित परिचालन हेतु जहां तक आवश्यक हो, अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली के संबंध में, वे शर्तें विनिर्दिष्ट करते हुए एक वितरण कोड, जिसके अधीन अपनी वितरण प्रणाली का अनुज्ञप्तिधारी परिचालन करेगा तथा जिसके अधीन व्यक्ति अपने संयंत्र व/या वितरण प्रणाली परिचालित करेंगे।

- (2) अनुज्ञप्तिधारी व अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से जुड़े या जुड़ने के इच्छुक उपयोगकर्ताओं द्वारा अपेक्षित अनुपालनों के लिये वितरण कोड सर्वांगपूर्ण नहीं है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा उपयोगकर्ताओं/उपभोक्ताओं को प्रवृत्त सुसंगत विधि के अधीन विभिन्न मोड्स, मानकों व विनियमों में नियत अपेक्षाओं को भी पूरा करना चाहिये।
- (3) वितरण कोड, प्रणाली के नेटवर्क के अनुसार उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के मध्य विद्युत आपूर्ति व उसके वितरण की आउटटेज या कमी की स्थिति में वितरण प्रबंधन के सम्बन्ध में भी कार्य करता है, किन्तु जिन उपभोक्ताओं के पास केप्टिव ऊर्जा संयंत्र है, वे आउटटेज या कमी की स्थिति में प्रथम प्राथमिकता के रूप में अनुज्ञप्तिधारी के बचाव में आये आदेशों तथा अनुज्ञप्तिधारी के अनुदेशों पर तुरन्त विद्युत आपूर्ति बंद कर भार में कमी करेंगे।
- (4) वितरण कोड में, वितरण व खुदरा आपूर्ति लाइसेन्स के खण्ड 19 में अपेक्षानुसार, वितरण प्रणाली योजना व सुरक्षा मानक, वितरण प्रणाली परिचालन मानक सम्मिलित है। वितरण व खुदरा आपूर्ति लाइसेन्स के खण्ड 19 के अनुसार—
 - (क) अनुज्ञप्तिधारी का लाइसेन्स प्रभावी होने के पश्चात् छः माह के भीतर वह आपूर्तिकर्ताओं, उत्पादक कंपनियों तथा अन्य ऐसे व्यक्तियों से, जिन्हें आयोग विनिर्दिष्ट करे, के साथ परामर्श कर, वितरण प्रणाली योजना व सुरक्षा मानकों तथा वितरण परिचालन मानकों हेतु प्रस्ताव तैयार करेगा व आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। इस प्रस्ताव में, मानदण्ड नियत करते हुए एक कथन सम्मिलित होगा जिसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी का मानकों के साथ अनुपालन परिभाषित किया जायेगा। ऐसे मानदण्ड में आपूर्ति-अवरोधों का प्रकार व संख्या तथा विनिर्दिष्ट ऊर्जा आपूर्ति गुणवत्ता मानकों से विचलन सम्मिलित होना चाहिये;
 - (ख) प्रस्ताव के दस्तावेज में अनुज्ञप्तिधारी का एक कथन सम्मिलित होना चाहिए कि वह मानकों को लागू करने के लिए किस प्रकार प्रस्तावित करेगा ताकि—
 - (i) उत्तराखण्ड राज्य के भीतर संयंत्र, उपकरणों व उपयंत्रों का संतोषजनक मात्रा में मानकीकरण सुनिश्चित कर सकें,
 - (ii) अतिरिक्त पुर्जों की आवश्यकता हेतु नीति का विकास व पालन कर सकें।

1.5 वितरण कोड का क्रियान्वयन व परिचालन :

- (1) अनुज्ञप्तिधारी, अपने आपूर्ति क्षेत्र के भीतर इसके क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होगा। उपयोगकर्ता इस कोड के उपबन्धों का अनुपालन करेंगे।
- (2) यदि किसी उपयोगकर्ता को, वितरण कोड के किसी उपबन्ध के अनुपालन में कोई कठिनाई है, तो वह तुरन्त, बिना विलंब किये यथास्थिति वितरण अनुज्ञप्तिधारी या आयोग, को सूचित करेगा।
- (3) बिना किसी युक्तियुक्त आधार के लगातार अनुपालन न करना, अधिनियम के अधीन विचलन स्थापित करेगा तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से उपयोगकर्ता के संयंत्र या उपकरण के विच्छेदन का कारण बन सकता है। हर्जाने के व अन्य भुगतान सहित विच्छेदन के परिणामों की जिम्मेदारी ऐसे उपयोगकर्ता की है जो निरन्तर वितरण कोड का उल्लंघन करता है।
- (4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण कोड के किसी उपबन्ध का अनुपालन न करना, अधिनियमों या लाइसेन्स में दिये गये उपबन्धों के अनुसार परिणाम प्रदान करेगा। तथापि, वितरण कोड के अनुपालन न करने की स्थिति में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण कोड के अनुपालन हेतु एक कार्ययोजना तैयार कर आयोग को प्रस्तुत करेगा। उपलब्ध संसाधनों व विद्यमान परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यदि यह पाया जाता है कि उस अवधि के लिये अनुपालन साध्य नहीं है तो आयोग एक अवधि विशेष के लिये किसी उपबन्ध से अनुज्ञप्तिधारी को छूट प्रदान कर सकता है।

1.6 वितरण कोड की सीमायें :

- (1) इस कोड में समादेशित कुछ भी, सुसंगत खण्डों के अधीन विद्युत अधिनियम, 2003 में उल्लिखित से अधिक या अधिक दुर्भर अधिरोपित बाध्यता/उपभोक्ताओं/वितरण अनुज्ञप्तिधारियों पर कर्तव्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जाना चाहिए।
- (2) वितरण कोड में, वितरण प्रणाली में दिन-प्रतिदिन की तकनीकी परिस्थितियों के प्रबंधन हेतु प्रक्रियाओं का समावेश है, जिसमें सामान्य व असामान्य दोनों परिस्थितियों में संभावित रूप से सामने आने वाली अनेकों परिचालन परिस्थितियों पर विचार किया गया है। वितरण कोड सभी संभावित परिचालन परिस्थितियों की पूर्व कल्पना नहीं कर सकता। अतः उपयोगकर्ताओं को यह समझना चाहिए व स्वीकार करना चाहिये कि ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में वितरण अनुज्ञप्तिधारी को लाइसेन्स के अधीन दायित्वों को निभाने के लिये निर्णायक रूप से व शीघ्रता से कार्यवाही करना आवश्यक होगा। उपयोगकर्ता ऐसी परिस्थितियों में वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी युक्तियुक्त सहायता व सहयोग प्रदान करेंगे जैसी उसके लिये आवश्यक हो। संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी, तथापि, ऐसे सभी मामलों को, 'वितरण कोड का प्रबंधन' कोड के अध्याय 2 के अंतर्गत वर्णित वितरण कोड समीक्षा पैनल की अगली बैठक में अनुसमर्थन हेतु विचारार्थ भेजेगा।

1.7 गोपनीयता :

वितरण कोड के निबंधनों के अधीन, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उपयोगकर्ताओं से उनके कार्य के बारे में सूचना प्राप्त करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण कोड द्वारा अपेक्षित के अलावा, ऐसी सूचना देने वाले की लिखित पूर्व सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को यह सूचना प्रकट नहीं करेगा, जब तक कि केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग या प्राधिकारी द्वारा यह अपेक्षित न हो।

1.8 विवादों के निपटारे के लिये प्रक्रिया :

उपयोगकर्ता व वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य वितरण कोड में उपबंधित किन्हीं विनियमों के निर्वचन के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में, मामले को वितरण कोड समीक्षा पैनल को संदर्भित किया जायेगा तथा इसके पश्चात् इसे उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग को संदर्भित किया जायेगा। आयोग का निर्णय अंतिम तथा दोनों पक्षों पर बाध्य होगा।

अध्याय 2-वितरण कोड का प्रबंधन

2.1 उद्देश्य :

इस अध्याय में, वितरण कोड के प्रबंधन के तरीके, कोई अपेक्षित परिवर्तन/संशोधन करना तथा इस संबंध में वितरण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता के उत्तरदायित्व निश्चित किये गये हैं। इस अनुभाग में सभी पक्षों का समान रूप से ध्यान रखते हुए संशोधनों को सुगम बनाया गया है।

2.2 वितरण कोड की समीक्षा पैनल :

- (1) आयोग द्वारा एक स्थायी वितरण कोड समीक्षा पैनल का गठन किया जायेगा जिसमें वितरण अनुज्ञापी के प्रतिनिधियों व इस कोड के उपबन्धों के अनुसार वितरण प्रणाली के उपयोगकर्ताओं का समावेश होगा।
- (2) इस वितरण कोड में, छोटा या बड़ा, कोई भी परिवर्तन, वितरण कोड समीक्षा पैनल द्वारा विचार-विमर्श कर स्वीकार करने व तत्पश्चात् आयोग द्वारा अनुमोदित किये बिना नहीं किया जायेगा। किन्तु असामान्य स्थिति में, जहां वितरण कोड में कुछ उपबंधों में संशोधन किये बिना दैनिक परिचालन संभव नहीं है, वहां आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने से पहले एक अनंतिम संशोधन लागू किया जा सकेगा। परन्तु ऐसा आपात आधार पर बैठक बुलाकर एक विशेष समीक्षा पैनल में चर्चा के पश्चात् ही किया जा सकेगा। अनंतिम संशोधन के संबंध में तुरन्त आयोग को सूचित किया जायेगा। आयोग, वितरण कोड को तदनुसार संशोधित करने के लिये अपेक्षित निदेश जारी करेगा, जोकि उन निदेशों में विनिर्दिष्ट हों तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे निदेशों का तुरन्त अनुपालन करेगा।
- (3) वितरण कोड समीक्षा पैनल का निर्माण निम्नलिखित सदस्यों के द्वारा होगा जिन्हें आयोग द्वारा अधिसूचित किया जायेगा :-

- (क) संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी का निदेशक (तकनीकी/परिचालन)।
- (ख) राज्य में अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों में से महाप्रबंधक स्तर का अधिकारी।
- (ग) एस.टी.यू. से महाप्रबंधक स्तर का अधिकारी।
- (घ) एस.एल.डी.सी. द्वारा नामित एक सदस्य।
- (ङ) राज्य के स्वामित्व वाली उत्पादक कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य।
- (च) राज्य में अन्य उत्पादन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य।
- (छ) खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य।
- (ज) औद्योगिक उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य।
- (झ) घरेलू/व्यावसायिक उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य।
- (ञ) कृषि उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य।

2.3 कार्यालय का कार्यकाल :

वितरण कोड समीक्षा पैनल का अध्यक्ष, वितरण अनुज्ञप्तिधारी का निदेशक (तकनीकी/परिचालन) होगा। वितरण कोड समीक्षा पैनल तथापि, वितरण कोड के अधीन स्थायी होगा। वितरण कोड समीक्षा पैनल में सभी सदस्य अपनी मूल संस्था द्वारा परिवर्तित/प्रतिस्थापित किये जाने तक कार्यभार संभालेंगे।

2.4 डी.सी.आर. पैनल समर्थक स्टाफ व परिचालन लागत :

एक विशिष्ट समय पर डी.सी.आर. पैनल के अध्यक्ष का कार्यालय संभाल रहे वितरण अनुज्ञप्तिधारी के सदस्य, डी.सी.आर. पैनल परिचालन की सहायता हेतु अपेक्षित सचिवीय कर्मचारी उपलब्ध करायेंगे। ऐसी सचिवीय सहायता पर आने वाली लागत भी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जायेगी।

2.5 समीक्षा पैनल के कार्य :

समीक्षा पैनल के कार्य होंगे—

- (1) निरंतर संवीक्षा व समीक्षा के अधीन वितरण कोड व इसके कामकाज का अनुरक्षण।
- (2) उपयोगकर्ता द्वारा किये गये समीक्षा हेतु निवेदनों पर विचार करना व वितरण कोड में कारण प्रदान करते हुए परिवर्तनों के लिये संस्तुतियों का प्रकाशन करना।
- (3) वितरण कोड के निर्वचन व क्रियान्वयन पर मार्गदर्शन प्रदान करना।
- (4) किसी उपयोगकर्ता द्वारा उठाई गयी समस्याओं का परीक्षण तथा साथ ही उन समस्याओं का निदान करना।
- (5) यह सुनिश्चित करना कि वितरण कोड में प्रस्तावित परिवर्तन/आशोधन, उस समय पर प्रवृत्त मानक तकनीकी पुस्तिकाओं या मार्गदर्शकों, मोड्स, विधियों, अधिनियमों, नियमों व विनियमों के अनुरूप व संगत हैं।
- (6) वितरण कोड से संबंधित विभिन्न मामलों के विस्तृत अध्ययन हेतु एक उप समिति का गठन करना तथा निष्कर्षों व संस्तुतियों का पैनल सदस्यों व संबंधित व्यक्तियों तक परिचालित करना।
- (7) इन उप समितियों द्वारा उपबंधित किये अनुसार, मामलों (उप समिति के निष्कर्षों व संस्तुतियों के संबंध में) में विचार-विमर्श हेतु व्यवस्था करना।
- (8) अपेक्षानुसार उप समिति की बैठक बुलाना किन्तु प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक बुलाना।
- (9) उपयोगकर्ताओं अथवा उपयोगकर्ताओं के समूहों के साथ, समीक्षा पैनल विचारार्थ।

2.6 समीक्षा व परिशोधन :

- (1) वितरण कोड में किसी प्रकार का संशोधन चाहने वाले उपयोगकर्ता, समीक्षा पैनल के सचिव (वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नामित) को लिखित निवेदन भेजेंगे तथा इसकी प्रति आयोग को भेजी जायेगी। यदि निवेदन सीधे आयोग को भेजा जाता है तो इसे समीक्षा पैनल के सचिव को अग्रेषित किया जायेगा जो संबंधित व्यक्तियों व अन्य व्यक्तियों, जिन्हें आयोग निर्देशित करे, के साथ परामर्श कर वितरण कोड प्रावधानों की समीक्षा करेगा। सचिव, प्रस्तावित परिवर्तनों/आशोधनों का एक उचित अवधि के भीतर अपनी लिखित टिप्पणी प्रस्तुत करने के लिये इसे समी पैनल सदस्यों के मध्य परिचालित करेगा या सचिव, अध्यक्ष के साथ परामर्श कर समीक्षा पैनल की बैठक बुलायेगा। इस परस्पर संवाद/चर्चा के आधार पर, आयोग के अनुमोदन के पश्चात् वितरण कोड में आवश्यक संशोधन/परिशोधन समादिष्ट किये जायेंगे।
- (2) पैनल की प्रत्येक समीक्षा बैठक पूर्ण हो जाने पर, सचिव, आयोग को निम्न रिपोर्ट्स भेजेगा :-
 - (क) ऐसी समीक्षा बैठक के परिणाम पर रिपोर्ट्स।
 - (ख) वितरण कोड में कोई प्रस्तावित परिशोधन तथा इसकी युक्तिसंगतता।
 - (ग) समीक्षा के समय उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सभी लिखित अभिवेदन व आपत्तियाँ।
- (3) वितरण कोड में सभी परिशोधनों हेतु आयोग का अनुमोदन आवश्यक है। आयोग के अनुमोदन के पश्चात्, सचिव, वितरण कोड के परिशोधनों को प्रकाशित करेगा। ऐसे मामलों में, जहां उपयोगकर्ताओं/वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को वितरण कोड की अपेक्षाओं को पूरा करने में कठिनाई है, समीक्षा पैनल शिथिलन प्रदान करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकेगा।
- (4) पिछले रूप में किसी प्रकार के परिवर्तन को हाशिये पर स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त परिशोधित रूप में अग्रभाग में एक परिशोधित शीट रखी जायेगी जिसमें प्रत्येक परिवर्तित उपखण्ड व उस परिवर्तन के कारण नोट किये जायेंगे।
- (5) सचिव, नवीनतम संशोधनों को सम्मिलित करते हुए वितरण कोड की प्रतियां रखेगा तथा किसी इच्छुक व्यक्ति को उचित मूल्य पर उपलब्ध करायेगा।
- (6) अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर अथवा अन्यथा, जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, आयोग, समीक्षा पैनल की आपात बैठक बुला सकता है तथा जैसे वह उचित समझे, वैसे परिवर्तन व संशोधन कर सकता है।

अध्याय 3-वितरण प्रणाली योजना

3.1 उद्देश्य :

वितरण प्रणाली योजना के मुख्य उद्देश्य हैं-

- (1) प्रवृत्त सांविधिक अधिनियमों व नियमों की पुष्टि करने वाले एक सुरक्षित, विश्वसनीय व भितव्ययी परिचालन के लिये वितरण प्रणाली की योजना, अभिकल्पना व निर्माण को समर्थ बनाना।
- (2) साझा विद्युत उभयनिष्ठता के कुशल परिचालन हेतु मानकों हेतु पूर्ण करने के लिये सम्बन्धित वितरण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीकी शर्तों को विनिर्दिष्ट करना।
- (3) अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता के स्तर पर वितरण प्रणाली के साथ-साथ चलने वाली योजना को सुगम बनाने हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ताओं के मध्य प्रणाली योजना डाटा के विनिमय के लिये प्रक्रिया निर्धारित करना।
- (4) योजना के दो मार्गदर्शक, व्यक्तिगत सबस्टेशनों, प्रणाली योजना, विश्लेषण व वितरण प्रणालियों के क्षेत्र में तकनीकी-आर्थिक पहलुओं को समावेशित करते हैं। यह वितरण प्रणाली, वितरण-अनुज्ञप्तिधारियों व राज्य पारेषण युटिलिटी (एसटीयू) जहां भी यह लागू हो, से पहले से जुड़े, जुड़ने को प्रतीक्षारत या जुड़ने के इच्छुक सभी उपभोक्ताओं पर लागू होता है।

3.2 वितरण प्रणाली योजना मानक :

- (1) वितरण प्रणाली योजना मानक, वितरण प्रणाली की योजना-कार्य प्रणाली हेतु मार्गदर्शकों को विनिर्दिष्ट करते हैं। इन मानकों की परिधि में समावेशित हैं—
 - (क) भार प्रक्षेपण;
 - (ख) सुरक्षा मानक;
 - (ग) योजना प्रक्रिया;
 - (घ) वितरण नेटवर्क का सेवा क्षेत्र;
 - (ङ) योजना मानक;
 - (च) विश्वसनीयता विश्लेषण;
 - (छ) वितरण प्रवर्तकों में डिजायन का मानकीकरण;
 - (ज) सबस्टेशन अभिन्यास का मानकीकरण;
 - (झ) रिएक्टिव प्रतिपूर्ति;
 - (ञ) सर्विस मेन्स;
 - (ट) मीटरिंग;
 - (ठ) ऊर्जा आपूर्ति की गुणवत्ता;
- (2) वितरण प्रणाली इस प्रकार योजनाबद्ध व विकसित की जायेगी कि प्रणाली, उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों की एक सुरक्षित, विश्वसनीय, मितव्ययी व गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति की अपेक्षाओं को पूर्ण करने योग्य हो सके। साथ ही, उपभोक्ता, विद्युत की गुणवत्ता पूर्ण आपूर्ति के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी को समर्थ बनाने के लिये उसे पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। वितरण प्रणाली, सभी सुसंगत मोड, मानकों व प्रवृत्त अधिनियमों की सांविधिक-अपेक्षाओं की पुष्टि करेंगे।

3.3 भार डाटा :

- (1) पारेषण प्रणाली के साथ प्रत्येक समयनिष्ठ बिन्दु पर संग्रहित मोटर्ड डाटा से, अनुज्ञप्तिधारी, एक समुचित विविधता साधन लागू कर, पोषित क्षेत्र के लिये लोड कर्व व साथ ही आपूर्ति क्षेत्र के लिये सिस्टम लोड कर्व विकसित करेगा।
- (2) 1 एम0वी0ए0 व उससे अधिक की मांग वाले उपयोगकर्ता अपने लोड डाटा/वैशिष्ट्य व अन्य सुसंगत विवरण, परिशिष्ट-1 में वर्णित रूप में वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत करेंगे। वितरण अनुज्ञप्तिधारी, एक एकल बिन्दु पर 1 एम0वी0ए0 व उससे अधिक भार का उपयोग वाहने वाले उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में भार के वास्तविक विकास के अनुवीक्षण हेतु विशेष सावधानी बरतेगा।
- (3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अपनी ओर से, अपनी वितरण प्रणाली में संरक्षण व सिस्टम डाटा के उद्देश्य हेतु विद्युत-उपकरण की अभिकल्पना व चयन, मीटरिंग व रिले के विवरण के लिये सुसंगत डाटा अनुरक्षित रखेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी नियमित रूप से व वर्ष में न्यूनतम एक बार सिस्टम डाटा को अद्यतन करेगा।

3.4 भार पूर्वानुमान :

- (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने आपूर्ति क्षेत्र में पांच वर्ष की अवधि के लिये एक प्रवाही लघु अवधि मांग पूर्वानुमान बनायेगा (एस0टी0यू0 को राज्य के भीतर के लिये 5 वर्षीय अग्रवर्ती वार्षिक योजना के तदनुरूप वार्षिक योजना प्रक्रिया आहरण करने में समर्थ बनाने के लिये)।
- (2) उपयुक्त कार्यविधि अपना कर, जैसे कि पिछले पांच वर्षों के रुझानों को ध्यान में रखकर तथा अगले पांच वर्षों में अपने आपूर्ति क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों के अपेक्षित आर्थिक व सामाजिक विकास को ध्यान में रख कर-पिछले पांच वित्तीय वर्षों को आधार मान कर व अगले पांच वर्षों की मांग प्रक्षेपित कर, प्रत्येक शुल्क श्रेणी में पूर्वानुमान अवधि में ऊर्जा का विक्रय प्रक्षेपित किया जायेगा।

- (3) इस प्रक्रिया के दौरान वह पिछले भार पूर्वानुमान के अनुसार वास्तव में हुए भार की स्थिति की भी समीक्षा करेगा। इसके अतिरिक्त ये पूर्वानुमान, सी0ई0ए0 द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किये जाने वाली योजना के अनुरूप होंगे। वितरण अनुज्ञप्तिधारी, जब कभी अपेक्षित हो, पूर्वानुमान में परिवर्तनों को सम्मिलित करेगा।
- (4) प्रत्येक उभयनिष्ठ बिन्दु पर पीक भार आवश्यकताओं का प्राक्कलन किया जायेगा। यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी एक संहत क्षेत्र में अनेकों ऐसे उभयनिष्ठ बिन्दुओं पर ऊर्जा प्राप्त करता है जो कि एक चक्र में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी, एस0टी0यू0 के साथ आपस में हुई चर्चा व सहमति के अनुसार परिवर्तन या सहनशीलता के साथ प्रत्येक उभयनिष्ठ बिन्दु पर पूर्ण लघु अवधि मांग पूर्वानुमान अग्रेषित करेगा।
- (5) पीक भार आवश्यकताओं हेतु प्रत्येक उभयनिष्ठ बिन्दु के लिये-लघु अवधि मांग पूर्वानुमान के अतिरिक्त, विपणन अनुज्ञप्तिधारी एस0टी0यू0, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व आयोग को वार्षिक आधार पर आपूर्ति क्षेत्र हेतु निम्नलिखित विवरण के साथ कुल योग ऊर्जा व पीक भार मांग भी अग्रेषित करेगा, जिस के आधार पर पूर्वानुमान किया गया है-डाटा, कार्य विधि व धारणायें।
- (6) प्रत्येक उभयनिष्ठ बिन्दु पर पीक भार आवश्यकताएं आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित करेंगी कि एस0टी0यू0, उभयनिष्ठ बिन्दु तक पारेषण प्रणाली में अथवा पर्याप्तता बनाये रखने के लिये सुधारक उपाय निर्धारित करेगा। इससे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अनुकूल पारेषण प्रणाली विकसित करने में आसानी होगी।
- (7) अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक उपभोक्ता वर्ग व प्रत्येक वितरण सबस्टेशन के लिये भार का एक डाटा बेस बनायेगा व वार्षिक रूप से इसे अद्यतन करेगा।

3.5 ऊर्जा प्रणाली अध्ययन व नेटवर्क विस्तार योजना :

- (1) दीर्घावधि समयमान पर वृहद् वितरण योजना प्रारम्भ करने से पहले वितरण अनुज्ञप्तिधारी, प्रक्षेपित भार पर आधारित ऊर्जा प्रणाली अध्ययन (भार प्रवाह विश्लेषण) प्रारम्भ करेगा।
- (2) अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित के लिये वितरण नेटवर्क विश्लेषण हेतु सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगा :-
 - (क) अधिकतम वितरण प्रवर्तक अवस्थितियां।
 - (ख) उप पारेषण प्रणाली, प्राथमिक वितरण, एल0टी0 फीडर्स व उप-स्टेशन अवस्थिति का अधिकतम नेटवर्क।
 - (ग) एच0टी0 व एल0टी0 वितरण लाईनों की लम्बाई का अधिकतम अनुपात।
 - (घ) अधिकतम पुनः सक्रिय प्रतिपूर्ति।

3.6 सुरक्षा मानक :

वितरण प्रणाली को इस प्रकार नियोजित व अनुरक्षित किया जायेगा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उचित नियंत्रण से बाहर की अपरिहार्य घटनाओं को छोड़कर निम्नलिखित सुरक्षा मानक पूरे किये जा सकें :-

- (1) अस्पतालों, शवदाहगृहों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों इत्यादि महत्वपूर्ण भार को पोषित करने वाले फीडर्स चाहे एच0टी0 हों या एल0टी0 को इस प्रकार नियोजित किया जायेगा कि उनकी एक चयनित स्विचिंग प्रणाली हो ताकि वैकल्पिक समर्थ फीडर पर भार स्थानांतरित करने के लिये चयनित स्विचिंग परिचालित की जा सके। इस सम्बन्ध में समुचित सुरक्षा उपाय निरपवाद रूप से दिये जायेंगे। फीडर के काम न करने की स्थिति में भार की महत्ता अनुसार इन स्विचों को हाथ से या स्वचालित रूप से तुरन्त चलाया जायेगा।
- (2) प्रणाली में लगे स्विचगियर की फटने की क्षमता, प्रणाली के प्रत्याशित भविष्य विकास को ध्यान में रखते हुए गणना करने पर भी शॉर्ट सर्किट स्तर से कम-से-कम 25% से अधिक होगी।
- (3) प्रत्येक एच0टी0 फीडर के लिये चाहे वह प्राथमिक हो या द्वितीय, यह प्रयास किया जायेगा कि वह उस इलाके में उपलब्ध उसी वोल्टेज श्रेणी में उपलब्ध एच0टी0 फीडर पर तुरन्त हस्तचालित रूप से परिवर्तित किया जाये। सभी संवेदनशील एच0टी0 फीडर्स के डिजायन में ही, आपात स्थिति में साथ के फीडर में 50% भार बांट देने का प्रावधान किया जायेगा। इसे क्रमशः सभी एच0टी0 फीडर्स तक विस्तारित किया जायेगा।

- (4) एकल आकस्मिकता के मामले में किसी निर्गामी 11 के0वी0 या 33 के0वी0 फीडर को नियंत्रित करने वाले सबस्टेशन उपस्कर के विफल हो जाने पर, अवरोधित भार सामान्यतः सबस्टेशन पर कुल मांग के 50% से अधिक नहीं होगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, तीन वर्ष की अवधि के भीतर इसे 20% पर लाना होगा। यह सुदूर अगम्य बर्फ से घिरे क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा।

3.7 प्रणाली पर्याप्तता व प्रचुरता :

- (1) वितरण प्रणाली की योजना बनाते समय वितरण अनुज्ञप्तिधारी, लाईनों व प्रवर्तकों में जबरन या नियोजित आउटेज की स्थिति में स्वरूप योजना व उपभोक्ताओं को आपूर्ति बनाये रखने पर आधारित दीर्घावधि भार वृद्धि हेतु प्रणाली क्षमता व योग्यता की प्रचुरता व पर्याप्तता का ध्यान रखेगा। प्रणाली में प्रचुरता आवश्यक रूप से होगी ताकि वैकल्पिक सर्किट व्यवस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति में किसी अवरोध का सामना न करना पड़े।
- (2) सबस्टेशन डिजायन, अधिकतम मांग समय में भी किसी क्षेत्र की आपूर्ति पर प्रभाव डाले बिना, प्रवर्तक को अनुरक्षण हेतु ले जाये जाने की अनुमति देगा। एन-1 योजना मानदण्ड पूरा करने के लिये, विशाल क्षमता के एक प्रवर्तक की अपेक्षा लघु क्षमता में एक से अधिक प्रवर्तक लगाये जाने चाहियें। महत्वपूर्ण भारों के लिये वैकल्पिक भी नियोजित किये जायेंगे। जहां तक सम्भव हो, आपात स्थिति से निपटने के लिये, प्रचुरता प्रणाली में ही होनी चाहिये तथा प्रणाली पर्याप्तता का ध्यान सबस्टेशन(नों) की योजना प्रणाली के समय रखा जाना चाहिये।

3.8 ऊर्जा लेखा परीक्षा :

- (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, ऊर्जा लेखा परीक्षा के माध्यम से तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों को पृथक-पृथक करने के लिये प्रणाली स्थापित करेगा व चलायेगा। 65 दिन का डाटा संरक्षित रखने की क्षमता वाले उभयनिष्ठ मीटर, प्रत्येक ऐसी यूनिट के लिये आवक निर्गामी फीडर्स हेतु लगाये जायेंगे।
- (2) सम्पूर्ण प्रणाली हेतु ऊर्जा लेखा परीक्षा डाटा संकलित कर दी जायेगी तथा विश्लेषण प्रत्येक उत्तरदायी केन्द्र में किया जायेगा। प्रत्येक उपस्टेशन से प्राप्त ऊर्जा, उपयुक्त ऊर्जा मीटरों के साथ लगाये गये सभी निर्गामी फीडर्स के 11 के0वी0/33 के0वी0 टर्मिनल स्विचगियर पर नापी जायेगी जिससे कि प्रत्येक फीडर को आपूर्ति की गई ऊर्जा सही रूप से उपलब्ध हो। इसकी तुलना मासिक ऊर्जा-विक्रय के तदनुरूप आंकड़ों से की जायेगी तथा प्रत्येक फीडर के लिये वितरण हानि ज्ञात की जायेगी। यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने 11 के0वी0 व 33 के0वी0 पर रिंग मेन प्रणाली अपनाई है तथा प्रत्येक फीडर के लिये वितरण हानि निर्धारित करने में कठिनाई है, तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आपूर्ति के सम्पूर्ण क्षेत्र हेतु वितरण हानि ज्ञात करेगा।
- (3) पर्याप्त निदेश व शासन में समुचित सुधार के साथ हानि में कमी लाने के लिये एक कार्य योजना बनाई जानी चाहिये तथा इसे वार्षिक राजस्व अपेक्षाओं की फाइलिंग के साथ वार्षिक रूप से आयोग के पास जमा किया जाना चाहिये।

3.9 डाटा बेस प्रबन्धन :

- (1) दीर्घावधि आधार पर वितरण प्रणाली के नियोजन एवं विकास हेतु सही व विश्वसनीय डाटा की उपलब्धता आवश्यक है। डाटा प्रबंधन प्रणाली से वितरण की अपेक्षाओं को पूरा करने व अन्य उद्देश्यों जैसे कि ऊर्जा प्रणाली अध्ययन के लिये डाटा में सम्मालने, पुनः प्राप्त करने, अद्यतन करने में सुविधा होती है।
- (2) वितरण प्रणाली से जुड़े अन्तःस्थापित उत्पादक या नवीन संयोजन के इच्छुक, परिशिष्ट-2 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में नियोजन डाटा प्रस्तुत करेंगे। बड़े उपभोक्ताओं जो एच0टी0 या ई0एच0टी0 से जुड़े हैं या नया संयोजन चाह रहे हैं तथा उनके पास 1 एम0वी0ए0 या इससे अधिक का संयोजित भार है, वे वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दीर्घावधि नियोजन हेतु परिशिष्ट-1 में दिये अनुसार, निर्धारित में नियोजन डाटा प्रस्तुत करेंगे। परिशिष्ट-3 पर प्रारूप के अनुसार, उनसे नियोजन उद्देश्य हेतु जहां कहीं अपेक्षित हो, उपयोगकर्ताओं, अन्तः स्थापित उत्पादकों व बड़े उपभोक्ताओं को वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सिस्टम डाटा की आपूर्ति करेगा।
- (3) एक सही व विश्वसनीय तरीके से दीर्घावधि योजना व वितरण कार्य हेतु अपेक्षित, उपयोगकर्ताओं व वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य डाटा विनिमय को एक उचित रूप से अनुरक्षित डाटा प्रबंधन प्रणाली सुविधाजनक बनायेगी। यह उपयोगकर्ताओं, बड़े उपभोक्ताओं, खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं व अन्तःस्थापित उत्पादकों को डाटा प्राप्त करने में भी सहायता करेगा जिसकी उन्हें अपनी योजना के उद्देश्य से आवश्यकता पड़ेगी।

3.10 अभिकल्पना, निर्माण व अनुरक्षण पद्धतियों हेतु स्थायी समिति :

- (1) इन विनियमों की अधिसूचना के एक माह के भीतर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को समावेशित कर एक स्थायी समिति का गठन किया जायेगा :-
 - (क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी का तकनीकी सदस्य-स्थायी समिति का अध्यक्ष।
 - (ख) महाप्रबन्धक (अभियांत्रिकी/नियोजन) वितरण अनुज्ञप्तिधारी-सदस्य।
 - (ग) महाप्रबन्धक (संविदा/प्रापण) वितरण अनुज्ञप्तिधारी-सदस्य।
 - (घ) महाप्रबन्धक (अभिकल्पना/नियोजन) एस0टी0यू0-सदस्य।
 - (ङ) औद्योगिक उपभोक्ताओं में से एक प्रतिनिधि-सदस्य।
 - (च) घरेलू/व्यावसायिक उपभोक्ताओं में से एक प्रतिनिधि-सदस्य।
 - (छ) कोई अन्य व्यक्ति जिसे अनुज्ञप्तिधारी उपयुक्त समझे-सदस्य।
- (2) स्थायी समिति एक सलाहकार समिति होगी जिसका कार्यकाल सतत होगा। यह प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार बैठक करेगी। स्थायी समिति, अन्य मामलों के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्रों पर अपने सुझाव व संस्तुतियां देगी :-
 - (क) लाईन सामग्री, मीटर्स, मीटर उपकरण, सेवा लाईन सामग्री, सबस्टेशन उपस्कर जैसे प्रवर्तक, सर्किट ब्रेकर्स, सी0टी0/पी0टी0 सेट्स इत्यादि की अभिकल्पना व तकनीकी विशिष्टताओं पर नवीनतम पद्धतियों की समीक्षा करना व सुझाव देना।
 - (ख) थोक में उपयोग में लाये जा रहे विभिन्न उपकरणों व सामग्रियों के लिये विक्रेता चयन व लघुसूचिदन प्रक्रिया पर सुझाव देना।
 - (ग) 33 के0वी0, 11 के0वी0 व एल0टी0 लाईन्स, 33/11 के0वी0 सबस्टेशनों, 11 के0वी0 पोल माउन्टेड व अन्य ग्राउन्ड माउन्टेड सबस्टेशनों इत्यादि के निर्माण, परिचालन, अनुरक्षण हेतु सर्वोत्तम उद्योग पद्धति का सुझाव देना।
 - (घ) नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रगति व प्रक्रिया जैसे आई0टी0 टूल्स व एस0सी0ए0डी0ए0 व अन्य नियंत्रण प्रणाली की संस्तुति व सुझाव देना।
 - (ङ) सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, व प्रदूषण मानकों की दृष्टि से खतरनाक, अस्वास्थ्यकारी पद्धतियों व सामग्री पर रोक व प्रतिबंध की संस्तुति करना।

3.11 नामावली व पहचान कूट संकेतन का मानकीकरण :

वितरण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण प्रणाली में विभिन्न उपस्करों को एकमात्र रूप से पहचानने के लिये उपस्कर नामावली व पहचान उपकरण तैयार करेगा। नामावली योजना, राज्य के भीतर पारेषण प्रणाली हेतु यूईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2007 में उपबंधित योजना से संगत होगी।

3.12 रिएक्टिव प्रतिपूर्ति :

- (1) ग्रिड को रिएक्टिव ऊर्जा निकासी को न्यूनतम करने, वोल्टेज की संतोषप्रद स्थिति बनाये रखने व उप-पारेषण व वितरण हानियों में कमी के लिये वितरण प्रणाली में उपयुक्त स्थानों पर स्विच्छ व अनस्विच्छ शंट कैपेसिटर्स लगाये जायेंगे। कैपेसिटर्स के संस्थापन का आकार व अवस्थिति, विश्वसनीय स्थल डाटा के साथ उपयुक्त कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग कर निर्धारित की जायेगी। कम भार की समयावधि के दौरान अधिक वोल्टेज को रोकने के लिये उपयुक्त पूर्वोपाय, जैसे कि स्वतः चालित स्विचिंग इत्यादि अपनाये जायेंगे।
- (2) शंट कैपेसिटर लगाने के लिये सर्वाधिक उपयुक्त आकारों व अवस्थितियों के निर्धारण के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शंट प्रतिपूर्ति का अनुकूलन अध्ययन संचालित किया जायेगा।

3.13 मीटरिंग :

- (1) सभी उभयनिष्ठ मीटर, उपभोक्ता मीटर व ऊर्जा लेखाकरण एवं लेखा परीक्षा मीटर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की संस्थापना व परिचालन) विनियम, 2006 से समानुरूपता में संस्थापित व परिचालित किये जायेंगे।

- (2) 230 वोल्ट एकल फेज आपूर्ति के लिये मीटरिंग एक बोर्ड पर या एक उपयुक्त बक्से में प्रदान की जायेगी जो ऐसे स्थान पर अवस्थित हो जहाँ वह धूप व वर्षा से सुरक्षित रह सके तथा रीडिंग लेने की दृष्टि से सुविधाजनक स्थिति में हो। मीटर में टर्मिनल्स, टैम्पर प्रूफ व सील्ड होने चाहिये। 400 वोल्ट्स के लिये तीन फेज आपूर्ति, मीटर्स व कड़ियों के साथ मीटरिंग उपस्कर एक उपयुक्त टैम्पर प्रूफ बक्से में बंद किया जायेगा। टैम्पर प्रूफ बक्सा मजबूत डिजायन का होगा जिसमें ताला लगाने व सील करने का साधन उपलब्ध हो। इसमें अपेक्षित विद्युत निकासियों के साथ गर्मी के अपव्यय हेतु पर्याप्त प्रावधान होगा। कड़ियों को छेड़े बिना रीडिंग ली जा सके इसका ऐसा डिजायन होगा।
- (3) एच0टी0 उपभोक्ताओं के लिये अधिकतम मांग संकेतक एक अलग मीटरिंग कक्ष में रहेंगे तथा गौण उपकरण जैसे कि अपेक्षित औजार प्रवर्तक व कड़ियाँ दूसरे कक्ष में रखे जायेंगे। जो छेड़छाड़ से बचाने के लिये ताला/सील लगा कर रखे जायेंगे।
- (4) एच0टी0 मीटरिंग घनाकृति दोनों ओर से या कम-से-कम एक ओर से केबल में प्रवेश के लिये उपयुक्त होगी। औजार प्रवर्तकों के सहायक सर्किट्स में कोई फ्यूज अनुमोदित नहीं हैं। हिमाच्छादित व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में संस्थापना हेतु मीटरिंग घनाकृति को उपयुक्त रेजीन वाले रंग से रंगा जायेगा। औजार प्रवर्तक स्थिर अनुपात में होंगे तथा इनमें कोई टॉटी नहीं होगी। करेन्ट प्रवर्तकों की प्राथमिक करेन्ट रेटिंग सामान्य पूर्ण भार के साथ मेल खायेगी तथा कोर का संतृप्ति बिंदु, सभी संयोजित उपकरणों व यंत्रों के एक साथ पूर्ण भार परिचालन के कारण होने वाले अधिकतम करेन्ट से ऊँचा होगा।
- (5) एच0टी0 व ई0एच0टी0 उपभोक्ताओं के लिये औजार प्रवर्तकों के सहायक टर्मिनल्स ताले में व सील लगा कर रखे जायेंगे तथा सहायक वायर्स मीटरिंग पैनल तक एक उपयुक्त जीआई वाहक नली में लाये जायेंगे। इस वाहक नली में कोई जोड़ नहीं होंगे। मीटर्स, औजार प्रवर्तक के समीपस्थ स्थित होगा तथा किसी भी स्थिति में इसे दस (10) मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित नहीं होना चाहिये। मीटरिंग पैनल को एक मौसमसह व टैम्पर प्रूफ बक्से में रखा जायेगा तथा सीलबंद किया जायेगा।

अध्याय 4-संयोजकता की शर्तें

4.1 उद्देश्य :

- (1) संयोजकता शर्तें उस न्यूनतम तकनीकी व डिजायन मानदण्ड को विनिर्दिष्ट करती हैं व जिसका वितरण प्रणाली से जुड़े या जुड़ने के इच्छुक अभिकरण द्वारा अनुपालन करना है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि एक सहमत संयोजन की स्थापना हेतु पूर्वापेक्ष के रूप में किसी भी अभिकरण द्वारा इसका अनुपालन किया जाये। संयोजकता शर्तों को अधिनियम की धारा 50 व 53 में अनुबंधित अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिये।
- (2) संयोजकता शर्तें यह सुनिश्चित करने के लिये उपबंधित की गई हैं कि—
 - (क) प्राथमिक नियमों का अनुपालन सभी अभिकरणों द्वारा किया जाये। इससे सभी अभिकरणों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करने में सहायता मिलेगी।
 - (ख) कोई नया या परिशोधित संयोजन, जब स्थापित हो जाये तो उसे वितरण प्रणाली में इसके संयोजन के कारण अस्वीकार्य प्रभाव के कारण परेशान नहीं होना पड़ेगा, न ही इस प्रणाली पर या किसी अन्य सम्बन्धित अभिकरण पर अस्वीकार्य प्रभाव प्रस्तुत करने पड़ेंगे।
 - (ग) सभी उपयोगकर्ताओं पर एच0टी0/ई0एच0टी0 उभयनिष्ठ/संयोजन के मामले में सभी उपस्करों हेतु स्वामित्व व उत्तरदायित्व, परिशिष्ट-4 में विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार प्रत्येक उस स्थल हेतु जहाँ संयोजन किया गया है, स्थल-उत्तरदायित्व अनुसूची में स्पष्ट रूप में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

4.2 उभयनिष्ठ बिंदु :

- (1) पारेषण प्रणाली से संयोजन यू0ई0आर0सी0 (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2007 द्वारा शासित होंगे।
- (2) बस बार पर वितरण प्रणाली के, छोटे उत्पादक (1एम0वी0ए0 से छोटे नहीं) संयोजन, उत्पादक स्टेशन पर प्रदान किये जायेंगे। सभी उत्पादक यूनिट, उत्पादन को एककालिक अवरोधक के माध्यम से अन्तःक्षेपित करेंगी। एककालिक अवरोधक व बस बार के मध्य निःसंगक, उत्पादन व वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य भी सीमा होगी।

शुल्क मीटरिंग के प्रवाह प्रवर्तक एककालिक अवरोधक के समीप संयोजित होंगे। शुल्क मीटरिंग के वोल्टेज प्रवर्तक (प्रतीक्षारत सेट सहित) बस बार से संयोजित किये जायेंगे। किन्तु ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोत पर आधारित लघु-उत्पादकों को छूट दी जायेगी तथा इन्हें वितरण प्रणाली/पारेषण प्रणाली, जो साथ हो, से संयोजन हेतु अनुमति होगी।

- (3) ई0एच0टी0/एच0टी0 उपभोक्ता : आपूर्ति वोल्टेज 220 के0वी0/32 के0वी0/66 के0वी0/33 के0वी0/11 के0वी0 या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सहमत वोल्टेज होगी। उपयोगकर्ताओं के स्वामित्व वाले उपस्टेशनों के सम्बन्ध में, सीमा, वितरण अनुज्ञप्तिधारी कट ऑफ बिन्दु/निःसंगक होगा। जब कोई ई0एच0टी0/एच0टी0 उपभोक्ता समर्पित फीडर से पोषित हो तो सीमा बिंदु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के सबस्टेशन पर लाईन निःसंगक होगा।
- (4) निम्न वोल्टेज उपभोक्ता : उपभोक्ता द्वारा लगाये गये कट आउट/सर्किट ब्रेकर के अवाक टर्मिनल, निम्न वोल्टेज उपभोक्ताओं की सीमा है। शुल्क मीटरिंग, उपभोक्ता की फ्यूज यूनिट/सर्किट ब्रेकर के पहले उपलब्ध कराई जायेगी। मीटरिंग उपस्कर, एक सुरक्षित अवस्थिति में उपभोक्ता के परिक्षेत्र में प्रवेश बिंदु पर उपलब्ध कराया जायेगा जो कि प्राथमिक रूप से, मीटर रीडिंग, रखरखाव, मरम्मत, निरीक्षण, इत्यादि के उद्देश्य हेतु आसान पहुंच के लिये, परिक्षेत्र की सीमा के प्रवेश पर, या एक साझा गलियारे पर, या भूतल पर या परिक्षेत्र के बाहर समीप के सुरक्षित अवस्थिति पर होगा। मीटरिंग उपस्कर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सील किया जायेगा तथा उपयोगकर्ता/उपभोक्ता, मीटरिंग उपस्कर को नहीं छेड़ेंगे व मीटर एवं उपस्कर के संरक्षण हेतु उपयुक्त सावधानी बरतेंगे।

4.3 परिचालक लेबलिंग :

- (1) अनुज्ञप्तिधारी एवं सभी उपयोगकर्ता, सबस्टेशनों व संयोजन स्थलों पर संख्याओं व/या उपस्कर/उपकरण के नाम व सर्किट को इंगित करते हुए स्पष्ट चिन्ह व लेबल्स में प्रावधान व उनके रखरखाव हेतु उत्तरदायी होंगे।
- (2) लगाये गये उपस्कर इसकी सुसंगत आई0एस0 विशिष्टताओं व रेटिंग की पुष्टि करेंगे तथा इसकी प्रमुख विशिष्टताओं को उपस्कर की नाम पट्टिका पर लिख कर रखा जायेगा। स्थायी रूप से निर्माता की नाम पट्टिका बिना लगे किसी भी विद्युत उपस्कर का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4.4 प्रणाली प्रदर्शन :

- (1) वितरण प्रणाली से जुड़े सभी उपस्करों की अभिकल्पना व निर्माण, उच्चतम सम्भव स्तर तक, सुसंगत भारतीय मानक विशिष्टताओं को पूरा करेगा।
- (2) सभी विद्युत उपस्करों का संस्थापन, प्रवृत्त नियमों व कोड का अनुपालन करेगा।
- (3) मांगे गये प्रत्येक नये संयोजन हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी, कोड में विनिर्दिष्ट किये अनुसार मीटरिंग व संरक्षण अपेक्षाओं के साथ संयोजन बिंदु/उभयनिष्ठ बिंदु व आपूर्ति वोल्टेज विनिर्दिष्ट करेगा।
- (4) वितरण प्रणाली का परिचालन "वितरण प्रणाली परिचालन मानक" के अनुरूप होगा तथापि उपयोगकर्ता, एस0एल0डी0सी0/उप एल0डी0सी0 द्वारा निर्धारित वितरण अनुशासन के अधीन होगा।
- (5) उपयोगकर्ता के उपस्कर का विद्युत रोधन समन्वय, लागू भारतीय मानकों/पद्धति कोड की पुष्टि करेगा।

4.5 प्रणाली से संयोजन हेतु आवेदन की प्रक्रिया :

वितरण प्रणाली का उपयोग चाहने वाले किसी उपयोगकर्ता को यू0ई0आर0सी0 (नवीन एल0टी0 संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2007 में नियत प्रक्रिया व प्रारूप के अनुसार, संयोजन हेतु आवेदन जमा करना होगा।

4.6 नियोजन अनुबंध :

उपयोगकर्ता व वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य संयोजन अनुबंध क्रय व विक्रय दोनों के लिये निष्पादित किया जायेगा जिसमें स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आई0पी0पी0) सम्मिलित होगा। उत्पादन हेतु भिन्न सहमति निर्धारित की जायेगी।

अध्याय 5-परिचालन कोड

5.1 परिचय :

इस अध्याय में अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ताओं द्वारा वितरण प्रणाली में सुरक्षित व कुशल परिचालन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं व पद्धतियों का समावेश है। इस खण्ड में परिचालन में निम्नलिखित पहलुओं को समावेशित किया गया है :-

- (1) मांग परिमाण;
- (2) आउटटेज नियोजन;
- (3) आकस्मिकता नियोजन ;
- (4) मांग पक्ष प्रबंधन व भार कटौती;
- (5) सी0पी0पी0एस0 सहित लघु उत्पादक संयंत्र के साथ उभयनिष्ठता (इन्टरफेस);
- (6) वोल्टेज व पावर फैक्टर का अनुश्रवण व नियंत्रण;
- (7) सुरक्षा समन्वय;
- (8) संसूचना;
- (9) अनुरक्षण एवं परीक्षण;
- (10) औजार व पुर्जे;
- (11) प्रशिक्षण।

5.2 मांग अनुमान :

- (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता से प्राप्त किसी आकस्मिकता के कारण उत्पन्न संसूचना के अनुसार परिशोधन की शर्त पर, अगले दिन के लिये निकाले गये सुसंगत भार (कर्व्स) के आधार पर अपने आपूर्ति क्षेत्र हेतु प्रति घंटा व दैनिक अनुमान लगायेगा। इसे अपेक्षानुसार एस0एल0डी0सी0 को दिया जायेगा।
- (2) इस उद्देश्य के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मान्य, सम्बन्धित मुख्य उपयोगकर्ता उसको अपने अधिष्ठान की अपनी मांगों से सम्बन्धित अपेक्षित डाटा प्रस्तुत करेंगे।

5.3 आउटटेज नियोजन :

- (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपना प्रस्तावित आउटटेज कार्यक्रम आगे आने वाले माह के आधार पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत करेगा। इस आउटटेज कार्यक्रम में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित वितरण प्रणाली को लाईन व उपस्कर की पहचान का समावेश होगा।
- (2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित आउटटेज योजना, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्तिम रूप से सहमत पारेषण आउटटेज योजना जारी किये जाने के पश्चात् ही प्रवृत्त होगी।
- (3) किन्तु लाईन या उपस्कर को सेवा से हटाये जाने के समय, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को, यदि संभव हो तो, अपने अनुरक्षण कार्य के साथ सामंजस्य की सुविधा हेतु सूचित करेगा भले ही यह स्वीकृत योजना में पहले से ही सम्मिलित है।
- (4) 66 के0वी0 व उससे अधिक के उपस्कर व लाईनों के मामले में, उपरोक्त के अतिरिक्त, एस0एल0डी0सी0 की विशेष सहमति प्राप्त करनी होगी।
- (5) निम्नलिखित परिस्थितियों में उपरोक्त प्रक्रिया लागू नहीं होगी :-
 - (क) संयंत्र व यंत्रों को बचाने के लिये आसान स्थिति।
 - (ख) ऐसी अप्रत्याशित आपात स्थितियों में, मानव जीवन की रक्षा के लिये लाईनों व उपस्कर को हटाने की आवश्यकता पर।
 - (ग) जहाँ अनुबन्ध मंग होने के कारण किसी उपयोगकर्ता के अधिष्ठान पर, विच्छेदन पर प्रभाव पड़ता हो। ऐसे मामले में, जहाँ 1 एम0वी0ए0 या इससे अधिक का भार प्रभावित होता हो वहाँ एस0एल0डी0सी0 को सूचना दी जायेगी।

- (6) अनुरक्षण में उद्देश्यों से अनुज्ञप्तिधारी हेतु यू0ई0आर0सी0—(प्रदर्शन के मानक) विनियम, 2007 में विनिर्दिष्ट की अवधि के लिये ऊर्जा प्रणाली की नियोजित आउटलेज मीडिया के माध्यम से जनता को सूचित की जायेगी जिसमें दो दिन पहले उस क्षेत्र के, उत्तराखण्ड में बड़े प्रसार वाले दो समाचार पत्र (एक हिन्दी व एक अंग्रेजी) में सूचना देना सम्मिलित है।

5.4 आकस्मिकता योजना व संकट प्रबंधन :

- (1) पारेषण प्रणाली में पूर्ण या आंशिक अंधियारे की स्थिति में एक आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्वयं वितरण प्रणाली में स्थानीय अवरोध के कारण भी वितरण प्रणाली के एक भाग में आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अन्तः संयोजन बिंदु पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण में अवरोध के कारण भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- (2) आकस्मिकता व संकट प्रबंधन प्रक्रिया स्पष्ट रूप से प्रलेखित की जायेगी ताकि सम्पूर्ण प्रणाली व सम्मिलित मांग को तुरन्त पुनः स्थापित किया जा सके तथा कम से कम सम्भव समय में सम्पूर्ण प्रणाली में उन भागों को पुनः एककालिक (रिसिन्क्रोनाइजेशन) किया जा सके जो एक दूसरे के साथ एककालिक नहीं रह गये हैं।
- (3) पारेषण प्रणाली विफलता :
 - (क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी में आपूर्ति क्षेत्र में किसी बिंदु पर पूर्ण अंधेरे की स्थिति में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संरचित ब्लैकस्टार्ट प्रक्रिया अपनायेगा।
 - (ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, मांग में भिन्न खण्डों में वितरण प्रणाली को खण्डवार करेगा। अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक मांग खण्ड स्विच ऑन करने पर उठने वाले सम्भावित भार की मात्रा हेतु एस0एल0डी0सी0 के साथ सलाह व सहयोग करेगा।
 - (ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, पुनः स्थापन प्रक्रिया के दौरान लिये जाने वाले प्रत्येक संयोजन पर प्राथमिकता के क्रम में जरूरी व गैर जरूरी भारों की एक अनुसूची तैयार करेगा।
 - (घ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी एस0एल0डी0सी0 के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित करेगा तथा एस0एल0डी0सी0 के निर्देश के अधीन भार उत्पादन सन्तुलन बनाये रखना सुनिश्चित करेगा।
 - (ङ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी एस0एल0डी0सी0 को, आकस्मिकता परिचालन से निपटने के लिये अधिकृत व्यक्ति(यों) के नाम व पदनाम, उनके दूरभाष नम्बर तथा स्टेशन के साथ प्रस्तुत करेगा।
- (4) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण की विफलता :
 - (क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के उपस्टेशन पर अधिकृत व्यक्ति से तुरन्त सम्पर्क करेगा तथा प्रभावित उपस्टेशन से भार निकासी के पुनः स्थापन की सम्भावित अवधि व सम्भावित रुकावट का आकलन करेगा।
 - (ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी तदनुसार मांग प्रबन्धन योजना जारी करेगा।
- (5) वितरण प्रणाली विफलता :
 - (क) वितरण प्रणाली के किसी भाग में रुकावट के कारण, यू0ई0आर0सी0 (मानकों का प्रदर्शन) विनियम, 2007 में अनुज्ञप्तिधारी के लिये विनिर्दिष्ट अवधि हेतु ऊर्जा आपूर्ति में अवरोध वितरण प्रणाली में अवरोध कहलायेगा।
 - (ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी पुनः स्थापन प्रक्रिया हेतु एस0एल0डी0सी0 के साथ सहयोग करेगा जो कि यू0ई0आर0सी0 (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2007 के अनुसार होगी।
 - (ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण प्रणाली पुनः स्थापन हेतु एस0एल0डी0सी0 के साथ सहयोग करने के लिये एक नोडल अधिकारी पद नामित करेगा।

5.5 मांग प्रबन्धन व भार कटौती :

- (1) एस0एल0डी0सी0 द्वारा दिये गये अनुदेशों के अनुसार ग्रिड आवृत्ति बनाये रखने के लिये अस्थायी भार कटौती का आश्रय लिया जायेगा। अस्थायी भार कटौती किसी सर्किट या उपस्कर की हानि या किसी अन्य परिचालन

आकस्मिकता के कारण भी आवश्यक हो सकती है। अण्डर फ्रीक्वेन्सी रिलेज के माध्यम से स्वचालित भार कटौती के मामले में सर्किट तथा तदनु रूप रिले सैटिंग्स के साथ अवरुद्ध होने वाले भार की मात्रा को एस0एल0डी0सी0 तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उपस्टेशन के प्रभारी व्यक्तियों के साथ आवश्यकतानुसार संयोजित किया जायेगा।

- (2) सतत रूप से कमी की स्थिति में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, प्रस्तावित भार कटौती के क्षेत्र व समयावधि इंगित करते हुए नियोजित भार कटौती हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी, अनुमोदित कार्यक्रम को कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा। अनुमोदित भार कटौती कार्यक्रम से विचलन हेतु, अनुज्ञप्तिधारी आयोग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- (3) वितरण प्रणाली के किसी भाग में यदि अनियोजित भार कटौती की अवधि दो घंटे से अधिक होती है तो प्राथमिक सबस्टेशन से प्रकट होने वाले, स्वतंत्र सर्किट्स पर प्रभावित उपभोक्ताओं को उपयुक्त रूप से सूचना दी जायेगी। आवश्यक सेवाओं जैसे कि सार्वजनिक बिक्रित्सालय, सार्वजनिक जल संस्थान, सीवेज, सीवेज कार्य इत्यादि को जहां कहीं सम्भव हो, दूरभाष द्वारा सूचित किया जायेगा।
- (4) कृषि उपभोक्ताओं को ऊर्जा की आपूर्ति हेतु डेडिकेटेड फीडर्स निर्मित किये जायेंगे ताकि ऐसे फीडर्स पर 8-10 घंटा आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- (5) जहां तक सम्भव हो, बड़े शहरों में 33 के0वी0 रिंगमेन्स उपलब्ध कराये जायेंगे।

5.6 केप्टिव ऊर्जा संयंत्र (सी0पी0पी0) सहित लघु उत्पादक यूनिट्स के साथ उभयनिष्ठता :

- (1) यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सी0पी0पी0 सहित किसी उत्पादक यूनिट के साथ उभयनिष्ठता है तथा इस उद्देश्य के लिये एक करार अस्तित्व में है तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादक यूनिट के सम्बन्धित स्वामी सभी उपयोगकर्ताओं पर लागू रूप में इस कोड में समाहित उपबन्धों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपबन्धों द्वारा बंधे होंगे :-
 - (क) स्वामी वितरण प्रणाली में सामान्य व असामान्य परिस्थितियों के कारण किसी हानि से अपनी प्रणाली के संरक्षण हेतु उभयनिष्ठ बिन्दु पर उपयुक्त संरक्षण प्रदान करेगा।
 - (ख) यदि जेनरेटर एक प्रवेशण जेनरेटर है तो स्वामी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ सहमति से, जब प्रवेशण जेनरेटर एककालिक हो तो प्रणाली में व्यवधान को सीमित करने के लिये वह पर्याप्त सावधानी बरतेगा। जिन कम्पनियों के पास प्रवेशण जेनरेटर हैं, वे पुनः सक्रिय ऊर्जा निकासी हेतु पर्याप्त केपेसिटर लगायेंगी। साथ ही जब कमी प्रारम्भिक अवस्था में पवर फैक्टर अत्यधिक निम्न पाया जाये तथा अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में वोल्टेज गिरने लगे तो अनुज्ञप्तिधारी स्वामी को केपेसिटर लगाने की सलाह दे सकता है तथा उत्पादक कम्पनी को इसका अनुपालन करना होगा। अनुपालन में विफल रहने पर नियमों तथा अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार जुर्माना व/या प्रणाली से विच्छेदन होगा।
 - (2) स्वामी यू0ई0आर0सी0 (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2007 के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।
- 5.7 वोल्टेज व पावर फैक्टर का अनुरक्षण व नियंत्रण :
- (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी व्यस्त समय व अव्यस्त समय पर प्रणाली आवक बिन्दुओं पर वितरण प्रणाली में वोल्टेज तथा पवर फैक्टर का अनुवीक्षण करेगा तथा 1 एम0वी0ए0 तथा उससे ऊपर की मांग वाले उपयोगकर्ताओं तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ सामंजस्य कर इसके सुधार हेतु उचित उपाय करेगा।
 - (2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली अध्ययन कर तथा अपेक्षित पुनः सक्रिय प्रतिपूर्ति उपस्कर संस्थापित कर वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर पवर फैक्टर सुधार उपाय करेगा।
 - (3) जिन उपयोगकर्ताओं के पास निम्न पवर फैक्टर का भार है, वे परिशिष्ट पाँच के अनुसार उपयुक्त रेटिंग के केपेसिटर लगायेंगे। वैल्टिंग के उद्देश्य से ऊर्जा का उपयोग करने वाले उपभोक्ता बार-बार होने वाले वोल्टेज से उतार चढ़ाव को दूर करने के लिये, समय-समय पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर आपूर्ति की आवृत्ति बनाये रखने के लिये भार प्रबंधन पर समय समय पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी

अनुदेशों के अधीन होगा।

- (4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर आपूर्ति की आवृत्ति बनाये रखने के लिए भार प्रबन्धन पर समय-समय पर एस.एल.डी.सी. द्वारा जारी अनुदेशों से बंधा रहेगा।

5.8 सुरक्षा समन्वय :

- (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता (उत्पादक कम्पनियाँ, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा 1 एम0वी0ए0 या इससे अधिक डेडिकेटेड लाईन्स वाले उपभोक्ता) तथा कोई अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी जिसका अनुज्ञप्तिधारी के साथ साझा विद्युत उभयनिष्ठ हो, सुरक्षित समन्वय हेतु उत्तरदायी उपयुक्त व्यक्तियों को पदनामित करेंगे। ये व्यक्ति सुरक्षा व नियंत्रण व्यक्ति कहलायेंगे। इनके पदनाम व दूरभाष नम्बर सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के मध्य वितरित किये जायेंगे। सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सम्बन्धित व्यक्तियों को तुरन्त अधिसूचित किया जायेगा।
- (2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा उपयोगकर्ता सुरक्षा पुस्तिका तैयार करेंगे जिसमें अलग से जारी सुरक्षा कोड के अधीन वितरण प्रणाली पर आधारित वितरण प्रणाली के प्रत्येक पहलू हेतु किये जाने वाली सुरक्षा सावधानियों को सम्मिलित किया जायेगा। उपयोगकर्ता की प्रणाली के किसी भाग या वितरण प्रणाली के किसी भाग में किसी लाईन या उपकरण, स्विच गेयर या सर्किट पर किये जा रहे कार्य के समय सभी सुरक्षा नियम व सावधानियाँ बरती जायेंगी। इस प्रकार तैयार सुरक्षा कोड सभी सुरक्षा व नियंत्रण व्यक्तियों तथा ऐसे उपयोगकर्ताओं को अनुपालन हेतु जारी किया जायेगा।
- (3) अन्तर संयोजन के बिन्दु पर प्रत्येक पक्ष में किसी उपकरण या लाईनों पर कार्य करने के लिये, वितरण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ताओं के मध्य, विद्युतीय उभयनिष्ठता वाले दो वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य सामंजस्य होगा।
- (4) यू0ई0आर0सी0 (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2007 के उपबन्ध, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ सामंजस्य कर संयोजक बिन्दुओं/उभयनिष्ठ बिन्दुओं पर अपनाये जायेंगे।
- (5) प्रत्येक विद्युतीय उभयनिष्ठ पर विच्छेदक युक्ति (या), जो कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी व अन्य उपयोगकर्ताओं की प्रणाली को प्रभावी रूप से विच्छेदित करने की क्षमता रखती हो तथा नियंत्रण सीमा पर सम्बन्धित प्रणाली की आधारभूत ज्ञान-युक्तियाँ विनियमित की जायेंगी। इन्हें हर समय एवं अच्छी स्थिति में रखा जायेगा। अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा गलती से इसका उपयोग रोकने के लिये इन विच्छेदन युक्तियों में एक दूसरे से जुड़े ताले लगाये जायेंगे।
- (6) जहाँ कहीं किसी उपभोक्ता ने कोई आपात ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली लगाई हुई है, चाहे वह इलैक्ट्रॉनिक हो, स्टोर बैटरीज हो या जेनरेटर हो तो यह व्यवस्था होगी कि आपूर्ति मेन्स से प्रणाली को पूरी तरह अलग किये बिना इसे संचालित न किया जा सके। आपूर्ति मेन्स से इसे अलग करने की अपेक्षित व्यवस्था की जिम्मेदारी उपयोगकर्ता की होगी तथा अनुमोदन हेतु विद्युत निरीक्षक के पास जमा किये गये नक्शे का यह एक भाग होगा। अनुमोदित नक्शे की एक प्रति, इसके पश्चात् वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध कराई जायेगी। न्यूट्रल कन्डक्टर सहित किसी कन्डक्टर से वितरण प्रणाली की प्रतिपुष्टि की सम्भावना स्पष्टतः नियम बाह्य ठहराई जायेगी।
- (7) विद्युतीय उभयनिष्ठ पर उचित नियंत्रक व्यक्ति, विद्युतीय उभयनिष्ठ से परे किसी उपकरण, स्विचगियर या लाईनों पर कार्य करने के लिये अपने प्रतिस्थानों को लिखित अनुमति जारी करेगा। ऐसी अनुमतियाँ कार्य का अनुज्ञापत्र (पीटीडब्ल्यू) कहलायेंगी। पीटीडब्ल्यू का प्रारूप, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मानकीकृत होगा तथा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाया जायेगा।
- (8) सभी अनुरक्षण कार्य, विधिवत, पदनामित अधिकारी द्वारा अधिकृत कराये जायेंगे। अनुरक्षण कार्य हेतु पीटीडब्ल्यू की प्रणाली अपनाई जायेगी। अनुरक्षण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त पीटीडब्ल्यू की वापसी के बिना लाईन को पुनः सक्रिय नहीं किया जाना चाहिये।
- (9) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सम्बन्धित उपयोगकर्ताओं के साथ परामर्श कर, पीटीडब्ल्यू के जारी किये जाने व वापसी से पहले, सुरक्षा समन्वय हेतु प्रक्रियाओं व लिये जाने वाले परिचालन कार्यों की जांच सूची बनायेगा। ऐसी जांच सूची व प्रक्रियायें, परिचालन के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को जारी की जायेगी।

5.9 परिचालक संप्रेषण :

- (1) एस0एल0डी0सी0 व वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अन्तःस्थापित उत्पादकों, उपयोगकर्ताओं व 1 एम0वी0ए0 से अधिक की मांग वाले उपभोक्ताओं के मध्य डाटा, सूचना व परिचालन अनुदेशों के विनिमय हेतु, विश्वसनीय संप्रेषण जैसे कि टेलीफोन, ई-मेल इत्यादि सम्पर्क स्थापित किये जायेंगे।
- (2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा इसकी वितरण प्रणाली से जुड़े उपयोगकर्ता अधिकारियों को पदनामित करेंगे तथा सूचना के आदान प्रदान हेतु संप्रेषण माध्यमों पर सहमत होंगे। जहां तक सम्भव हो, जिस वितरण प्रणाली से उपयोगकर्ता जुड़ा है, उसके परिचालक व उपयोगकर्ता के मध्य सीधा संप्रेषण हो।
- (3) नियंत्रक कार्य कलापों के कुशल समन्वय हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ताओं द्वारा दूरभाष नम्बरों, कॉल लाईन व ई-मेल आईडीज, का आदान-प्रदान किया जायेगा।

5.10 चलती फिरती ब्रैक डाउन वैन :

बिना देरी किये लाईन व प्रवर्तक दोषों व उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे के लिये महत्वपूर्ण शहरों व नगरों में वितरण अनुज्ञप्तिधारी चलती फिरती ब्रैक डाउन वैन उपलब्ध करायेगा। ये चलती फिरती ब्रैक डाउन वैन, ड्यूटी पर हर समय सभी आवश्यक उपकरणों, जैसे केबल जोड़ने की किट व उपभोज्यों से लैस होंगी। चलती फिरती ब्रैक डाउन वैन में वायरलेस फोन व हेलोस्कोपिंग सीढ़ी लगी होगी। इनमें मरम्मत हेतु सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध होंगे तथा उन्हें समय-समय पर बदला जायेगा।

5.11 आरक्षित व प्रतीक्षारत :

- (1) लाइनों व प्रवर्तकों की जबरन आउटेज परिस्थिति की जांच के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी पर्याप्त आरक्षित व प्रतीक्षारत आपात उपकरण रखेगा। इनमें ऑयल फिल्टरेशन सेट्स, केबल जोड़ने व रखरखाव की किट, चलती फिरती क्रैन, चैन पुली, लिफ्टर इत्यादि सम्मिलित हैं।
- (2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास आपात परिस्थिति के लिये, हर समय पर्याप्त अतिरिक्त प्रवर्तक, आइसोलेटर्स, सर्किट ब्रेकर्स, सीटीज पीटीज, इन्सुलेटर्स, हार्डवेयर केबल व केबल बॉक्सेज इत्यादि होने चाहिये।
- (3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास महत्वपूर्ण अवस्थितियों पर न्यूनतम रखरखाव उत्साही टोली उपलब्ध होनी चाहिये जिसे आपात स्वभाव के रखरखाव कार्य हेतु बुलाया जा सके।

5.12 निर्माण पद्धतियां :

- (1) सभी विद्युत आपूर्ति लाइनें व उपकरण, ऊर्जा, इन्सुलेशन व अनुमानित दोष प्रवाह हेतु पर्याप्त रेटिंग की व ड्यूटी, जो कि अधिष्ठान की पर्यावरणीय परिस्थितियों के अधीन प्रदर्शन हेतु अपेक्षित है, उस के लिये पर्याप्त यांत्रिक क्षमता की होनी चाहिये। इसका निर्माण, संस्थापना, संरक्षण व अनुरक्षण इस प्रकार होना चाहिये कि मानव जीवन, पशु व सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
- (2) राष्ट्रीय विद्युतीय कोड सहित भारतीय मानक ब्यूरो की सुसंगत कोड पद्धति, यदि कोई है, अपनाई जानी चाहिये। उपयोग किये जाने वाली सामग्री व उपकरण, जहां ऐसी विशिष्टतायें बनाई गई हों, भारतीय मानक ब्यूरो की सुसंगत विशिष्टताओं को पुष्ट करेंगे।
- (3) अनुज्ञप्तिधारी, विभिन्न उपस्कर/कार्य जैसे कि 33 के0वी0 लाईन्स, 11 के0वी0 लाईन्स, एल0टी0 लाईन्स, 33 के0वी0 सबस्टेशनों व 11 के0वी0 सबस्टेशनों के लिये निर्माण व अनुरक्षण नियमावली तैयार करेगा व उसका पालन करेगा। निर्माण व अनुरक्षण नियमावली निम्नलिखित का ध्यान रखते हुए तैयार की जायेगी :-
 - (क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73 (बी) के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट विद्युतीय संयंत्र, विद्युत लाईन के निर्माण व गिड के संयोजिता हेतु तकनीकी मानक।
 - (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73 (सी) के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट, विद्युत संयंत्रों व विद्युत लाईनों के निर्माण, परिचालन व अनुरक्षण हेतु सुरक्षा अपेक्षाएँ।
 - (ग) आर0ई0सी0 निर्माण मानक व मानक डिजायन नक्शा।
 - (घ) कोड की पद्धतियों पर सीबीआईपी प्रकाशन।

- (ड) विभिन्न उपकरणों व अनुरक्षण पद्धतियों हेतु भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी पद्धतियों का कोड।
 (व) सम्बन्धित मानक उपस्कर विनिर्माता द्वारा जारी संस्थापना, परिचालन व अनुरक्षण हेतु अनुदेश नियमावली।

(4) कण्डक्टर, आकार, फ्यूज आकार, वायर गेज, इलैक्ट्रीकल क्लीयरेंस, ग्राउन्ड वायर आकार, इन्सुलेशन रेजिस्टेंस व अर्थ रेजिस्टिवली इत्यादि हेतु मानक सारिणियां निर्माण व अनुरक्षण नियमावली में सम्मिलित की जायेंगी। वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसका निर्माण व अनुरक्षण स्टाफ इस नियमावली में दिये गये आदर्शों का पालन करें।

5.13 निवारक (प्रीवेंटिव) अनुरक्षण अनुसूचियां :

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण प्रणाली में संस्थापित विभिन्न लाईन व उपस्टेशन उपस्करों हेतु एक निवारक अनुरक्षण अनुसूची तैयार करेगा। इस निवारक अनुरक्षण अनुसूची में निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपस्कर सम्मिलित होंगे :-

- (क) बाहर/भीतर संस्थापित ऊर्जा प्रवर्तक व वितरण प्रवर्तक;
 (ख) 11 के०वी० व 33 के०वी० सर्किट ब्रेकर्स व सहायक उपस्कर;
 (ग) सामान्य आदेश (जीओ) स्वीचेस व ड्राप आउट फ्यूजेस सहित 11 के०वी० व 33 के०वी० ओवर हेड लाईन्स;
 (घ) 11 के०वी० व 33 के०वी० केबल्स व केबल बक्से;
 (ङ) एल०टी० लाइनें व सर्किट ब्रेकर्स, तथा
 (च) सेवा संयोजन।

(2) निवारक अनुरक्षण अनुसूची में निम्नलिखित का समावेश करने वाले खंड होंगे :-

- (क) निरीक्षण हेतु संस्तुत अनुसूची;
 (ख) निवारक अनुरक्षण हेतु संस्तुत अनुसूची;
 (ग) पूरी मरम्मत हेतु संस्तुत अनुसूची।

(3) निरीक्षण अनुसूची व निवारक अनुरक्षण अनुसूची में विभिन्न उपस्कर हेतु की जाने वाली दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक अवधि की गतिविधियां होंगी।

5.14 अनुरक्षण अभिलेख :

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, निवारक अनुरक्षण अनुसूची में निर्धारित मानक प्रारूप में, समय-समय पर किये जाने वाले निरीक्षण का अभिलेख रखेगा। अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित का अभिलेख रखा जायेगा :-

- (क) बाहर/भीतर संस्थापित ऊर्जा प्रवर्तक व वितरण प्रवर्तक।
 (ख) 11 के०वी० तथा 33 के०वी० सर्किट ब्रेकर्स।
 (ग) 33 के०वी० तथा 11 के०वी० लाईनें।

(2) सभी उपस्करों जैसे कि प्रवर्तकों, स्विचगियर्स, प्रोटेक्टिव रिलेज इत्यादि का नियमित परीक्षण विनिर्माता तथा भारतीय मानक ब्यूरो व सीबीआईपी द्वारा जारी सुसंगत पद्धति के कोड द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार किया जायेगा। यह परीक्षण निर्धारित अंतराल में किये जायेंगे तथा इनका परिणाम अनुरक्षण पंजी में अभिलिखित किया जायेगा। जहां कहीं परीक्षण परिणाम इन्सुलेशन रेजिस्टेंस में गिरावट व/या उपस्कर में हास इंगित करते हों, वहां सेवा योग्यता, सुरक्षा व कुशलता सुनिश्चित करने के लिये निवारक अनुरक्षण किया जायेगा। वर्तमान में अनुरक्षण परीक्षण कार्यक्रम आर०ई०सी० नियमावली के अनुसार अपनाया जायेगा।

(3) उपभोक्ता हर समय अपने उपकरणों व ऊर्जा लाईनों को भारतीय विद्युत नियम, 1956 से पुष्टि करते हुए अनुरक्षित रखेंगे तथा ये एक सुरक्षित व विश्वसनीय तरीके के साथ वितरण प्रणाली से संयोजन हेतु उपयुक्त होंगे।

5.15 पर्यावरणीय मुद्दे :

- (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण प्रणाली में नियोजन, डिजायन, विनिर्माण व परिचालन में पर्यावरणीय नियामक मार्गदर्शकों का उचित ध्यान रखेगा। पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन, हरित व आरक्षित क्षेत्र में सबस्टेशनों के विनिर्माण जैसे सभी बड़ी वितरण परियोजनाओं के लिये किया जायेगा। अपेक्षित अनुमति व अनापत्ति, जहां कहीं ऐसा निर्धारित हो, राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड से लिया जायेगा।
- (2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि पर्यावरणीय सरोकार, व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन व पर्यावरणीय कार्यवाही योजना (ई0ए0पी0) के द्वारा उचित अग्रिम कार्यवाही के माध्यम से उचित रूप से निपटाये जायें।

5.16 ऊर्जा संरक्षण :

- (1) सम्पूर्ण मांग को न्यूनतम करने, ऊर्जा संरक्षण व मांग पक्ष प्रबंधन (डी0एस0एम0), वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उच्च प्राथमिकता देगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा इस सम्बन्ध में ऊर्जा कुशलता ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफेशियेन्सी) के मार्ग-दर्शकों का अनुवर्तन करेगा।
- (2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अधीन ऊर्जा केन्द्रित उद्योग के लिये आवधिक ऊर्जा लेखा परीक्षा जहां कहीं आवश्यक की गई है, वहां उपभोक्ताओं द्वारा इसका अनुपालन किया जाये। अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी ऊर्जा लेखा परीक्षा कराने व ऊर्जा संरक्षण उपाय कराने के लिये प्रोत्साहित किया जाये। ऊर्जा संरक्षण उपाय उन सभी सरकारी भवनों द्वारा अपनाये जायेंगे जिन के लिये बचत क्षमता लगभग 30% ऊर्जा अनुमानित की गई है। सोलर द्वारा पानी गर्म करने की प्रणाली व सोलर पैंसिव आर्किटेक्चर इस प्रयास में पर्याप्त योगदान प्रदान कर सकते हैं।
- (3) कृषि क्षेत्र में वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उच्च कुशलता हेतु निर्मित पम्पसेट्स व जल प्रेषण प्रणाली प्रोन्नत करेगा। औद्योगिक क्षेत्र में वितरण अनुज्ञप्तिधारी, ऊर्जा संरक्षण उपायों के रूप में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी की प्रोन्नति हेतु कार्यवाही करेगा। मोटर व ड्राइव प्रणाली, औद्योगिक व कृषि क्षेत्र में उच्च उपभोग के मुख्य स्रोत हैं। वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह सलाह देगा कि उपभोक्ता कृषि व औद्योगिक क्षेत्र में उच्च दक्षता मोटरों का उपयोग करें। वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे प्रभावी कदम उठायेगा जिससे औद्योगिक, व्यावसायिक व घरेलू अधिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता प्रकाश प्रौद्योगिकी अपनाई जाये।
- (4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह प्रयास करेगा कि एक दक्ष लोड प्रबंधन प्राप्त करने के लिये अधिकतम मांग व कम मांग समय आपूर्ति हेतु विभेदक शुल्क संरचना व मीटरिंग व्यवस्था (दिन के समयानुसार मीटरिंग) जैसे उपयुक्त लोड प्रबंधन तकनीकी के माध्यम से व अधिकतम मांग समय व कम मांग समय की अवधि में विद्युत ऊर्जा मांग के मध्य अंतर कम दूर सम्भावित सीमा तक क्षमता वृद्धि की आवश्यकता को कम किया जाये।

5.17 औजार व पुर्जो :

- (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अनुरक्षण कार्य के लिये सभी कार्य स्थलों पर उचित औजारों व उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। औजार व उपकरणों की समय-समय पर जांच की जायेगी तथा उनकी सेवायोग्यता सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उसके द्वारा नियत एक स्पष्ट नीति के अनुसार उपयुक्त अवस्थितियों पर अनुरक्षण व बदले जाने के लिये अपेक्षित पुर्जों की एक तालिका रखेगा।

5.18 मानव संसाधन विकास व प्रशिक्षण :

वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अपने वितरण प्रणाली परिचालन व अनुरक्षण पद्धतियों में अधिकारियों/स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण दिलायेगा ताकि इस विनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित किया जा सके। वितरण अनुज्ञप्तिधारी, कर्मचारियों व पर्यवेक्षक स्टाफ को प्रशिक्षण देने के लिये समुचित व्यवस्था करेगा तथा इसमें वितरण प्रणाली डिजायन, विनिर्माण व अनुरक्षण की नवीनतम तकनीक व सुरक्षा उपाय सम्मिलित किये जायेंगे।

5.19 भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)/ग्लोबल पोजीशन उपग्रह (जीपीएस) आधारित सूचना प्रणाली :

वितरण अनुज्ञाप्री, वितरण प्रणाली के परिचालन व अनुरक्षण हेतु चरणों में, जीआईएस/जीपीएस, वितरण

प्रणाली के सभी महत्वपूर्ण तत्वों के मानचित्रीकरण हेतु उपयोग में लाया जायेगा जिसमें लाईनें, प्रवर्तक, सबस्टेशन, उत्पादक स्टेशन, सभी यूनिट अवस्थितियां सम्मिलित हैं तथा अन्ततः सभी उपभोक्ताओं को समावेशित करता है। जीआईएस को एक्टिव रिलेशनल डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली (आरडीबीएमएस) से जोड़ा जायेगा व जीपीएस का उपयोग टाईम सिन्क्रोनाइजेशन के लिये किया जायेगा।

अध्याय 6—वितरण संरक्षण अपेक्षाएं

6.1 परिचय :

वितरण प्रणाली के संरक्षण के लिये तथा पारेषण प्रणाली में प्रवेश कर जाने वाली दोषों को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि वितरण प्रणाली से जुड़े वितरण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ताओं के लिये, संरक्षण हेतु कुछ न्यूनतम मानक विनिर्दिष्ट किये जायें। इस अध्याय में इन न्यूनतम मानकों को वर्णित किया गया है।

6.2 उद्देश्य :

इस अध्याय का उद्देश्य, वितरण प्रणाली से जुड़े किसी उपस्कर हेतु अपेक्षित न्यूनतम मानक को निश्चित करना है ताकि दोषपूर्ण वितरण खण्ड की ऊर्जा प्रणाली को शेष भाग से अलग कर, दोषों के कारण होने वाले व्यवधान को कम से कम किया जा सके।

6.3 सामान्य सिद्धांत :

(1) विद्युत उपस्कर के किसी मद को वितरण प्रणाली से जुड़ा रहने नहीं दिया जायेगा जब तक कि यह विश्वसनीयता, चयनता, संरक्षक रिलेज/युक्तियों संवेदनशीलता के उद्देश्य से उपयुक्त संरक्षण से ढका हुआ न हो। वितरण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता, यूईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) अधिनियम, 2007 में विनिर्दिष्ट, लक्षित अनुमति समय के भीतर दोषपूर्ण उपस्कर प्रभावी, भेदमूलक युक्ति प्राप्त करने के लिये, संरक्षण का सही व उपयुक्त सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिये पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ सहयोग करेंगे।

(2) सम्बन्धित वितरण अनुज्ञप्तिधारी से परामर्श किये बिना संरक्षक रिले स्थापनाओं को बदला नहीं जायेगा या संरक्षण को बाय पास व/या विच्छेदित नहीं किया जायेगा। यदि संरक्षण को आपसी सहमति से बाय पास व/या विच्छेदित किया गया है तो जितना शीघ्र सम्भव हो, उसे सुधारा जाना चाहिये व संरक्षण को सामान्य स्थिति में लाना चाहिये। यदि कोई सहमति नहीं बनती है तो इसके आगे सभी विद्युत उपस्कर अलग किये जायेंगे।

6.4 संरक्षण नियमावली :

वितरण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण प्रणाली व संयोजित उपयोगकर्ता प्रणाली के भीतर न्यूनतम संरक्षण अपेक्षाओं को इंगित करते हुए संरक्षण की मानक नियमावली तैयार करेगा व लागू करेगा। संरक्षण नियमावली में आपूर्ति लाईनें व ऊर्जा व वितरण प्रवर्तक, जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं को आपूर्ति उपलब्ध कराई जाती है, सम्मिलित होंगी। संरक्षण नियमावली, यूईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2007 को ध्यान में रखकर बनाई जायेगी तथा इसमें विभिन्न स्थानों पर दोष के स्तरों पर सुसंगत डाटा, अति करेन्ट व अर्थ दोषों हेतु मानक रिलेज तय करने के लिये मार्गदर्शन, फ्यूज रेटिंग चयन मानदण्ड इत्यादि का समावेश होगा। संरक्षण नियमावली की एक प्रति, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसको तैयार कर लिये जाने के पश्चात् इस अपेक्षा के अनुपालन में आयोग को प्रस्तुत की जायेगी।

6.5 ईएचटीजीएसएस में अन्तः संयोजित बिंदु पर संरक्षण :

ईएचटीजीएसएस से निकलने वाली सभी 33 के0वी0 व 11 के0वी0 लाईनों में यूईआरसी (ग्रिड कोड) नियमावली, 2007 की अपेक्षाओं के अनुसार उच्च स्थापित एलीमेन्ट के साथ निदेशक विशेषताओं के बिना या उनके साथ न्यूनतम अति करेन्ट व अर्थ दोष संरक्षण उपलब्ध कराया जायेगा। मूल ईएचटी सबस्टेशन के साथ सामंजस्य सुनिश्चित किया जाना चाहिये ताकि वितरण फीडर्स में देर से दोष दूर करने के कारण, दोषों के कारण धीमी या तीव्र गति से मुख्य सबस्टेशन उपस्कर/ईएचटी पारेषण लाईनों को अलग रखा जा सके।

6.6 33 के0वी0 व 11 के0वी0 लाईन संरक्षण :

- (1) पोषक सबस्टेशन से 33 के0वी0 व 11 के0वी0 लाईनों के लिये संरक्षक रिलेज की स्थापना इस प्रकार होगी कि किसी खण्ड में यदि कोई दोष है तो सभी परिस्थितियों में उत्पादक यूनिट/पोषक सबस्टेशन व दोषपूर्ण खण्ड के मध्य धारा के विपरीत का खण्ड प्रभावित न हो। 33 के0वी0 रेडियल लाईनों में, पोषक स्टेशन पर दो अति करेन्ट व एक अर्थ दोष नॉन-डायरेक्शनल आई.डी.एम.टी. रिले संरक्षण होंगे। रिलेज में तात्कालिक अति करेन्ट एलीमेंट भी होगा। जहाँ दो सबस्टेशनों के मध्य या उत्पादक यूनिट व सबस्टेशन के मध्य 33 के. वी. लाईन एक अन्तः संयोजन है, वहाँ इन रिलेज में निदेशक विशिष्टताएं होंगी।
- (2) संयोजन बिन्दुओं पर सभी 22 के.वी. व 11 के.वी. लाईनों में निम्नानुसार न्यूनतम अति करेन्ट व अर्थ दोष रिले लगाए जायेंगे :-

1.	रेडियल पोषक	साथ में लगे रिले सैटिंग्स के मध्य विभेद प्राप्त करने के लिये उपयुक्त सैटिंग्स के साथ नॉन-डायरेक्शनल टाईम लैग अति करेन्ट व अर्थ दोष रिलेज।
2.	समानान्तर/रिंग पोषक व अन्तः संयोजित पोषक	डायरेक्शनल टाईम लैग अति करेन्ट व अर्थ दोष रिलेज
3.	लंबे पोषक/प्रवर्तक पोषक	इन पोषकों में उच्च स्थापित तात्कालिक एलीमेंट होगा।

6.7 प्रवर्तक संरक्षण :

वितरण प्रणाली में संस्थापित प्रवर्तकों की न्यूनतम संरक्षण अपेक्षा निम्नानुसार होगी :-

(1) 33/11 के.वी. प्रवर्तक

(क) प्राथमिक दिशा में :

- (i) प्रवर्तक की प्राथमिक दिशा में इतनी क्षमता का एक लिंक स्विच जिस क्षमता से पूर्ण भार करेन्ट ले जाया जा सके तथा प्रवर्तक का मैग्नेटाइजिंग करेन्ट ही अवरुद्ध हो सके, बशर्ते कि प्रवर्तक की क्षमता 1500 के.वी.ए. से अधिक न बढ़े।
- (ii) 1500 के.वी.ए. से अधिक क्षमता वाले प्रवर्तकों के लिये पर्याप्त क्षमता के सर्किट ब्रेकर उपलब्ध कराये जायें।

(ख) द्वितीयक दिशा में :

सभी प्रवर्तकों के लिये पर्याप्त क्षमता के सर्किट ब्रेकर उपलब्ध कराये जायें।

(ग) 1500 के.वी.ए. तक के प्रवर्तकों में बुशहोल्टज, वाईडिंग व ऑयल तापमान एलार्म संरक्षण उपलब्ध कराये जायें। 1500 के.वी.ए. से अधिक के प्रवर्तकों में एलार्म व ट्रिपिंग संरक्षण दोनों ही प्रकार के संरक्षण उपलब्ध कराये जायेंगे।

(घ) 5 एम.वी.ए. से अधिक क्षमता के प्रवर्तक, विभेदक संरक्षण द्वारा सहज दोषों के विरुद्ध संरक्षित किये जायेंगे।

(2) 11/0.4 के.वी. वितरण प्रवर्तक

(क) प्राथमिक दिशा पर :

- (i) प्रवर्तकों की प्राथमिक दिशा में इतनी क्षमता का एक लिंक स्विच जिस क्षमता से पूर्ण भार करेन्ट ले जाया जा सके तथा प्रवर्तक का मैग्नेटाइजिंग करेन्ट ही अवरुद्ध हो सके, उपलब्ध कराया जायेगा।

(ख) द्वितीयक दिशा पर :

- (ii) 250 के.वी.ए. व उससे अधिक क्षमता के सभी प्रवर्तकों में पर्याप्त रेटिंग के सर्किट ब्रेकर्स होंगे।
- (iii) 250 के.वी.ए. से कम क्षमता वाले प्रवर्तकों के मामले में पर्याप्त रेटिंग का सर्किट ब्रेकर या फ्यूज के साथ एक लिंक स्विच उपलब्ध कराया जायेगा।

6.8 संरक्षण सामंजस्य

- (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विभिन्न ई.एच.टी. सबस्टेशनों पर दोष स्तरों पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ताओं से संग्रहित डाटा से रिले सैटिंग्स निर्धारित करेगा। उत्पादक कंपनियों, पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों व वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के प्रतिनिधि ऐसी खराबियों, प्रणाली की आकृति व रिलेज की संभावित संशोधित सैटिंग्स पर चर्चा करने के लिये नियत अवधि में बैठक करेंगे। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, समय-समय पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ताओं को प्रारंभिक सैटिंग्स पर इसके बाद के परिवर्तनों के संबंध में अधिसूचित करेगा। संरक्षक रिलेज के प्रदर्शन पर नैतिक जांच संचालित की जायेगी तथा कोई भी गड़बड़ी होने पर उसे नोट कर यथाशीघ्र सुधारा जायेगा।
- (2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यू.ई.आर.सी. (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2007 की अपेक्षाओं के अनुसार, संरक्षण के सामंजस्य पर चर्चा करने के लिये उत्पादक कंपनियों, वितरण अनुज्ञप्तिधारी व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य नियत कालीन बैठकों की व्यवस्था करने के लिये जिम्मेदार होगा। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी संरक्षण में किसी गड़बड़ी या किसी अन्य असंतोषजनक संरक्षण मामले में अन्वेषण करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इन नियत कालीन बैठकों में की गयी चर्चा व सहमति के अनुसार किसी संरक्षण गड़बड़ी को सुधारने के लिये तुरन्त कार्यवाही करेगा।

अध्याय 7—सीमा पार सुरक्षा कोड

7.1 परिचय :

यह अध्याय सीमापार परिचालन से सम्बन्धित उपस्करों के अनुरक्षण हेतु सुरक्षित कार्य पद्धतियों के लिए आवश्यकताओं को विनिर्दिष्ट करता है तथा दूसरे उपयोगकर्ता की प्रणाली से जुड़े विद्युत उपस्कर पर चल रहे कार्य के दौरान अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियत करता है।

7.2 उद्देश्य :

इस खण्ड का उद्देश्य, वितरण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ताओं के मध्य एक नियंत्रण सीमा के पार कार्य करते हुए सुरक्षा के सिद्धांतों पर सहमति प्राप्त करना।

7.3 नियंत्रण व्यक्ति व उनके उत्तरदायित्व :

- (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा सभी उपयोगकर्ता (इनमें उत्पादक कंपनियां, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व 1 एम.वी.ए. व उससे ऊपर के भार या डेडिकेटेड लाईन वाले उपभोक्ता सम्मिलित हैं) अपनी सीमा के पार, उपयुक्त रूप से अधिकृत व तकनीकी रूप से योग्य उत्तरदायी व्यक्तियों को नामित करेगा। इन व्यक्तियों को "नियंत्रण व्यक्तियों" के रूप में संदर्भित किया जायेगा।
- (2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उन सभी उपयोगकर्ताओं को जिनकी उसके साथ सीधी नियंत्रण सीमा है। नियंत्रण व्यक्तियों के नाम, पदनाम, पता व दूरभाष नम्बर के साथ उनकी एक सूची जारी करेगा, सूची में लिखे गये नामों में से किसी नियंत्रण व्यक्ति के नाम, पदनाम, दूरभाष नम्बर में परिवर्तन होने के स्थिति में इस सूची को तुरन्त अद्यतन किया जायेगा।
- (3) सभी उपयोगकर्ता जिनकी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ सीधी नियंत्रण सीमा है, वे अपने नियंत्रण व्यक्तियों की ऐसी ही सूची अनुज्ञप्तिधारी को जारी करेंगे। सूची में लिखे गये नामों में से किसी नियंत्रण व्यक्ति के नाम, पदनाम व दूरभाष नम्बर में परिवर्तन होने की स्थिति में इस सूची को तुरन्त अद्यतन किया जायेगा।
- (4) जब कभी उपयोगकर्ता या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सीमा पार कोई कार्य किया जायेगा तो उपयोगकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण व्यक्ति जिन्हें यह कार्य करना है, वे सीधे अपने प्रतिस्थानी से संपर्क करेंगे। दोनों पक्षों की उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए, कार्य के समय पर कोड शब्दों पर सहमत हुआ जायेगा, नियंत्रण व्यक्तियों के मध्य संपर्क, साधारणतया सीधे टेलीफोन द्वारा किया जायेगा।

- (5) यदि कार्य एक शिफ्ट से अधिक बढ़ जाता है तो नियंत्रण व्यक्ति राहत नियंत्रण व्यक्ति को प्रभार सौंप देगा तथा उसे कार्य में स्वभाव व परिचालन के कोड शब्दों से भलीभांति अवगत करायेगा।
- (6) एक सुरक्षित तरीके से, अपेक्षित कार्य करने के लिये की जाने वाली आवश्यक सावधानियां स्थापित करने व उन्हें बनाये रखने के लिये नियंत्रण व्यक्ति सहयोग करेंगे। स्थापित पृथक्करण व स्थापित अर्थ, जहां कहीं ऐसी सुविधा अस्तित्व में हो, वहां इन्हें ताले में रखा जायेगा तथा स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जायेगा।
- (7) कार्य का प्रभारी नियंत्रण व्यक्ति स्वयं इस बात से अपनी संतुष्टि करेगा कि कार्य प्रारम्भ किये जाने से पहले बरती जाने वाली सावधानियां स्थापित कर ली गयी हैं। वह दल को कार्य प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान करने के लिए सुरक्षा दस्तावेज जारी करेगा।
- (8) कार्य के पूर्ण हो जाने पर, किये जाने वाले कार्य के प्रभारी नियंत्रक व्यक्ति को स्वयं अपनी संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि बरती गयी सुरक्षा सावधानियों की अब आवश्यकता नहीं है तथा वह अपने प्रतिस्थानी नियंत्रण व्यक्ति से सीधा संपर्क करेगा व सुरक्षा सावधानियों को हटाने का निवेदन करेगा। दो नियंत्रण व्यक्तियों के मध्य कोड शब्द संपर्क का उपयोग करते हुए तथा कार्यदल से, सुरक्षा दस्तावेज वापिस लेकर, सीधे संपर्क द्वारा सभी सुरक्षा सावधानियों के हटायें जाने की पुष्टि के पश्चात् की उपस्कर को सेवा से वापसी हेतु उपयुक्त घोषित किया जायेगा।
- (9) वितरण अनुज्ञप्तिधारी सीमापार सुरक्षा हेतु एक सहमति प्राप्त लिखित प्रक्रिया विकसित करेगा तथा इसे नियमित रूप से अद्यतन करेगा।
- (10) सीमापार सुरक्षा से सम्बन्धित एस.टी.यू. के स्तर पर सुलझाया जायेगा, जबकि एस.टी.यू. इसमें पक्ष नहीं होगी। जहां किसी मामले में एस.टी.यू. पक्ष है, वहां विवाद को हल करने के लिए आयोग के पास भेजा जायेगा।

7.4 विशेष प्रतिफल :

- (1) सीमापार सर्किट्स पर सभी उपस्कर जिनका उपयोग पृथक्करण व अर्थिंग के सुरक्षा सामंजस्य व स्थापना के उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना हो, सबस्टेशन विशेष की विशिष्ट पहचान संख्या या नाम के साथ स्थायी व स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जायेगा। इन उपस्करों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जायेगा व इन्हें विनिर्माता की विशिष्टताओं के अनुसार रखा जायेगा।
- (2) प्रत्येक नियंत्रण व्यक्ति उसके द्वारा भेजे गये व प्राप्त किये गये सुरक्षा सामंजस्य से सम्बन्धित सभी परिचालनों व संदेशों को कालक्रम में स्पष्ट रूप से लिखित सुरक्षा लॉग में रखेगा। यह सभी सुरक्षा लॉग कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिये रखे जायेंगे।
- (3) जहां तक संभव हो, प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक सबस्टेशन द्वारा पोषित क्षेत्र से सम्बन्धित उसकी प्रणाली का एक अद्यतन नक्शा रखेगा, अन्यथा 11 के.वी. व इससे ऊपर हेतु प्रणाली का रेखाचित्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के सम्बन्धित क्षेत्र कार्यालयों/पोषक सबस्टेशनों में रखा जायेगा व प्रदर्शित किया जायेगा।

अध्याय 8—घटना/दुर्घटना रिपोर्टिंग

8.1 परिचय :

इस अध्याय में उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मुख्य विद्युत निरीक्षक को रिपोर्टिंग (वितरण प्रणाली में होने वाली) मुख्य घटना/दुर्घटना का समावेश है।

8.2 मुख्य घटना या दुर्घटना रिपोर्टिंग :

- (1) उपयोगकर्ता, अनुज्ञप्तिधारी को, प्रणाली में होने वाली मुख्य घटनाओं के संबंध में तुरन्त सूचना प्रस्तुत करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता सूचना के आदान-प्रदान हेतु एक प्रारूप व प्रक्रिया स्थापित करेंगे।
- (2) घटनाओं की रिपोर्टिंग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 161 के साथ पठित, भारतीय विद्युत नियमों, 1956 के नियम 44-ए के अनुरूप होगी। यदि वितरण प्रणाली में कोई दुर्घटना होती है जिसके परिणामस्वरूप मानवजीवन या पशुजीवन की हानि हो या उसे चोट पहुंचे या संभावित परिणामस्वरूप ऐसी संभावना हो, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी घटना होने के 24 घंटे के भीतर विद्युत निरीक्षक को दूरभाष पर उसकी रिपोर्ट देगा। इसके पश्चात्, घातक या अन्य दुर्घटनाओं के होने की जानकारी 24 घंटे के भीतर परिशिष्ट-6 (भारतीय विद्युत

अधिनियम, 1956 के नियम 44-ए के परिशिष्ट xiii) में दिये प्रपत्र में लिख कर रिपोर्ट की जायेगी।

8.3 रिपोर्टिंग प्रक्रिया :

- (1) वितरण प्रणाली में लाईनों व सबस्टेशनों में होने वाली सभी रिपोर्ट करने योग्य घटनाओं की, जिस अनुज्ञप्तिधारी के यहां यह घटना हुई है, उसके द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा चिन्हित अन्य सभी पर्याप्त रूप से प्रभावित उपयोगकर्ताओं को, मौखिक रूप से रिपोर्ट की जायेगी। रिपोर्ट करने वाले वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी मौखिक रिपोर्ट करने के पश्चात् एक घंटे के भीतर, वितरण व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपस में सहमत निर्धारित प्रारूप में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिये। यदि रिपोर्ट की जाने वाली घटना गंभीर स्वभाव की है तो लिखित रिपोर्ट छः घंटे के भीतर की जायेगी। इसके पश्चात् प्रारम्भिक लिखित रिपोर्ट के पश्चात् 7 दिन के भीतर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। अन्य मामलों में, रिपोर्ट करने वाला वितरण अनुज्ञप्तिधारी पन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (2) अन्य उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करने वाली किसी रिपोर्ट करने योग्य घटना पर, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से रिपोर्ट मांगेगा, विशेष रूप से तब, यदि ऐसे उपयोगकर्ता व उपस्कर रिपोर्ट करने योग्य घटना का स्रोत हैं तथा वे इसकी रिपोर्ट न करें। किन्तु इससे उपयोगकर्ता को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन निर्मित सुसंगत उपबन्धों के अधीन संरक्षित नियमों के अनुरूप घटनाओं की रिपोर्ट करने की बाध्यता से राहत नहीं मिलेगी। ऐसी रिपोर्ट के लिये प्रारूप, वितरण कोड समीक्षा पैनल के अनुमोदन के अनुसार होगा तथा इसमें विशेष रूप से निम्नलिखित का समावेश होगा :-
 - (क) घटना की अवस्थिति;
 - (ख) घटना तिथि व समय;
 - (ग) संलिप्त संयंत्र या उपस्कर;
 - (घ) अवरोधित आपूर्ति व अवधि, जहां कहीं लागू हो;
 - (ङ) उत्पादन की हानि की मात्रा, जहां कहीं लागू हो;
 - (च) घटना के पहले व उसके पश्चात् प्रणाली के मानदण्ड (वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, भार, उत्पादन इत्यादि);
 - (छ) घटना से पहले नेटवर्क आकृति;
 - (ज) रिले संकेत व संरक्षण का प्रदर्शन;
 - (झ) घटना का संक्षिप्त विवरण;
 - (ञ) सेवा में वापसी का अनुमानित समय;
 - (ट) कोई अन्य संगत सूचना;
 - (ठ) भविष्य में सुधार के लिये संस्तुतियां;
 - (ड) रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम व पदनाम।
- (3) घटना के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभावों व खतरों के आकलन को समझने में रिपोर्ट प्राप्त करने वाले की सहायता हेतु रिपोर्ट पर्याप्त विस्तृत होनी चाहिए। प्राप्तकर्ता जहां कहीं आवश्यक समझे, वहां स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी की मांग कर सकता है तथा रिपोर्ट करने वाले उपयोगकर्ता के लिये बाध्यकारी होगा कि वह सभी आवश्यक व उचित जानकारी देने के लिये पूरा प्रयास करे।
- (4) दोनों ही पक्षों द्वारा निवेदन करने पर मौखिक रिपोर्ट को इसे भेजने वाले व्यक्ति द्वारा लिखा जायेगा तथा दूरभाष संदेश द्वारा बताया जायेगा या फैक्स/ई-मेल द्वारा भेजा जायेगा। आपात स्थिति में रिपोर्ट केवल मौखिक रूप से दी जा सकती है तथा बाद में लिखित में इसी पुष्टि की जा सकती है।
- (5) दुर्घटना की रिपोर्टिंग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 161 के अधीन निर्मित सुसंगत उपबन्धों के अधीन व उसके अधीन निर्मित नियमों के अनुरूप की जायेगी। उस समय तक जब तक कि विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन नियम, सी.ई.ए. द्वारा संरचित होते हैं, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, दुर्घटना की रिपोर्टिंग के लिये परिशिष्ट 6 में दिये गये प्रारूप को अपनायेगा।

परिशिष्ट-1

उपयोगकर्ता/उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला 1 एम.वी.ए. व उससे अधिक की मांग हेतु लोड डाटा

उपयोगकर्ता/उपभोक्ता का नाम व पता :

क्रम सं.	वर्णन	विवरण
1.	भार का प्रकार	(बतायें कि क्या स्टील मेल्टिंग फर्नेस लोड्स, रोलिंग मिल, ट्रेक्शन लोड, अन्य औद्योगिक लोड, पम्पिंग लोड्स इत्यादि हैं)
2.	अधिकतम मांग (कै.वी.ए.) व वार्षिक ऊर्जा आवश्यकता के.डब्ल्यू.एच. में	
3.	वर्ष/वर्षों, जब तक पूर्ण/आंशिक आपूर्ति अपेक्षित है	
4.	भार की अवस्थिति	(पैमाने के साथ अवस्थिति का नक्शा प्रस्तुत करें। उपभोक्ता की श्रेणी/क्षमता, समीपस्थ रेलवे स्टेशन व समीपस्थ ई.एच.टी. सबस्टेशन का विवरण इंगित करें)
5.	रेटेड वोल्टेज जिस पर आपूर्ति अपेक्षित है। क्या एकल फेज या तीन फेज की आपूर्ति की आवश्यकता है	
6.	आपूर्ति का प्रकार	सामान्य/वैकल्पिक/डेडिकेटेड (विवरण दें)
7.	उपस्करण का वर्णन	
क)	मोटर्स	अधिष्ठानों की संख्या व उद्देश्य, वोल्टेज व के.डब्ल्यू. रेटिंग, प्रारंभिक करेन्ट, मोटर का प्रकार, ड्राईव्स के प्रकार व कन्ट्रोल व्यवस्थाएं लिखें
ख)	हीटिंग	प्रकार व के.डब्ल्यू. रेटिंग
ग)	फर्नेस	प्रकार, फर्नेस प्रवर्तक क्षमता व वोल्टेज अनुपात
घ)	इलैक्ट्रोलायसिस	उद्देश्य, कै.वी.ए. क्षमता
ङ)	लाईटिंग	के.डब्ल्यू. मांग
8.	वोल्टेज/फ्रीक्वेन्सी में उतार-चढ़ाव पर मांग को संवेदनशीलता तथा अतिमांग समय पर आपूर्ति का उतार चढ़ाव (विवरण दें)	

9.	वोल्टेज संवेदनशीलता	एम.डब्ल्यू./के.वी. एम.वी.ए.आर./के.वी.
10.	फ्रीक्वेन्सी संवेदनशीलता	एम.डब्ल्यू./हर्ट्ज एम.वी.ए.आर./हर्ट्ज
11.	प्रणाली पर अधिरोपित फेज असंतुलन अधिकतम (%) औसतन (%)	
12.	अधिरोपित अधिकतम हारमोनिक अवयव (हारमोनिक्स को दबाने के लिये सम्मिलित युक्तियों का विवरण दें। साथ ही बिना फिल्टर के प्रत्येक युक्ति द्वारा विभिन्न क्रमों में हारमोनिक करेन्ट्स भी प्रस्तुत करें)	
13.	उन भारों का विवरण जो 5 सैकण्ड्स या उससे अधिक तक चलने वाली वोल्टेज गिरावट (%) सहित, संयोजना बिंदु पर 10 एम.डब्ल्यू. से अधिक की मांग में उतार चढ़ाव उत्पन्न कर सकता हो।	

परिशिष्ट-2

अन्तः संयोजित जनरेटर यूनिट वार डाटा

उत्पादक कंपनी का नाम व पता	
उत्पादक संयंत्रों की अवस्थिति	
टर्मिनल वोल्ट्स (के.वी.)	
रेटेड के.वी.ए.	
अधिकतम व न्यूनतम एक्टिव पावर (कि.वाट) भेजी गयी रिएक्टिव पावर अपेक्षाओं (के.वी.ए.आर.) यदि कुछ है	
उत्पादक संयंत्र का प्रकार— सिन्क्रोन्स, एसिनक्रोन्स इत्यादि	
दोष स्तर योगदान	
वोल्टेज नियंत्रण का तरीका	
जेनरेटर प्रवर्तक विवरण, यदि लागू हो	
टॉप अप आपूर्तियों व/या प्रतीक्षारत आपूर्तियों के लिये अपेक्षाएं	
जेनरेटर के.डब्ल्यू./के.वी.ए.आर. क्षमता चार्ट (निचले वोल्टेज टर्मिनल्स पर)	
एक्साईटेशन प्रणाली का प्रकार	
अक्रिय स्थिर के.डब्ल्यू.सेक./के.वी.ए.	
स्टेटर रेजिस्टेन्स	

डायरेक्ट-एक्सिस रिएक्टैन्स (सब ट्रान्जिएन्ट व सिन्क्रोनुअस)	
क्वाडरेटर-एक्सिस रिएक्टैन्स (सब ट्रान्सिएन्ट व सिन्क्रोनुअस)	
जीरो सीक्वेन्स (प्रतिरोधकता व रिएक्टैन्स)	
नेगेटिव सीक्वेन्स (प्रतिरोधकता व रिएक्टैन्स)	
जेनरेटर प्रवर्तक (प्रतिरोधकता, रिएक्टैन्स, के.वी.ए. रेटिंग, टैप व्यवस्था, वेक्टर समूह, ग्राउंडिंग, संयोजन व प्रतिशत इम्पीडेन्स)	
स्वचालित वोल्टेज रेगुलेटर ब्लॉक डायग्राम, प्राप्तिर्यों पर डाटा सहित (अग्रिम व फीडबैक) टाईम कॉन्स्टैन्ट्स व वोल्टेज कन्ट्रोल लिमिट्स	
यदि लागू हो तो गवर्नर फ्लाय बॉल के वर्णन के साथ स्पीड गवर्नर ब्लॉक डायग्राम तथा टर्बाईन रेटिंग व अधिकतम ऊर्जा के साथ नियंत्रण प्रणाली प्राईम मूवर टाईम कॉन्स्टैन्ट्स	
प्रतीक्षारत आवश्यकताएं	
प्रतीक्षारत क्षमता आवश्यकताओं के लिये के.डब्ल्यू. में प्रत्येक उत्पादन यूनिट का न्यूनतम उत्पादन व रेटेड क्षमता	
रेटेड क्षमता परिस्थितियों पर के.डब्ल्यू. व के.वी.आर. में उत्पादक यूनिट ऊर्जा स्टेशन सहायक मांग (सक्रिय ऊर्जा व प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा) उपभोक्ताओं के स्वतः उत्पादक संयंत्र के लिये इसमें टॉप अप अपेक्षाएं सम्मिलित होंगी	
समयनिष्ठ व्यवस्थाएं- वितरक व उपयोगकर्ता के मध्य एक कालिकता में साधन	
वितरण प्रणाली से सीधे जुड़े उत्पादक की प्रणाली का वह भाग जो ग्राउंड से जोड़ना है, उसके लिये व्यवस्थाएं	
संयोजन व विच्छेदन के साधन जो उपयोग में लाये जाने हैं	
उत्पादक की प्रणाली का कोई ग्राउंडेड न्यूट्रल प्वाइंट ग्राउंड से विच्छेदित हो जाता है तो सुरक्षित परिस्थितियां जारी रखना सुनिश्चित करने हेतु सावधानियां	

1-एम.वी.ए. या अधिक (जहां कहीं भी लागू हो) की सहमति मांग वाले आशयित उपयोगकर्ता/उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाने वाला प्रणाली डाटा।

1. जहां संयोजन के लिये आवेदन किया गया है/उपलब्ध कराना साध्य है, उस अवस्थिति से सुसंगत 33 के.वी. या उससे अधिक का वितरण लाईन डाटा।
2. प्रस्तावित मीटरिंग प्रणाली व संरक्षण प्रणाली।
3. दोष स्तर जिन पर उपभोक्ता को अपना उपस्कर डिजायन करना चाहिये।
4. उपभोक्ता के स्विच गियर हेतु दोष सुधारने का समय, तथा
5. सबस्टेशन दोष स्तर।

संयोजन सहमति पत्र :

स्थल उत्तरदायित्व सूचीपत्र -

सबस्टेशन का नाम/अवस्थिति :

स्थल स्वामी :

स्थल के समन्वयक अधिकारी का नाम :

दूरमाष नं० :

फैक्स नं० :

संयंत्र/ उपकरण की मद	संयंत्र का स्वामी	सुरक्षा उत्तरदायित्व	नियंत्रण उत्तरदायित्व	परिचालन उत्तरदायित्व	अनुरक्षण	टिप्पणी
.....के.वी. स्विचयार्ड						
बस बार सहित सभी उपकरण						
पोषक						
उत्पादक यूनिटें						
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						

	हस्ताक्षर
संयंत्र स्वामी	
सुरक्षा उत्तरदायित्व अधिकारी	
नियंत्रण उत्तरदायित्व अधिकारी	
परिचालन उत्तरदायित्व अधिकारी	
अनुरक्षण उत्तरदायित्व अधिकारी	

पावर फैक्टर उपकरणों की सूची

मोटर्सों के लिये

क्र.सं.	व्यक्तिगत मोटर की रेटिंग	कैपेसिटर की के०वी०ए०आर० रेटिंग				
		750 आर.पी.एम.	1000 आर.पी.एम.	1500 आर.पी.एम.	3000 आर.पी.एम.	
1	3 एच.पी. तक	1	1	1	1	
2	5 एच.पी.	2	2	2	2	
3	7.5 एच.पी.	3	3	3	3	
4	10 एच.पी.	4	4	4	3	
5	15 एच.पी.	6	5	5	4	
6	20 एच.पी.	8	7	6	5	
7	25 एच.पी.	9	8	7	6	
8	30 एच.पी.	10	9	8	7	
9	40 एच.पी.	13	11	10	9	
10	50 एच.पी.	15	15	12	10	
11	60 एच.पी.	20	20	16	14	
12	75 एच.पी.	24	23	19	16	
13	100 एच.पी.	30	30	24	20	
14	125 एच.पी.	39	38	31	26	
15	150 एच.पी.	45	45	36	30	
16	200 एच.पी.	60	60	48	40	

परिशिष्ट-5 (जारी)

पावर फैक्टर उपकरण की सूची

वैलिंग प्रवर्तकों के लिये

क्र.सं.	व्यक्तिगत वैलिंग प्रवर्तक की के.वी.ए. में नाम पट्टिका	कैपेसिटर की क्षमता (के.वी.ए.आर.)
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	3
5	5	4
6	6	5
7	7	6
8	8	6
9	9	7
10	10	8
11	11	9
12	12	9
13	13	10
14	14	11
15	15	12
16	16	12
17	17	13
18	18	14
19	19	15
20	20	15
21	21	16
22	22	17
23	23	18
24	24	19
25	25	19
26	26	20
27	27	21
28	28	22
29	29	22
30	30	23
31	31	24
32	32	25
33	33	25
34	34	26
35	35	27

परिशिष्ट-6

भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956

[परिशिष्ट xiii]

विद्युत दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिये प्रपत्र
(देखिये नियम 44—ए)

1	दुर्घटना की तिथि व समय	
2	दुर्घटना का स्थान (ग्राम/नगर, तहसील/थाना, जनपद व राज्य)	
3	प्रणाली व आपूर्ति की वोल्टेज (क्या ई.एच.टी./एच.टी./एलटी लाईन, उपस्टेशन /उत्पादक स्टेशन/ उपभोक्ता की संस्थापना/सेवा लाईनें/अन्य संस्थापनाएं हैं)	
4	प्रभारी अधिकारी का पदनाम (जिसके कार्य क्षेत्र में दुर्घटना हुई है)	
5	जिसके परिक्षेत्र में दुर्घटना हुई है, उसके स्वामी/ऊर्जा के उपभोक्ता का नाम	
6	पीड़ित व्यक्ति/यों का विवरण	

(क) मानव						
क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	पीड़ित का लिंग	पूरा डाक का पता	अनुमानित उम्र	घातक/ अघातक

(ख) पशु					
क्र.सं.	पशुओं का विवरण	संख्या (ए)	स्वामी (यों) का/के नाम	स्वामी (यों) का/ के पता/पते	घातक/ अघातक

7	यदि पीड़ित कर्मचारी है/हैं : (क) ऐसे व्यक्ति (यों) का/के पदनाम (ख) कार्य, यदि कोई है, का संक्षिप्त विवरण (ग) क्या ऐसे व्यक्ति/यों को उस कार्य करने की अनुमति थी?	
8.	यदि पीड़ित अनुज्ञापित ठेकेदार का/के कर्मचारी है/हैं (क) क्या पीड़ित/तों के पास विद्युत कार्य करने का अनुमति पत्र या नियम-45 के अधीन पर्यवेक्षक द्वारा जारी सक्षमता प्रमाण पत्र था ? यदि हां तो जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम जारी करने की तिथि व संख्या दें। (ख) पीड़ित/तों को कार्य नियत करने वाले व्यक्ति का नाम व पदनाम	
9	यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में दुर्घटना हुई है, तो क्या कार्य का अनुमति पत्र (पी.टी.डब्ल्यू.) लिया गया था ?	
10	आघात के स्वभाव व विस्तार का पूर्ण विवरण दें, उदाहरणार्थ-शरीर के किसी भाग की घातक/ निःशक्तता स्थायी या अस्थायी या जलना या अन्य आघात घातक दुर्घटना की स्थिति में, क्या पोस्ट मार्टम किया गया?	
11	दुर्घटना के कारणों का विस्तृत वर्णन (इस प्रपत्र के साथ संलग्न कर एक अलग शीट में दिया जाये)	
12	दुर्घटना होने के तुरन्त उपरान्त, प्राथमिक उपचार, चिकित्सा प्रदान करने के संबंध में की गई कार्यवाही (विवरण दें)	
13	क्या दुर्घटना के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट व संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित कर दिया गया है? (यदि हां, तो विवरण दें)	
14	संभावित अवधि तक दुर्घटना से संबंधित साक्ष्य संरक्षित रखने हेतु उठाये गये कदम।	
15	मृत या घायल व्यक्ति(यों) की सहायता, परिवेक्षण कर रहे व्यक्ति (यों) का/के नाम व पदनाम	
16	दुर्घटना के शिकार व्यक्ति (यों) को दिये गये व उनके द्वारा उपयोग किए गए सुरक्षा उपकरण (उदाहरण के लिए रबर की मैट्स, सुरक्षा पेटी व सीढ़ी इत्यादि)	
17	क्या पृथक कारक रिववेस व अन्य खण्डकारी युक्तियों का उपयोग खण्ड से पृथक होने के लिये किया गया था ? क्या कार्य स्थल पर कार्यरत खण्ड को अर्थ किया गया था ?	
18	क्या जीवित लाईनों पर कार्य अधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा लिया जा रहा था? यदि हां तो ऐसे व्यक्ति (यों) के नाम व पदनाम दिये जायें।	
19	क्या जो व्यक्ति विद्युतीय दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उन्हें कृत्रिम श्वसन उपचार दिया गया था ? यदि हां तो इसे त्यागने से पहले यह कितने समय तक जारी रखा गया ?	

20	दुर्घटना के समय उपस्थित व इसके साक्षी व्यक्तियों के नाम व पदनाम	
21	कोई अन्य सूचना टिप्पणी	

स्थान :

समय :

दिनांक :

हस्ताक्षर :

पदनाम :

रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का पता :

अधिसूचना

अप्रैल 09, 2007

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2007

सं0 एफ-(9)14/आर.जी./यू.ई.आर.सी./2007/33 विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (एच) के साथ पठित धारा 181 में खण्ड (जेड पी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन करते हुए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

अध्याय 1-सामान्य

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारम्भ :

- (1) यह विनियम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2007 कहलाएगा।
- (2) इन विनियम का विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह विनियम, सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

1.2 परिचय :

राज्य ग्रिड कोड (एस.जी.सी.) विद्युत के उत्पादन व आपूर्ति में स्वस्थ स्पर्धा को सुगम बनाते हुए, सर्वाधिक कुशल, विश्वसनीय, मितव्ययी व सुरक्षित तरीके से उत्तरी क्षेत्र ग्रिड प्रणाली के एक भाग, अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली (आई.ए.एस.टी.एस.) को नियोजित, विकसित, अनुरक्षित व परिचालित करने के लिए अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में विभिन्न अभिकरणों व भागीदारों द्वारा अपनाये जाने वाले नियम, मार्गदर्शक व मानक नियत करता है।

1.3 उद्देश्य :

एस.जी.सी., तकनीकी नियमों के एक सेट को एक साथ लाता है तथा अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली (आई.ए.एस.टी.एस.) का उपयोग कर रही या इससे जुड़ी सभी यूटिलिटीज को परिवेष्टित करता है तथा निम्नलिखित उपबन्धित करता है:-

- (1) ऐसे सिद्धान्तों व प्रक्रियाओं का प्रलेखन जो अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली (आई.ए.एस.टी.एस.) में विभिन्न उपयोगकर्ताओं के मध्य व साथ ही क्षेत्रीय व राज्य लोड डिस्पैच केन्द्रों के मध्य संबंधों को परिभाषित करते हैं।
- (2) भित्तव्ययी व विश्वसनीय राज्य ग्रिड के परिचालन, अनुरक्षण, विकास व नियोजन का सरलीकरण करना।
- (3) आई.ए.एस.टी.एस. के सभी उपयोग कर्ताओं पर लागू आई.ए.एस.टी.एस. के प्रचालन के सामान्य आधार को परिभाषित करते हुए विद्युत फायदाप्रद व्यापार का सरलीकरण करना।

1.4 परिधि व लागू होने की तिथि :

- (1) ये विनियम उन सभी पक्षों पर लागू होंगे जो आई.ए.एस.टी.एस. के साथ जुड़ते हैं या उसका उपयोग करते हैं या एस.एल.डी.सी. सहित वे जो, एस.जी.सी. में परिभाषित सिद्धान्तों व प्रक्रियाओं, जहां तक वे उस पक्षकार पर लागू होते हैं, का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।
- (2) आई.ए.एस.टी.एस. की संरचना के एक भाग के रूप में पारेषण अनुज्ञापी तथा इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि पर आई.ए.एस.टी.एस. से संयोजित उपयोगकर्ता को इन विनियमों के अधीन निम्नलिखित अपेक्षाओं के साथ अनुपालन हेतु अधिकतम एक वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी :—
 - (i) विनियम 3.6 के अनुसार एक संयोजन अनुबन्ध में शामिल होना।
 - (ii) विनियम 3.9.2 व 3.9.3 के अनुसार संरक्षण प्रणाली उपलब्ध कराना।
 - (iii) विनियम 3.12 के अनुसार संचार सुविधाएं उपलब्ध कराना।
 - (iv) विनियम 3.13 के अनुसार प्रणाली रिकॉर्डिंग उपकरण उपलब्ध कराना।
 - (v) विनियम 3.16(1) के अनुसार सिंगल लाईन डायग्राम विकसित करना।
 - (vi) विनियम 3.17(2) के अनुसार साईट का कॉमन ड्रॉइंग्स विकसित करना।
 - (vii) विनियम 6.1 के अनुरूप विकसित मीटरिंग कोड के अनुसार मीटर्स का अधिष्ठापन एवं प्रचालन।
- (3) इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार, फ्री गवर्नर एक्शन से संबंधित उपबन्धों की लागू होने की तिथि, अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (एच) के अधीन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड में उपबंधित सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप होगी।
- (4) खुली पहुंच का उपयोग कर रहे व्यक्ति जो आई.ए.एस.टी.एस. से जुड़े हैं व/या इसका उपयोग करते हैं, आयोग द्वारा यदि कोई पारेषण खुली पहुंच विनियम तथा वितरण खुली पहुंच अधिनियम अधिसूचित किया गया है, का अनुपालन करेंगे।

1.5 भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता की संरचना :

इस एस.जी.सी. में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

अध्याय I: सामान्य

यह अध्याय बृहत रूप से इन विनियमों की परिधि व इनके लागू किये जाने तथा ग्रिड समन्वय समिति की संरचना व भूमिका को परिभाषित करती है।

अध्याय II: अन्तर-राज्यिक पारेषण के लिए योजना संहिता

यह अध्याय थोक ऊर्जा अन्तरण तथा सहबद्ध आई.ए.एस.टी.एस. की योजना और विकास में अंगीकार की जाने वाली नीतियों का उपबन्ध करता है। योजना संहिता भार पूर्वानुमान, उत्पादन उपलब्धता के लिए ऊर्जा प्रणाली के योजना अभिकरणों तथा विभिन्न भागीदारों के बीच अपेक्षित विस्तृत जानकारी आदान-प्रदान तथा भावी

वर्षों का अध्ययन करने के लिए ऊर्जा प्रणाली योजना आदि को अभिलक्षित करती है। योजना संहिता, योजना प्रक्रिया के दौरान अंगीकार किये जाने वाले विभिन्न मानदण्डों को अनुबद्ध करता है।

अध्याय III: संयोजन शर्तें

यह अध्याय प्रणाली से संबंधित किसी भी अभिकरण या आई.ए.एस.टी.एस. का संयोजन चाहने वाले द्वारा प्रणाली की एकरूपता तथा गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अनुपालन किये जाने वाली न्यूनतम तकनीकी और डिजाइन मानदण्डों को विनिर्दिष्ट करता है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

(ए) आई.ए.एस.टी.एस. के संयोजन के लिए प्रक्रिया।

(बी) स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची।

अध्याय IV: राज्य ग्रिड के लिए प्रचालन संहिता

यह अध्याय ग्रिड प्रचालन को दक्ष, सुरक्षित तथा विश्वस्त बनाए रखने के लिए प्रचालनात्मक युक्ति विहित करता है तथा इसमें निम्नलिखित खण्ड हैं:-

(ए) प्रचालन नीति।

(बी) प्रणाली सुरक्षा पहलू

यह अनुभाग उत्पादन कंपनियों और ग्रिड के सभी राज्यीय संघटकों द्वारा अनुसरण किये जाने वाले साधारण सुरक्षा पहलुओं को विहित करता है।

(सी) प्रचालनात्मक प्रयोजनों के लिए मांग प्राक्कलन

यह खण्ड विभिन्न संघटकों द्वारा दिन/सप्ताह/मास/वर्ष आगे के लिए अपनी प्रणाली के लिए मांग द्वारा प्राक्कलन विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन करता है जो प्रचालनात्मक योजना के लिए उपयोग किया जाएगा।

(डी) मांग प्रबन्ध

यह खण्ड फ्रीक्वेन्सी और कम उत्पादन में कृत्यों के रूप में प्रत्येक राज्य, संघटक द्वारा मांग नियंत्रण के लिए स्वीकार किये जाने वाली पद्धति को विहित करता है।

(ई) आवधिक रिपोर्ट

यह खण्ड फ्रीक्वेन्सी प्रोफाईल, वोल्टेज प्रोफाईल इत्यादि जैसे राज्य ग्रिड के प्रचलनात्मक पैरामीटरों की रिपोर्टिंग के लिए विभिन्न उपबन्धों की व्याख्या करता है।

(एफ) प्रचालनात्मक संपर्क

यह खण्ड सामान्य प्रचालन और/या ग्रिड के संबंध में जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए अपेक्षा विहित करता है।

(जी) आउटेज योजना

यह खण्ड आउटेज के लिए प्रक्रिया विहित करता है।

(एच) वसूली प्रक्रिया

इस खण्ड में ब्लैक स्टार्ट तथा द्वीप समूह आदि को पुनः आरम्भ करने के लिए प्रमुख ग्रिड बाधाओं का अनुसरण करने के लिए स्वीकार किये जाने वाली प्रक्रियाएं अन्तर्विष्ट हैं।

(आई) घटना की जानकारी

यह खण्ड ऐसी प्रक्रियाओं को उपदर्शित करता है जिनके माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट की जाती है और जानकारी का आदान-प्रदान किया जाता है।

अध्याय V: अनुसूचीकरण तथा प्रेषण संहिता

यह खण्ड आई.ए.एस.जी.एस., अन्य उपयोगकर्ताओं व राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.) के बीच जानकारी देने की पद्धति के दैनिक आधार पर अन्तर-राज्यिक उत्पादन केन्द्र (एस.जी.एस.) जिसमें कम्प्लीमेंटरी वाणिज्यिक तंत्र

भी सम्मिलित है, के उत्पादन का अनुसूचीकरण तथा प्रेषण करने के लिए स्वीकार की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है।

अध्याय VI: मीटरिंग संहिता

मीटरिंग कोड, संयोजन बिन्दु पर उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान किये जाने वाले वाणिज्यिक व परिचालनक उद्देश्य के लिए मीटरों में संस्थापन व परिचालन हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं व मानकों के विकास हेतु उपबन्ध करता है।

अध्याय VII: अन्तर-राज्यीय आदान-प्रदान

यह खण्ड अन्तर-राज्यीय लिंकों के प्रचालन के लिए विशेष प्रतिफल से सम्बन्धित है।

अध्याय VIII: एस.जी.सी. का प्रबन्धन

यह अध्याय समीक्षा/संशोधन हेतु प्रक्रिया व एस.जी.सी. के प्रबन्धन से संबंधित है।

1.6 अनुपालन :

- (1) इन विनियमों के अध्याय-II, अध्याय-III व अध्याय-VI के उपबन्धों के साथ तथा ऐसे उपबन्धों के अधीन विकसित नियमों व प्रक्रियाओं के साथ पारेषण प्रणाली अनुज्ञप्तिधारियों व उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुपालन के अनुवीक्षण हेतु राज्य पारेषण यूटिलिटी उत्तरदायी होगी।

राज्य पारेषण यूटिलिटी किसी उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध अनुचित भेदभाव नहीं करेगा या अनुचित प्राथमिकता प्रदान नहीं करेगा।

- (2) राज्य मार प्रेषण केन्द्र, इन विनियमों के अध्याय-IV व अध्याय-V के उपबन्धों के साथ तथा ऐसे उपबन्धों के अधीन विकसित नियमों व प्रक्रियाओं के साथ पारेषण प्रणाली अनुज्ञप्तिधारियों व उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुपालन के अनुवीक्षण हेतु उत्तरदायी होगा।

राज्य पारेषण केन्द्र अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध अनुचित भेदभाव नहीं करेगा या अनुचित प्राथमिकता प्रदान नहीं करेगा।

- (3) राज्य ग्रिड कोड के उपबन्धों व/या ऐसे उपबन्धों के अधीन विकसित नियमों व प्रक्रियाओं के लगातार अपालन करने पर ऐसे मामलों की आयोग को रिपोर्ट की जाएगी।
- (4) उत्तर क्षेत्रीय मार प्रेषण केन्द्र द्वारा किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य के किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादक कम्पनी (अन्तरप्रदेशीय पारेषण प्रणाली के अतिरिक्त अन्य) या राज्य के उपस्टेशनों को जारी सभी निर्देश राज्य मार प्रेषण केन्द्र के माध्यम से जारी किये जाएंगे तथा राज्य मार प्रेषण केन्द्र यह सुनिश्चित करेगा कि सभी निर्देश, अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादक कम्पनी या उपस्टेशन के साथ उचित रूप से अनुपालित किये जाएं।
- (5) राज्य मार प्रेषण केन्द्र एक राज्य घटक को ऐसे निर्देश दे सकता है तथा ऐसा पर्यवेक्षण व अनुवीक्षण करेगा जैसाकि समेकित ग्रिड परिचालन सुनिश्चित करने हेतु व ऊर्जा प्रणाली के परिचालन में अधिकतम मितव्ययता व दक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा।
- (6) ऊर्जा प्रणाली के परिचालन से जुड़े प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता इस विनियम के उपविनियम (5) के अधीन राज्य मार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करेगा।
- (7) यदि विद्युत की गुणवत्ता या राज्य ग्रिड के सुरक्षित व एकीकृत परिचालन के सन्दर्भ में या इस विनियम के उपविनियम (5) के अधीन दिये गये निर्देश के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसे निर्णय के लिए आयोग को संदर्भित किया जाएगा।

आयोग का निर्णय लंबित रहने पर राज्य मार प्रेषण केन्द्र के निर्देश का पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या उपयोगकर्ता द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

- (8) उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राज्य ग्रिड संहिता के उपबन्धों या इन उपबन्धों के अधीन विकसित नियमों व प्रक्रियाओं के अनुपालन में लगातार विफल रहने पर ऐसे उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के संयंत्र व/या उपकरण के विच्छेदन का कारण होगा।

- (9) इस विनियम में समावेशित कुछ भी, किसी प्रकार से राज्य ग्रिड संहिता के उपबन्धों या इन उपबन्धों के अधीन विकसित नियमों व प्रक्रियाओं के, उपयोगकर्ताओं व पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुपालन के अनुवीक्षण व प्रवर्तन की आयोग को प्रदत्त शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा।

1.7 फ्री गवर्नर कार्यवाही :

- (1) सभी थर्मल व हाइड्रो (शून्य पॉइंज के अतिरिक्त) उत्पादक इकाईयां, आयोग द्वारा पृथक् रूप, अधिसूचित तिथि से फ्री गवर्नर कोड में परिचालित होगी।
- (2) उपरोक्त से कोई छूट केवल आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए संबंधित राज्य घटक/अभिकरण अग्रिम रूप से वाद फाईल करेंगे।
- (3) गैस टर्बाइन/संयुक्त चक्र ऊर्जा संयंत्र व न्यूक्लियर पावर स्टेशन, स्थिति को आयोग द्वारा समीक्षा किये जाने तक 3.10(3), 3.10(4), 4.2(5), 4.2(6), 4.2(7) व 4.2(8) विनियमों से छूट प्राप्त होंगे।

1.8 रिएक्टिव ऊर्जा एक्सचेंजों के लिए प्रभार/भुगतान :

रिएक्टिव ऊर्जा एक्सचेंजों के प्रभार/भुगतान हेतु दर, विनियम 5.6 में विनिर्दिष्ट योजना के अनुसार, ऐसी तिथि से प्रभावित व पैसे/के0वी0ए0आर0एच0 में ऐसी दर पर होगी व उसके पश्चात् प्रतिवर्ष पैसे/के0वी0ए0आर0एच0 की ऐसी दर से बढ़ेगी जैसा कि इस निमित्त आयोग द्वारा वर्णित की जाए।

1.9 छूट :

एस.जी.सी. के उपबन्धों से कोई छूट, केवल आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होगी जिसके लिए अभिकरण को अग्रिम रूप से आयोग के समक्ष याचिका फाईल करनी होगी।

1.10 ग्रिड संहिता के अधीन बाध्यता :

इन विनियमों के उपबन्ध, अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (एच) के अधीन केन्द्रीय आयोग द्वारा जारी ग्रिड संहिता के अभिवर्णन में हैं न कि अल्पीकरण में। दोनों के मध्य किसी विवाद की स्थिति में दूसरे प्रचलित रहेंगे। राज्य घटक/एस0एल0डी0सी0/अन्य अभिकरण, जब तक उनसे संबंधित हैं, ग्रिड संहिता के उपबन्धों का अनुपालन करेंगे।

1.11 ग्रिड समन्वय समिति :

- (1) ग्रिड समन्वय समिति का गठन, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से 30 (तीस) दिन के भीतर राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा किया जाएगा।
- (2) ग्रिड समन्वय समिति निम्नलिखित मामलों के लिए उत्तरदायी होगी :
 - (i) इन विनियमों व इन विनियमों के अधीन विकसित नियमों व प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन को सुगम बनाना।
 - (ii) इन विनियमों व इन विनियमों के अधीन विकसित नियमों व प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के मार्ग में उत्पन्न होने वाले मामलों के उपचारक उपायों का आंकलन व संस्तुति करना।
 - (iii) अधिनियम व इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार राज्य ग्रिड संहिता की समीक्षा करना, तथा
 - (iv) अन्य ऐसे मामले जो समय-समय पर आयोग द्वारा निर्देशित किये जाएं।
- (3) ग्रिड समन्वय समिति में निम्नलिखित सदस्यों का समावेश होगा :
 - (i) राज्य पारेषण यूटिलिटी से एक सदस्य।
 - (ii) राज्य भार प्रेषण केन्द्र से एक सदस्य।
 - (iii) राज्य व निजी स्वामित्व की उत्पादक कम्पनियों के प्रतिनिधित्व हेतु प्रत्येक का एक सदस्य।
 - (iv) राज्य पारेषण यूटिलिटी से अन्यथा राज्य में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधित्व हेतु एक सदस्य।
 - (v) राज्य में राज्य के स्वामित्व वाले वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधित्व हेतु एक सदस्य।

- (vi) राज्य में निजी स्वामित्व वाले वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधित्व हेतु एक सदस्य।
- (vii) राज्य में विद्युत का व्यापार करने वालों का एक प्रतिनिधि।
- (viii) पश्चिम क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र के प्रतिनिधित्व हेतु एक सदस्य, तथा
- (ix) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें आयोग नामित करें।

परन्तु, समिति का अध्यक्ष, राज्य पारेषण यूटिलिटी से सदस्य होगा, ग्रिड समन्वय समिति का संयोजक, राज्य भार प्रेषण केन्द्र से सदस्य होगा। साथ ही यह भी कि, राज्य पारेषण यूटिलिटी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र से सामन्जस्य कर ग्रिड समन्वय समिति की कार्यप्रणाली को सुगम बनाएगी व प्रबधित करेगी।

(4) ग्रिड समन्वय समिति के सदस्यों का चयन निम्नलिखित ढंग से किया जाएगा :

- (i) राज्य पारेषण यूटिलिटी का सम्बन्धित निदेशक, जिसके पास राज्य पारेषण यूटिलिटी के तकनीकी कार्यकलाप देखने का उत्तरदायित्व है, उपरोक्त उपविनियम (3) के खण्ड (ए) में संदर्भित सदस्य होगा।
- (ii) उपरोक्त उपविनियम (3) के खण्ड (बी) में संदर्भित सदस्य राज्य भार प्रेषण केन्द्र का मुखिया होगा जो महाप्रबन्धक के पद से नीचे का व्यक्ति नहीं होगा।
- (iii) उपरोक्त उपविनियम (3) के खण्ड (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी) व (एच) में संदर्भित सदस्य, अपने संबंधित संगठन द्वारा नामित किये जाएंगे, जो संगठन, राज्य में सभी ऐसे संगठनों के मध्य से चक्रावर्तन अनुसार चयनित किये जाएंगे। ऐसे चक्रावर्तन अनुसार चुने गये प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल एक (1) वर्ष होगा।

परन्तु उपरोक्त समिति में प्रत्येक संगठन द्वारा नामित सदस्य अपने सम्बन्धित संगठन में एक वरिष्ठ पद सम्माल रहा व्यक्ति होना चाहिए।

1.12 एस०एल०डी०सी० का उत्तरदायित्व :

राज्य भार प्रेषण केन्द्र, अधिनियम व इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन निर्धारित कार्यों को एक स्वतंत्र एवं भेदभाव रहित तरीके से निष्पादित करेगा।

किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उपधारा (2) के प्रथम उपबन्ध के अनुसार राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को परिचालित किये जाने की अवस्था में, उपर्युक्त तरीकों से कार्य निष्पादन हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र को पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाएगी।

1.13 राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विकसित की जाने वाली प्रक्रियायें :

इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन कार्य निष्पादन में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विकसित की गयी प्रक्रियायें व कार्यविधियां, जहां-कहीं लागू हों, निम्नलिखित पहलुओं हेतु स्पष्ट प्रावधान करेंगी :

- (i) एस०एल०डी०सी०, ए०एल०डी०सी० व राज्य घटकों की भूमिका व उत्तरदायित्व।
- (ii) एस०एल०डी०सी०, ए०एल०डी०सी० व राज्य घटकों के मध्य संवाद सुविधाएं।
- (iii) एस०एल०डी०सी०, ए०एल०डी०सी० व राज्य घटकों के मध्य सूचना प्रवाह।
- (iv) राज्य भार प्रेषण केन्द्र या आयोग द्वारा उचित समझा गया कोई अन्य पहलू।

किन्तु ऐसी प्रक्रियायें राज्य घटकों के साथ परामर्श कर विकसित की जाएंगी तथा इस एस०जी०सी० की अपेक्षाओं के साथ अनुपालन हेतु एस०जी०सी० की अपेक्षाओं के साथ अनुपालन हेतु एस०जी०सी० के साथ सुसंगत होंगी, साथ ही यह भी कि ऐसी प्रक्रियायें तीन (3) माह के भीतर अनुमोदन हेतु आयोग को प्रस्तुत की जाएंगी।

1.14 परिभाषाएं :

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (ए) 'अधिनियम' से, संशोधनों को सम्मिलित कर विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है।
- (बी) 'स्वचालित वोल्टेज रेग्युलेटर' से उत्पादन टर्मिनलों पर मापित उत्पादन इकाईयों की वोल्टेज नियंत्रित करने के लिए निरन्तर कार्यरत स्वचालित एक्साइटेशन कंट्रोल प्रणाली अभिप्रेत है।
- (सी) 'लामार्थी' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका आई.ए.एस.जी.एस./आई.एस.जी.एस. या खुली पहुंच वाले उपयोग कर्ताओं सहित बाइलेट्रल एक्सचेंज में हिस्सेदारी है।
- (डी) 'ब्लैक स्टार्ट प्रक्रिया' से आशिक या पूर्ण ब्लैक आउट से वसूली के लिए आवश्यक प्रक्रिया अभिप्रेत है।
- (ई) थोक ऊर्जा पारेषण करार (बी.पी.टी.ए.) से पारेषण सेवाओं के उपबंध के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और दीर्घकालिक ग्राहक के बीच वाणिज्यिक करार अभिप्रेत है।
- (एफ) 'बी.आई.एस.' से भारतीय मानक ब्यूरो अभिप्रेत है।
- (जी) 'कैपेसिटर' से रिएक्टिव ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रदान की गयी विद्युत सुविधा अभिप्रेत है।
- (एच) 'आयोग' से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है।
- (आई) 'संयोजन करार' से अन्तर राज्यिक पारेषण प्रणाली के संयोजन व/या उपयोग से सम्बन्धित उल्लिखित निबंधनों के लिए करार अभिप्रेत है।
- (जे) 'संयोजन बिन्दु' से वह बिन्दु अभिप्रेत है जिस पर उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का संयंत्र व/या उपकरण अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली को जोड़ते हैं।
- (के) 'संगठक' से एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य का समझा गया वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आई.ए.एस.जी.एस. वाली उत्पादक कम्पनी, राज्य पारेषण यूटिलिटी, राज्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, खुली पहुंच वाले अभिकर्ता अभिप्रेत हैं।
- (एल) 'मांग' से मेगावाट में सक्रिय ऊर्जा तथा जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो एम.वी.ए.आर. में रिएक्टिव ऊर्जा की मांग अभिप्रेत है।
- (एम) 'प्रेषण अनुसूची' से एक्स ऊर्जा संयंत्र एम.डब्ल्यू. तथा उत्पादन केन्द्र का एम.डब्ल्यू.एच.आउटपुट अभिप्रेत है जिसका समय-समय पर ग्रिड को भेजे जाने के लिए अनुसूचीकरण किया जाना होता है।
- (एन) 'डी.एफ./डी.टी. रिले' से ऐसा रिले अभिप्रेत है जो सिस्टम फ्रिक्वेन्सी (ओवरटाईम) के परिवर्तन की दर के विनिर्दिष्ट सीमा से ऊपर जाने पर परिचालित होता है तथा लोड शैडिंग प्रारम्भ करता है।
- (ओ) 'व्यवधान रिकॉर्डर' से, किसी घटना के दौरान सिस्टम पैरामीटर के पूर्व चयनित डिजिटल व एनेलॉग मूल्यों का बर्ताव रिकॉर्ड करने की युक्ति अभिप्रेत है।
- (पी) 'डाटा अर्जन प्रणाली (डी.ए.एस.)' से अवस्थान पर रिले/उपस्करों/प्रणाली पैरामीटरों को समय पर ऑपरेशन के अनुक्रम के अभिलेख के लिए प्रदान की गयी युक्ति अभिप्रेत है।
- (क्यू) 'निकासी अनुसूची' से ऐसा एक्स ऊर्जा संयंत्र एम.डब्ल्यू. अभिप्रेत है जिसे आई.ए.एस.जी.एस. या आई.एस.जी.एस. से वितरण अनुज्ञप्तिधारी या खुली पहुंच वाले उपयोगकर्ता, प्राप्त करने हेतु नियत हैं। इसमें समय-समय पर द्विपक्षीय आदान-प्रदान सम्मिलित है।
- (आर) 'हकदारी' से आई.एस.जी.एस./आई.एस.जी.एस. की संस्थापित क्षमता/आउटपुट क्षमता में लामार्थी का अंश (मेगावाट तथा एम.डब्ल्यू.एच. में) अभिप्रेत है।
- (एस) 'घटना' से ग्रिड पर अनुसूचित या आयोजनाबद्ध घटना अभिप्रेत है जिसमें त्रुटि, दुर्घटना तथा ब्रेकडाउन सम्मिलित हैं।
- (टी) 'घटना लॉगर (ई.एल.)' से घटना के दौरान अवस्थान पर रिले/उपस्करों के समय प्रचालन के क्रम को अभिलिखित करने के लिए प्रदान की गयी युक्ति अभिप्रेत है।
- (यू) 'एक्स ऊर्जा संयंत्र' से सहायक खपत तथा ट्रांसफॉर्मेशन हानियों में कटौती करने के पश्चात् उत्पादन केन्द्र का कुल एम.डब्ल्यू./एम.डब्ल्यू.एच. आउटपुट अभिप्रेत है।

- (वी) 'त्रुटिनिर्धारक' से, उस दूरी को जिस पर खराब लाईन पड़ी हुई हो, मापने/उपदर्शित करने के लिए पारेषण लाईन के अंत में प्रदान की गयी युक्ति अभिप्रेत है।
- (डब्लू) 'लचकदार प्रत्यावर्ती करेन्ट पारेषण' (एफ.ए.सी.टी.) से वह सुविधा अभिप्रेत है जो विनियमित की जाने वाली ए.सी. लाईनों पर ऊर्जा को प्रवाह करने में समर्थ बनाती है, लूपप्रवाह, लाईन लोडिंग आदि को नियंत्रित करती है।
- (एक्स) 'तात्कालिक उपाय' से ऐसी घटना अभिप्रेत है जो ऐसे अभिकरणों के नियंत्रण से परे है जो पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते हैं या जो उद्यम की युक्तियुक्त मात्रा के साथ देखे नहीं जा सकते हैं या निवारित नहीं किये जा सकेंगे तथा जो सारवान रूप से या तो अभिकरण द्वारा प्रभावित होते हैं या जो निम्नलिखित तक सीमित हैं:-
- दैवीय कार्य, प्राकृतिक प्रकोप जिसमें बाढ़, सूखा, भूकम्प तथा महामारी सम्मिलित हैं।
 - कोई सरकारी, घरेलू या विदेशी कार्य जिसमें घोषित या अघोषित युद्ध, पूर्विकताएं, संगरोध, नौकावरोध।
 - बलवे या सिविल युद्ध।
 - ग्रिड की असफलता जो अन्तर्वलित अभिकरण के कारण न हो।
- (वाई) 'फोर्सर्ड आउटेज' से उत्पादन यूनिट या किसी पारेषण सुविधा का ऐसा आउटेज अभिप्रेत है जो त्रुटि या किसी अन्य कारण से हो जिसकी योजना बनाई गयी हो।
- (जेड) 'उत्पादन यूनिट' से ऐसा विद्युत उत्पादन यूनिट अभिप्रेत है जो उस ऊर्जा केन्द्र (संयोजन बिन्दु तक) जो उस टर्बो जनरेटर में प्रचालन से विशेषकर संबंधित हो, पर सभी संयंत्रों व साधित्रों के साथ-साथ ऊर्जा केन्द्र के भीतर टर्बाइन से जुड़ा हो।
- (एए) 'अच्छी उपयोगिता पद्धति' से कोई ऐसी प्रैक्टिस, पद्धति व कार्य अभिप्रेत है जो उस सुसंगत अवधि के दौरान विद्युत उपयोगिता उद्योग के महत्वपूर्ण भाग में लगी हुई है या अनुमोदित है जिससे युक्तियुक्त लागत पर अच्छे परिणाम की आशा की जाती है जिसमें अच्छी व्यवसाय पद्धति, विश्वसनीयता, सुरक्षा तथा शीघ्रता सम्मिलित हो।
- (बीबी) 'गवर्नर ड्रूप' से गवर्नर के प्रचालन के सम्बन्ध में 'गवर्नर ड्रूप' से प्रणाली फ्रीक्वेंसी में प्रतिशतता ड्राप अभिप्रेत है जो शून्य से पूर्ण भार के उसके आउटपुट में परिवर्तन करने के लिए फ्री गवर्नर के अधीन उत्पादन केन्द्र को मारित करेगा।
- (सीसी) 'उच्च टेन्शन या एच.टी.' से भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ए. वी.) के अधीन 'उच्च' या 'अतिउच्च' के रूप में परिभाषित सभी वोल्टेज व तत्समान वोल्टेज श्रेणियां, जैसी कि अधिनियम की धारा 185 की उपधारा (2) के खण्ड (सी) के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाएं, अभिप्रेत है।
- (डीडी) 'स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (आई.पी.पी.)' से ऐसी उत्पादन कंपनियां अभिप्रेत हैं, जो केन्द्रीय/राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित नहीं हैं।
- (ईई) 'अन्तर-राज्यिक उत्पादन केन्द्र (आई.एस.जी.एस.)' से ऐसे केन्द्रीय/अन्य उत्पादन केन्द्र अभिप्रेत हैं जिसमें दो या अधिक राज्यों का अंश है तथा जिनका अनुसूचीकरण आर.एल.डी.सी. द्वारा किया जाना है।
- (एफएफ) 'अन्तर-राज्यिक उत्पादक स्टेशन (आई.ए.एस.जी.एस.)' से एक राज्य/अन्य उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है जो एल.ए.एस.टी.एस. से जुड़ा है, का उपयोग करता है तथा जिसका अनुसूचीकरण एस.एल.डी.सी. द्वारा किया जाना है।
- (जीजी) 'अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली (आई.एस.टी.एस.)' के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-
- एक राज्य के राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य के राज्य क्षेत्र को मुख्य पारेषण लाईन के माध्यम से विद्युत के प्रवहण के लिए कोई प्रणाली।

- (ii) किसी मध्यवर्ती राज्य के राज्यक्षेत्र में से होकर ऊर्जा का प्रवहण तथा ऐसे राज्य के भीतर प्रवहण जो ऊर्जा के ऐसे अन्तर-राज्यिक पारेषण के आनुषांगिक हैं।
- (iii) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा निर्मित, उसके स्वामित्वाधीन उसके द्वारा प्रचालित, अनुरक्षित या नियंत्रित प्रणाली पर ऊर्जा का पारेषण।
- (एचएच) 'अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली (आई.एस.टी.एस.)' से अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली से इतर, विद्युत के पारेषण हेतु कोई प्रणाली अभिप्रेत है तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-
- (i) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर मुख्य लाईन के माध्यम से विद्युत के प्रवहण के लिए कोई प्रणाली।
- (ii) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा निर्मित, उसके स्वामित्वाधीन, उसके द्वारा प्रचालित, अनुरक्षित या नियंत्रित प्रणाली पर ऊर्जा का पारेषण।
- किन्तु, पारेषण प्रणाली व वितरण प्रणाली तथा उत्पादक स्टेशन व पारेषण प्रणाली के मध्य विभक्ति के बिन्दु की परिभाषा, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73 के खण्ड (बी) के अधीन प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित विनियमों के उपबन्धों द्वारा मार्गदर्शित होगी।
- (आईआई) 'आई.ई.सी.' से अन्तर्राष्ट्रीय इलैक्ट्रो तकनीकी आयोग अभिप्रेत है।
- (जेजे) 'भार' से उपयोगिता/संस्थापन द्वारा उपयोग की गयी मेगावाट/एम.डब्ल्यू.एच. अभिप्रेत है।
- (केके) 'लो टेन्शन या एल.टी.' से भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ए.वी.) के अधीन 'उच्च' या 'अतिउच्च' के रूप में परिभाषित को छोड़कर अन्य सभी वोल्टेज तथा अधिनियम की धारा 185 की उपधारा (2) के खण्ड (सी) के अनुसार विनिर्दिष्ट रूप में तत्समान वोल्टेज वर्गीकरण, अभिप्रेत है।
- (एलएल) 'अधिकतम निरन्तर रेटिंग (एम.सी.आर.)' से उस उत्पादन यूनिट की सामान्य रेटिंग पूर्ण भार एक डब्ल्यू आउटपुट क्षमता अभिप्रेत है जो विनिर्दिष्ट शर्तों के आधार पर जारी रखी जा सकती है।
- (एमएम) 'राष्ट्रीय ग्रिड' से देश का ऐसा सम्पूर्ण अन्तरसंयोजित विद्युत ऊर्जा नेटवर्क अभिप्रेत है जो राष्ट्रीय ग्रिडों के अन्तर-संयोजन के पश्चात् अन्तर्वलित होगा।
- (एनएन) 'कुल निकासी अनुसूची' से कुल पारेषण हानियों (प्राक्कलित) में कटौती करने के पश्चात् लाभार्थी की निकासी अनुसूची अभिप्रेत है।
- (ओओ) 'प्रचालन' से प्रणाली के प्रचालन से संबंधित अनुसूचित या योजनाबद्ध कार्यवाही अभिप्रेत है।
- (पीपी) 'प्रचालन रेंज' से फ्रीक्वेन्सी और वोल्टेता की ऐसी प्रचालन रेंज अभिप्रेत है जो प्रचालन कोड के अधीन विनिर्दिष्ट है।
- (क्यूक्यू) 'राज्य पूल लेखा' से (i) उन अनुसूचित विनियम (राज्य यू.आई. लेखा) से संबंधित भुगतान या (ii) रिएक्टिव एनर्जी विनियम जैसी स्थिति हो, के लिए लेखा, अभिप्रेत है।
- (आरआर) 'रिएक्टर से ऐसी विद्युत सुविधा अभिप्रेत है जो विशेषकर रिएक्टिव ऊर्जा को समामेलित करने के लिए डिजाइन की गयी हो।
- (एसएस) 'प्रादेशिक ऊर्जा समिति' से उस क्षेत्र में ऊर्जा प्रणाली के एकीकृत ऑपरेशन को सुकर बनाने के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र हेतु केन्द्रीय सरकार के संकल्प द्वारा स्थापित एक समिति अभिप्रेत है।
- (टीटी) 'आर.पी.सी. सचिवालय' से आर.पी.सी. का सचिवालय अभिप्रेत है।
- (यूयू) 'राज्य ऊर्जा लेखा (एस.ई.ए.)' से 'केपेसिटी प्रभार', 'ऊर्जा प्रभार', 'यू.आई. प्रभार' व 'रिएक्टिव प्रभार' की बिलिंग व निपटान हेतु एक राज्य ऊर्जा लेखा अभिप्रेत है।
- (वीवी) 'राज्य ग्रिड' से राज्य के विद्युत नेटवर्क से जुड़ा संपूर्ण समक्रमिक अभिप्रेत है जो आई.एस.टी.एस., आई.एस.जी.एस. तथा अन्तर राज्य प्रणाली से बना है।

- (डब्लूडब्लू) 'प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र' (आर.एल.डी.सी.) से अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्र अभिप्रेत है।
- (एक्सएक्स) 'शेयर' से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आई.एस.जी.एस. में फायदाग्राही का प्रतिशतता शेयर या जो आई.एस.जी.एस. व इससे फायदा ग्राही के मध्य तय हुआ हो, अभिप्रेत है।
- (वाईवाई) 'एकल लाईन डायग्राम' ऐसा डायग्राम अभिप्रेत है जो एच.वी./ई.एच.वी. साधित्रों का योजनाबद्ध प्रतिरूपण व इसकी संख्या तथा लेबल वाली संख्या को प्रदर्शित करने वाले सभी बाह्य सर्किट संयोजन, अभिप्रेत हैं।
- (जेडजेड) 'साइट कॉमन रेखाचित्र' से प्रत्येक संयोजन बिन्दु के लिए तैयार ऐसा रेखाचित्र अभिप्रेत है जिसमें ले-आउट रेखाचित्र, विद्युत ले-आउट रेखाचित्र, सामान्य संरक्षण/नियंत्रण रेखाचित्र और सामान्य सेवा रेखाचित्र सम्मिलित हैं।
- (एएए) 'स्पनिंग रिजर्व' से 50 एच.जेड. की मानक दर फ्रीक्वेन्सी पर, कुछ रिजर्व मार्जिन के साथ उत्पादक क्षमता अभिप्रेत है जो प्रणाली के समकालिक होती है तथा प्रेषण अनुदेश के अनुसरण में या फ्रीक्वेन्सी ड्राप के प्रत्युत्तर में तत्काल सूचना पर उत्पादन वृद्धि हेतु तैयार रहती है।
- (बीबीबी) 'एस.ई.बी.' से राज्य विद्युत बोर्ड जिसमें राज्य विद्युत विभाग भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है।
- (सीसीसी) 'एस.ई.आर.सी.' से राज्य विद्युत नियामक आयोग, अभिप्रेत है।
- (डीडीडी) 'राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.)' से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्र अभिप्रेत है।
- (ईईई) 'राज्य पारेषण यूटिलिटी (एस.टी.यू.)' से ऐसा बोर्ड या सरकारी कंपनी अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अभिहित की गयी है।
- (एफएफएफ) 'स्टेटिक वी.ए.आर. कंपनसेटर या सिंक्रोनुअस कन्डेन्सर' से उत्पादन के प्रयोजन के लिए या रिएक्टिव ऊर्जा को समामेलित करने के लिए डिजायन की गयी विद्युत सुविधा अभिप्रेत है।
- (जीजीजी) 'क्षेत्र-भार प्रेषण केन्द्र' से, राज्यग्रिड के अनुवीक्षण व नियंत्रण हेतु राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित राज्य भार प्रेषण केन्द्र के कार्यालय व सहायक सुविधाएं जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा भविष्य में स्थापित हो, से अभिप्रेत हैं।
- (एचएचएच) 'समय ब्लॉक' से प्रत्येक 15 मिनट का ब्लॉक अभिप्रेत है जिसके लिए विशेष ऊर्जा मीटर विनिर्दिष्ट विद्युत पैरामीटरों तथा मात्राओं को प्रारंभिक प्रथम समय ब्लॉक व 00.00 घण्टे के साथ अभिलिखित करते हैं।
- (आईआईआई) 'पारेषण योजना मानदण्ड' से पारेषण प्रणाली की योजना या डिजायन के लिए सी.ई.ए.द्वारा जारी नीति, मानक तथा मार्गदर्शक सिद्धान्त अभिप्रेत हैं।
- (जेजेजे) 'अंडर फ्रीक्वेन्सी रिले' से ऐसा रिले अभिप्रेत है जो तब परिचालित होता है जब प्रणाली फ्रीक्वेन्सी एक विनिर्दिष्ट सीमा से नीचे चली जाती है तब यह लोड शेडिंग प्रारम्भ कर देता है।
- (केकेके) 'उपयोगकर्ता' से आई.एस.टी.एस. का उपयोग करने वाले व्यक्ति/अभिकरण को निर्दिष्ट करने के लिए एस.जी.सी. के विभिन्न खण्डों में प्रयुक्त पद अभिप्रेत है जो एस.जी.सी. के प्रत्येक खण्ड में व विशिष्ट रूप से पहचाने गये हैं।
- (आईआईआई) यहां उपयोग किये गये शब्द व अभिव्यक्तियां जो परिभाषित नहीं किये गये हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में नियत किया गया है।

अध्याय 2 – अन्तर्राज्यीय पारेषण हेतु योजना संहिता

इस अध्याय में अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का समावेश है।

2.1 परिचय :

योजना संहिता, राज्य ग्रिड व अन्तर्राज्यीय संपर्कों की योजना में लागू की जाने वाली नीतियों व प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट करती है।

2.2 उद्देश्य :

योजना संहिता के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- (1) उन सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं व मानदण्डों को विनिर्दिष्ट करना जिनका उपयोग आई.ए.एस.टी.एस. व अन्तर्राज्यीय सम्पर्कों की योजना व विकास में किया जाएगा।
- (2) आई.ए.एस.टी.एस. के किसी प्रस्तावित विकास में सभी राज्य संघटकों व अभिकरणों के मध्य सामन्जस्य को प्रोन्नत करना।
- (3) आई.ए.एस.टी.एस. की योजना व विकास में राज्य के सभी संघटकों व अभिकरणों के मध्य कार्यविधि व सूचना का आदान-प्रदान करना।

2.3 परिधि :

योजना संहिता आई.ए.एस.टी.एस. के विकास में संलिप्त तथा इसका उपयोग कर रहे व/या इससे जुड़े एस.टी.यू., अन्य राज्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन (आई.ए.एस.जी.एस.) पर लागू होता है। यह योजना संहिता आई.ए.एस.टी.एस. को/से ऊर्जा के पारेषण व/या उत्पादन के सम्बन्ध में उत्पादक कम्पनियों, आई.पी.जी., खुली पहुँच वाले उपयोगकर्ता व अन्य अनुज्ञप्तिधारियों पर भी लागू होती है।

2.4 योजना नीति :

- (1) एस.टी.यू., अन्तर्राज्यीय योजनाओं समेत मुख्य अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली की पहचान हेतु अपेक्षाओं के अनुसार समय-समय पर योजना प्रक्रिया बनाएगी जो कि प्राधिकरण द्वारा विकसित स्वरूप योजना के साथ उचित बैठेगी।
- (2) मुख्य अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के अतिरिक्त एस.टी.यू. समय-समय पर प्रणाली को सशक्त करने की योजना बनाएगी जिनकी आवश्यकता ऊर्जा अन्तरण में अवरोधों को दूर करने तथा ग्रिड के सम्पूर्ण प्रदर्शन को सुधारने में होगी। योजना अध्ययनों के आधार पर चिन्हित प्रणाली को सशक्त करने वाली योजनाओं सहित अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रस्तावों की ग्रिड समन्वय समिति की बैठकों में चर्चा, समीक्षा की जाएगी तथा उन्हें अन्तिम रूप दिया जाएगा।
- (3) उपरोक्त के आधार पर एस.टी.यू. एक पारेषण प्रणाली योजना तैयार करेगा जिसका प्रारूप राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- (4) पारेषण प्रणाली योजना आई.ए.एस.टी.एस. योजना का विवरण देगी तथा इसमें सभी उपयोग कर्ताओं के लाभ हेतु प्रस्तावित अन्तर्राज्यीय पारेषण योजनाएं तथा प्रणाली को सशक्त करने की योजनाएं सम्मिलित होंगी।

परन्तु पारेषण प्रणाली योजना में न केवल अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों से सम्बन्धित जानकारी सम्मिलित होगी बल्कि अतिरिक्त उपकरणों, प्रवर्तकों, कैपेसिटर्स, रिएक्टर्स, स्टैटिक वी.ए.आर. कम्पनसेटर्स तथा फ्लैगजिबल ऑल्टर्नेटिव करेन्ट पारेषण प्रणाली से सम्बन्धित जानकारी भी सम्मिलित होगी।

साथ ही यह भी कि पारेषण प्रणाली योजना में, चिन्हित की गयी अन्तर्राज्यीय/राज्य के भीतर पारेषण योजनाओं व प्रणाली सशक्त करने की योजनाओं पर पिछली योजनाओं हेतु निर्धारित लक्ष्य व प्राप्त प्रगति भी सम्मिलित होगी।

- (5) राज्य पारेषण यूटिलिटी, इन विनियमों के अधीन पारेषण प्रणाली योजना तैयार करने के उद्देश्य हेतु ऐसी सूचना प्राप्त करेगी जैसी कि उसे राज्य संघटकों से अपेक्षित होगी जिसमें उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि, प्रणाली आवर्धन व दीर्घकालिक भार पूर्वानुमान तथा सभी (स्वीकृत/लंबित) मुक्त प्रवेश हेतु आवेदन सम्मिलित हैं।

परन्तु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी का अपने संबंधित अनुज्ञपित क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक भार पूर्वानुमान विकसित करने हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व होगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण संहिता में उपबधित, भार पूर्वानुमान से संबंधित लागू उपबंधों द्वारा मार्गदर्शित होगा।

साथ ही यह भी कि राज्य पारेषण यूटिलिटी, पारेषण प्रणाली योजना तैयार करने में, इस विनियम के अधीन उपबंधित सूचना पर विचार करेगा, किन्तु इसके द्वारा बाध्य नहीं होगा।

- (6) राज्य पारेषण यूटिलिटी, इन विनियमों के अधीन पारेषण प्रणाली योजना तैयार करने के उद्देश्य हेतु निम्नलिखित पर भी विचार करेगी :-
 - (i) अधिनियम की धारा 73 के खण्ड (ए) के उपबन्धों के अधीन पारेषण प्रणाली हेतु प्राधिकारी द्वारा संरचित योजनाएं।
 - (ii) प्राधिकारी की भारतीय विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण रिपोर्ट।
 - (iii) अधिनियम की धारा 73 में खण्ड (डी) के अधीन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड मानक।
 - (iv) अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (एच) के अधीन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड संहिता के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी द्वारा संरचित पारेषण योजना।
 - (v) प्राधिकारी द्वारा जारी पारेषण योजना मानदण्ड व मार्गदर्शन।
 - (vi) क्षेत्रीय ऊर्जा समिति की संस्तुतियां/आदान, यदि कोई हैं।
 - (vii) आयोग द्वारा सुझाए गए डाटास्रोत/कोई अन्य जानकारी।
- (7) सभी राज्य संघटक व अभिकरण, एस.टी.यू. को अपनी योजना संरचित करने व इसे अंतिम रूप देने में सहायता हेतु समय-समय पर इच्छित योजना डाटा की आपूर्ति करेंगे।
- (8) योजना रिपोर्ट में अतिरिक्त पारेषण आवश्यकताओं पर एक अध्याय सम्मिलित होगा जिसमें न केवल राज्य के भीतर पारेषण लाईनों का बल्कि अतिरिक्त उपकरणों जैसे प्रवर्तक, कैपेसिटर, रिएक्टर इत्यादि का भी समावेश होगा।
- (9) योजना रिपोर्ट, नई योजनाओं पर की गयी वास्तविक प्रगति व अतिरिक्त अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए की गयी कार्यवाही भी इंगित करेगी। ये रिपोर्ट आई.ए.एस.टी.एस. पर निवेश निर्णय/संयोजन निर्णय लेने हेतु रूचि लेने वाले किसी पक्ष को उपलब्ध होंगी।
- (10) राज्य पारेषण यूटिलिटी प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक आयोग को आई.ए.एस.टी.एस. के लिए पारेषण प्रणाली योजना की एक प्रति भेजेगी तथा इसे अपनी इन्टरनेट वेब साइट में भी प्रकाशित करेगी। एस.टी.यू. भी इस किसी व्यक्ति के आवेदन पर उपलब्ध कराएगी।
- (11) क्योंकि वोल्टेज प्रबन्धन की, ऊर्जा के राज्य से भीतर पारेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, कैपेसिटर्स, रिएक्टर्स, एस.वी.सी. व फ्लैक्जिबल ऑल्टरनेटिंग करेंट पारेषण प्रणाली (एफ.ए.सी.टी.एस.) की योजना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

2.5 योजना मानदण्ड :

- (1) योजना मानदण्ड, सुरक्षा सिद्धान्त पर आधारित होंगे जिस पर आई.ए.एस.टी.एस. नियोजित है। सुरक्षा सिद्धान्त प्राधिकारी द्वारा दिये गये मार्गदर्शकों व पारेषण योजना मानदण्ड के अनुसार होंगे किन्तु राज्य पारेषण यूटिलिटी, पारेषण प्रणाली योजना विकसित करते समय उपयुक्त प्रणाली जारी करेगी।
- (2) प्रदेश के भीतर की पारेषण प्रणाली, एक सामान्य नियम के रूप में, निर्धारित राज्य परिचालन के दौरान उत्पादन के पुनः अनुसूचीकरण या लोड शैडिंग किये बिना निम्नलिखित आकस्मिकताओं के समक्ष सुरक्षित रहने व प्रतिरोधक क्षमतावान होनी चाहिए :-
 - (i) 110 के.वी./132 के.वी. डी./सी. लाइन की आउटटेज या,
 - (ii) 220 के.वी. डी./सी. लाइन की आउटटेज या,
 - (iii) 400 के.वी. एस./सी. लाइन की आउटटेज या,
 - (iv) एकल अन्तः संयोजक प्रवर्तक की आउटटेज या,
 - (v) एच.वी.डी.सी. बायपोल लाइन के एक पोल की आउटटेज या,
 - (vi) 765 के.वी. एस./सी. लाइन की आउटटेज

किन्तु उपरोक्त प्रासंगिकताएं दूसरी 110 के.वी./132 के.वी. डी./सी. लाईन या 220 के.वी. डी./सी. लाईन या दूसरे कॉरीडोर 400 के.वी. एस./सी. लाईन पूर्व प्रासंगिक प्रणाली की क्षीणता (योजनाबद्ध आउटटेज की अवास्तविकता) पर विचार किया जाएगा।

- (3) सभी उत्पादक यूनिटें अपनी रिएक्टर क्षमता के भीतर प्रचालित की जा सकेंगी तथा नेटवर्क वोल्टता को प्रोफाइल विनिर्दिष्ट वोल्टता सीमाओं के भीतर बनाए रखा जाएगा।
- (4) राज्य के भीतर की पारेषण प्रणाली, स्थिरता की हानि के बिना सर्वाधिक तीव्र एकल इनफीड की हानि के प्रतिरोध की क्षमता वाली होगी।
- (5) उपरोक्त उपविनियम (2) में परिभाषित कोई एक घटना निम्नलिखित का कारण नहीं बनेगी :-
 - (i) आपूर्ति की हानि।
 - (ii) विनिर्दिष्ट सीमाओं से नीचे या ऊपर प्रणाली फ्रीक्वेंसी का लम्बे समय तक चलने वाला परिचालन।
 - (iii) अस्वीकार्य उच्च या निम्न वोल्टेज।
 - (iv) प्रणाली की अस्थिरता।
 - (v) आई.ए.एस.टी.एस. की अस्वीकार्य अतिभारिता।
- (6) सिवाय एच.वी.डी.सी. के, सभी उपस्टेशनों में प्रवर्तकों की उचित संख्या (न्यूनतम दो) व क्षमता प्रदान की जाएगी ताकि उपस्टेशन की सुदृढ़ क्षमता बनाए रखने के लिए अपेक्षित पर्याप्त प्रचुरता रहे। एच.वी.डी.सी. उपस्टेशनों में, किसी भी समय उपयोग के लिए कम से कम एक अतिरिक्त कनवर्टर/इनवर्टर प्रवर्तक रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के उद्देश्य हेतु, सुदृढ़ क्षमता कथन से अभिप्राय—किसी एक प्रवर्तक की आउटटेज की स्थिति में उपस्टेशन पर उपलब्ध न्यूनतम प्रवर्तक क्षमता, होगा।

- (7) राज्य पारेषण यूटिलिटी, राज्य के भीतर उत्पादक स्टेशन में रिवचयार्ड पर रिएक्टिव ऊर्जा प्रतिपूर्ति सहित, आई.ए.एस.टी.एस. की रिएक्टिव ऊर्जा प्रतिपूर्ति सहित, आई.ए.एस.टी.एस. की रिएक्टिव ऊर्जा प्रतिपूर्ति हेतु योजना अध्ययन कराएगा।

2.6 योजना डाटा :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता, पारेषण योजना विकसित करने के उद्देश्य हेतु राज्य पारेषण यूटिलिटी को निम्नलिखित प्रकार का डाटा उपलब्ध करायेंगे :-

- (i) मानक योजना डाटा;
- (ii) विस्तृत योजना डाटा।

2.6.1 मानक योजना डाटा :

- (1) मानक योजना डाटा में, उपयोगकर्ता/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विकास के कारण आई.ए.एस.टी.एस. पर प्रभाव की जांच करने के लिए राज्य पारेषण यूटिलिटी हेतु सामान्यतः पर्याप्त सम्भावित होने वाले विवरण का समावेश है।
- (2) राज्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा उपयोगकर्ता, राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा प्रदान किये गये मानक प्रारूप में, समय-समय पर राज्य पारेषण यूटिलिटी को निम्नलिखित मानक डाटा उपलब्ध करायेंगे :-
 - (i) प्रारंभिक परियोजना नियोजन डाटा।
 - (ii) वचनबद्ध परियोजना नियोजन डाटा, तथा
 - (iii) संयोजित नियोजन डाटा।

परन्तु, राज्य पारेषण यूटिलिटी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता को उचित समय प्रदान करने के पश्चात् उक्त प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक तिथि व आवर्तिता (अधिकतम एक वर्ष) प्रदान करेगी।

यह भी कि, राज्य पारेषण यूटिलिटी इन विनियमों की अधिसूचना के एक माह के भीतर उपर्युक्त डाटा प्रस्तुत करने के लिए राज्य पारेषण यूटिलिटी एक मानक प्रारूप विकसित करेगी तथा इसे अपनी इनटरनेट वेबसाईट पर व जो कोई व्यक्ति इसमें रुचि रखता हो, उसे उपलब्ध करायेगी।

साथ ही यह भी कि राज्य पारेषण यूटिलिटी, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (एच) के अधीन केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड संहिता के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत करने के लिए विकसित प्रारूप द्वारा मार्गदर्शित होगा।

2.6.2 विस्तृत योजना डाटा :

- (1) विस्तृत योजना डाटा में, आई.ए.एस.टी.एस. पर उपयोगकर्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी विकास के प्रभाव का आंकलन करने के लिए राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा साधारण अनपेक्षित अतिरिक्त, अधिक विस्तृत डाटा का समावेश है।
- (2) विस्तृत योजना डाटा, राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा जब व जैसे निवेदन किया, उपयोगकर्ता व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

2.7 पारेषण योजना का कार्यान्वयन :

पारेषण लाईनों, अन्तः संयोजक प्रवर्तकों, रिएक्टर्स/कैपेसिटर्स व अन्य पारेषण एलीमेन्ट्स का वास्तविक कार्यक्रम एस.टी.यू. द्वारा, संबंधित अभिकरणों के साथ परामर्श कर निर्धारित किया जाएगा। अपेक्षित समय संरचना में कार्यों का पूर्ण किया जाना, एस.टी.यू. द्वारा संबंधित अभिकरण के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

अध्याय 3-संयोजन शर्तें

3.1 परिचय :

न्यूनतम तकनीकी व डिजायन मानदण्ड में विनिर्दिष्ट संयोजन शर्तें जिनका कि आई.ए.एस.टी.एस. से संयोजित या संयोजन के इच्छुक उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व एस.टी.यू. द्वारा अनुपालन किया जाएगा। ये उन प्रक्रियाओं को भी नियत करती हैं जिनका एस.टी.यू.एफ. सहमत हुए संयोजन की स्थापना हेतु पूर्व शर्त के रूप में उपरोक्त मानदण्ड के साथ किसी अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

3.2 उद्देश्य :

संयोजन शर्तें यह सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित की गयी हैं कि :-

- (i) संयोजन हेतु प्राथमिक बातों का अनुपालन हो तथा साथ ही सभी अभिकरणों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार हो।
- (ii) स्थापित होने पर कोई नया या संशोधित संयोजन न तो आई.ए.एस.टी.एस. से इसके संयोजन के कारण अस्वीकार्य प्रभावों से त्रस्त होगा न ही किसी अन्य संयोजित अभिकरण की प्रणाली पर अस्वीकार्य प्रभाव डालेगा।
- (iii) सभी उपस्करों हेतु स्वामित्व व उत्तरदायित्व, जहां-कहीं नया संयोजन लगाया जाए, प्रत्येक स्थल हेतु एक अनुसूची (स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची) में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

3.3 परिधि :

संयोजन शर्तें, आई.ए.एस.टी.एस. के विकास में संलिप्त व इससे जुड़े सभी राज्य संघटक (एस.टी.यू., आई.ए.एस.जी.एस. इत्यादि) तथा किसी अन्य अभिकरण/अनुज्ञप्तिधारी पर लागू होती है। यह संयोजन सहित उन सभी अभिकरणों पर भी लागू होती है जो आई.ए.एस.टी.एस. को/से ऊर्जा उत्पादित/पारेषित व/या उत्पादित/पारेषित करने की योजना बना रहे हैं। वितरण प्रणाली में अन्तःस्थापित उत्पादक यूनिटें जो आई.ए.एस.टी.एस. से संयोजित नहीं हैं, के लिए संयोजन शर्तों को, संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

3.4 संयोजन मानक :

विद्युत संयंत्रों, विद्युत लाईनों के निर्माण व आई.ए.एस.टी.एस. से संयोजिता हेतु लागू तकनीकी मानक, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73 के खण्ड (बी) के अधीन प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार होंगे।

परन्तु भारतीय विद्युत नियम, 1956 व प्राधिकारी के प्रचलित मार्गदर्शकों पर ही प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 73 के खण्ड (बी) के अधीन विनियमों के अधिसूचित किये जाने तक विचार किया जाएगा।

3.5 सुरक्षा मानक :

विद्युत संयंत्रों व विद्युत लाईनों के विनिर्माण, परिचालन व अनुरक्षण लागू अपेक्षाएं अधिनियम की धारा 73 खण्ड (सी) के अधीन प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार होंगे।

किन्तु भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 व प्राधिकारी के प्रचलित मार्गदर्शकों पर ही प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 73 के खण्ड (सी) के अधीन विनियमों के अधिसूचित होने तक विचार किया जाएगा।

3.6 संयोजन हेतु प्रक्रिया :

- (1) आई.ए.एस.टी.एस. से किसी अभिकरण के संयोजन से पूर्व, अनुपालन किये जाने वाली अन्य आपस में सहमत अपेक्षाओं के अतिरिक्त एस.जी.सी. में प्रदर्शित सभी आवश्यक शर्तें, अभिकरण द्वारा पूर्ण की जानी चाहिए।

- (2) आई.ए.एस.टी.एस. के संयोजन व/या उसके उपयोग की वर्तमान व्यवस्था को संशोधित करने या नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए आवेदन, संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या उपयोगकर्ता द्वारा राज्य पारेषण यूटिलिटी के पास जमा किये जाएंगे।

किन्तु, विनियम में उल्लिखित आवेदन हेतु मानक प्रारूप, राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा विकसित किया जाएगा तथा इन विनियमों की अधिसूचना के दो (2) माह के भीतर अपनी इन्टरनेट वेब साईट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

- (3) ऊपर उपनियम (2) में उल्लिखित आवेदन-पत्र, निम्नलिखित विवरण के साथ जमा किया जाएगा :-

- (i) प्रस्तावित संयोजन व/या उपान्तरण, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी जिसकी प्रणाली संयोजन के लिए प्रस्तावित है, संयोजन बिन्दु संयोजित किये जाने वाले साधनों का विवरण या पहले के संयोजित साधनों का उपान्तरण तथा प्रस्तावित संयोजन के लाभार्थियों के प्रयोजन को दर्शित करने वाली रिपोर्ट।
- (ii) संनिर्माण अनुसूची तथा लक्ष्य पूरा होने की तिथि।
- (iii) यह पुष्टि कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या उपयोगकर्ता राज्य ग्रिड संहिता के उपबन्धों, भारतीय विद्युत नियमों तथा अधिनियम के अनुसरण में निर्मित ग्रिड संयोजन मानकों सहित विभिन्न मानकों का पालन करेगा।

- (4) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, जिसकी प्रणाली में संयोजन चाहा गया है, को आवेदन की एक प्रति, राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र व राज्य के भीतर, ऐसे प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी जिनकी पारेषण प्रणाली के इससे प्रभावित होने की संभावना है, को अग्रसारित की जाएगी।

- (5) राज्य पारेषण यूटिलिटी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, जिसकी प्रणाली में संयोजन चाहा गया है, किसी नये संयोजन की अनुमति से पूर्व उपयुक्त समझे गये ऊर्जा प्रणाली का अध्ययन करवाएगा।

- (6) राज्य पारेषण यूटिलिटी, उपविनियम (2) के अधीन एक आवेदन की प्राप्ति से तीस (30) दिन के भीतर व उपविनियम (4) के अधीन चिन्हित पक्षों से प्राप्त सुझावों व टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात:-

- (i) राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों या संशोधनों के साथ आवेदन स्वीकार करेगा।
- (ii) यदि इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार आवेदन नहीं है तो कारण अभिलिखित कर उसे निरस्त कर सकता है।

- (7) उपविनियम (2) के खण्ड (ए) के अनुसार आवेदन स्वीकार किये जाने की स्थिति में, राज्य पारेषण यूटिलिटी, आवेदक को एक औपचारिक प्रस्थापना देगी।

किन्तु, राज्य पारेषण यूटिलिटी को प्रस्थापना की एक प्रति उपयुक्त पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अग्रसारित करनी होगी।

- (8) वोल्टेज का स्तर जिस पर आवेदक को आई.ए.एस.टी.एस. के साथ संयोजित होने की प्रस्थापना की गयी है, प्राधिकारी व राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा अपनाए गये प्रचलित मानदण्डों के अनुसार शासित होगा।
- (9) संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/उपयोगकर्ता द्वारा अपेक्षित शर्तों के अनुपालन पर, राज्य पारेषण यूटिलिटी, संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/उपयोगकर्ता को अधिसूचित करेगा कि उसे आई.ए.एस.टी.एस. के साथ संयोजित किया जा सकता है।
- (10) जिसकी प्रणाली में संयोजन चाहा गया है वह आवेदक व उपयुक्त पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आवेदक के प्रस्ताव के स्वीकार होने पर संयोजन करार को अंतिम रूप देगा।

परन्तु, उपयुक्त पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संयोजन करार की एक प्रति राज्य पारेषण यूटिलिटी को उपलब्ध करानी होगी।

साथ ही यह भी कि, राज्य मार प्रेषण केन्द्र को भी उपयुक्त संयोजन करार की एक प्रति उपयुक्त पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

- (11) आई.ए.एस.टी.एस. नेटवर्क व राज्य घटक/आई.ए.एस.जी.एस. के मध्य, शर्तों के संबंध में एक वर्ष की शिथिलता अनुमोदित है ताकि वर्तमान व्यवस्था जारी रहे। आई.ए.एस.जी.एस./राज्य घटकों के साथ संयोजन शर्तों पर पुनः बातचीत की प्रक्रिया एक वर्ष की अवधि में पूरी कर ली जानी चाहिए। यदि यह अवधारित हो जाता है कि संयोजन शर्तों के अनुपालन में और देरी हो सकती है तो आयोग आगे की शिथिलता पर विचार कर सकता है, इसके लिए संबंधित संघटक को एस.टी.यू. की संस्तुतियों/टिप्पणियों के साथ वाद दाखिल करना होगा। परिवर्तन में यदि कोई लागत आती है तो इसका व्यय संबंधित संघटक को उठाना होगा।

3.7 संयोजन करार :

- (1) संयोजन करार में इसकी शर्तों व निबंधनों के भीतर उचित रूप से, आई.ए.एस.टी.एस. के उपयोगकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी के संयोजन से संबंधित निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी :-
- (i) राज्य ग्रिड संहिता के दोनों पक्षों द्वारा अपेक्षित अनुपालन की शर्त।
 - (ii) संयोजन, तकनीकी अपेक्षाओं व वाणिज्यिक व्यवस्थाओं का विवरण।
 - (iii) आवश्यक पुनः प्रवर्तन या प्रणाली के विस्तार, डाटा संप्रेषण इत्यादि के कारण होने वाले पूंजीगत व्यय का विवरण तथा संबंधित पक्षों के मध्य उसका अम्यंकन।
 - (iv) स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची।
 - (v) संरक्षण व दूरी पता लगाने के लिए सामान्य सिद्धान्त का मार्गदर्शन।
 - (vi) संरक्षण प्रणालियाँ।
 - (vii) प्रणाली अभिलेख उपकरण।
 - (viii) संप्रेषण सुविधाएँ।
 - (ix) राज्य पारेषण यूटिलिटी या आयोग द्वारा उपयुक्त समझी गयी कोई अन्य सूचना।
- (2) राज्य पारेषण यूटिलिटी, दो (2) माह के भीतर एक आदर्श संयोजन करार विकसित करेगी तथा इसे आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।

3.8 ग्रिड मानदण्ड परिवर्तन :

3.8.1 सामान्य :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि आई.ए.एस.टी.एस. से सेवा अपेक्षा कर रहे या उसे सेवा प्रदान कर रहे संयंत्र व उपकरण ऐसे विनिर्माण व डिजायन के हों कि ऐसे संयंत्रों व उपकरणों का परिचालन, उसके अभिहित मूल्य से प्रणाली फ्रीक्वेन्सी व वोल्टेज के तत्काल मूल्य में परिवर्तन द्वारा बाधित नहीं होगा तथा ऐसे संयंत्र व उपकरण आई.ए.एस.टी.एस. पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेंगे।

3.8.2 फ्रीक्वेन्सी परिवर्तन :

प्रणाली की रेटेज फ्रीक्वेन्सी 50.0 एच.जैड होगी तथा सामान्यतः प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर नियंत्रित होगी।

3.8.3 वोल्टेज परिवर्तन :

- (1) वोल्टेज का परिवर्तन, प्राधिकारी द्वारा संरचित विनियमों में विनिर्दिष्ट वोल्टेज रेंज से अधिक नहीं होगा।
- (2) उप पारेषण व वितरण में संलग्न अभिकरण, संयोजित होने पर रिएक्टिव समर्थन के लिए आई.ए.एस.टी.एस. पर निर्भर नहीं होगा। अभिकरण एस.टी.यू. के साथ विशिष्ट रूप से सहमत होने तक अपनी पूर्ण ऊर्जा अपेक्षा को पूरा करने के लिए अपने पारेषण व वितरण नेटवर्क में अपेक्षित रिएक्टिव प्रतिपूर्ति का आंकलन करेगा व इसे प्रदान करेगा।

3.9 संयोजन बिन्दुओं पर उपस्कर :

3.9.1 उपस्टेशन उपस्कर :

- (1) सभी अति उच्च वोल्टेज (ई.एच.वी.) उपस्टेशन, भारतीय मानक ब्यूरो/अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग/प्रचलित आचार संहिता द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करेंगे।
- (2) सभी उपस्कर, अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग या भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार गुणवत्ता आश्वासन अपेक्षा के अनुरूप अभिकल्पित, विनिर्मित व परीक्षित किये जाएंगे।
- (3) उपयोगकर्ता व आई.ए.एस.टी.एस. के मध्य प्रत्येक संयोजन, विशिष्ट संयोजन करार में राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा सुझाया गया कम से कम शॉर्ट सर्किट करंट, संयोजन बिन्दु पर, रोकने की क्षमता वाले सर्किट ब्रेकर द्वारा नियंत्रित होगा।

3.9.2 त्रुटि दूर करने का समय :

- (1) उपयोगकर्ता के उपस्कर से संयोजित आई.ए.एस.टी.एस. पर तीन फेज फॉल्ट (बस बार्स के समीप) तथा आई.ए.एस.टी.एस. से सीधे जुड़े उपयोगकर्ता के उपस्कर पर तीन फेज फॉल्ट (बस बार्स के समीप) के लिए, जब सभी उपस्कर उचित रूप से कार्य कर रहे हों तब प्राथमिक संरक्षण योजना हेतु त्रुटि दूर करने का समय निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :-

(i) 800 के०वी० श्रेणी व 400 के०वी० के लिए 100 मिली० सैकण्ड्स।

(ii) 220 के०वी० व 132 के०वी०/110 के०वी० के लिए 160 मिली० सैकण्ड्स।

- (2) उपरोक्त त्रुटि दूर करने की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रदान की गयी प्राथमिक संरक्षण प्रणालियों के विफल होने की स्थिति में, अपेक्षित पृथक्करण/संरक्षण हेतु संरक्षण सहायता प्रदान की जाएगी। यदि कोई आई.ए.एस.टी.एस. से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है तो इसे आई.ए.एस.टी.एस. की ओर संरक्षण सहायता द्वारा त्रुटि दूर करने तक फॉल्ट को सहने योग्य होना चाहिए।

3.9.3 संरक्षण :

- (1) विश्वसनीयता, चयनियता व संवेदनशीलता के साथ, फॉल्ट विलयरेंस के विनिर्दिष्ट समय के भीतर सभी प्रकार के फॉल्ट्स आंतरिक/बाह्य के विरुद्ध त्रुटिपूर्ण उपकरणों के पृथक्करण व अन्य पुर्जों को संरक्षित रखने के लिए, एस.टी.यू. के साथ सामन्जस्य कर, आई.ए.एस.टी.एस. से जुड़े सभी उपयोगकर्ताओं पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

आई.ए.एस.टी.एस. से जुड़े सभी उपयोगकर्ता व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, संयोजन करार में विनिर्दिष्ट रूप से संरक्षण प्रणाली प्रदान करेंगे।

- (2) रिले सैटिंग समन्वय, क्षेत्रीय ऊर्जा समिति द्वारा क्षेत्रीय स्तर किया जाएगा।

3.10 उत्पादक यूनिट व ऊर्जा स्टेशन :

- (1) एक उत्पादक यूनिट, विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट अभिकल्पना सीमाओं की शर्त पर, उपरोक्त विनियम 3.8 पर इंगित प्रणाली फ्रीक्वेन्सी व वोल्टेज परिवर्तन रेन्ज के भीतर इसके सामान्य रेटेड एक्टिव/रिएक्टिव परिणाम की निरन्तर आपूर्ति के योग्य होनी चाहिए।
- (2) एक उत्पादक यूनिट को, संयोजन करार में नियत किये अनुसार एक ए0वी0आर0, संरक्षण व सुविधा युक्तियां प्रदान की जाएंगी।
- (3) प्रत्येक उत्पादक यूनिट में एक टरबाइन स्पीड गवर्नर लगाया जाएगा जिसमें 3 प्रतिशत से 6 प्रतिशत की रेन्ज के भीतर एक पूर्ण ड्रूप विशिष्टता होगी तथा यह सदैव सेवा में रहेगा।
- (4) प्रत्येक उत्पादक यूनिट, फ्रीक्वेन्सी फॉल्ट्स के 105 प्रतिशत एम0सी0आर0 सीमित होने पर तुरन्त 5 प्रतिशत आउटपुट बढ़ाने की क्षमता योग्य होगी। पिछला एक डब्ल्यू स्तर (यदि बढ़ा हुआ आउटपुट स्तर सतत नहीं रह पाता है) 1 प्रतिशत प्रति मिनट से अधिक तीव्र नहीं होगा।

3.11 रिएक्टिव ऊर्जा प्रतिपूर्ति :

- (1) मार बिन्दुओं से समीप निम्न वोल्टेज प्रणालियों में जहां तक सम्भव हो, उपयोगकर्ता द्वारा पुनः सक्रिय ऊर्जा प्रतिपूर्ति व/या अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस प्रकार विनिर्दिष्ट रेन्ज के भीतर आई.ए.एस.टी.एस. बनाए रखने के लिए तथा आई.ए.एस.टी.एस. को/से रिएक्टिव ऊर्जा के विनिमय की आवश्यकता को ढाला जाएगा।
- (2) संयोजन करार में नियत सीमाओं के भीतर अस्थाई अति वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए लाईन रिएक्टर्स उपलब्ध कराये जाएंगे।
- (3) उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली अतिरिक्त पुनः सक्रिय प्रतिपूर्ति, कार्यान्वयन हेतु संयोजन करार में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इंगित की जाएगी।

3.12 डाटा व संप्रेषण सुविधाएं :

विश्वसनीय व दक्ष कथन तथा आंकड़े संसूचना प्रणाली सामान्य तथा प्रसामान्य शर्तों के अधीन आवश्यक संसूचना और आंकड़ा आदान-प्रदान तथा इस एस.एल.डी.सी. द्वारा ग्रिड के पर्यवेक्षण/नियंत्रण अभिकरण अन्तरापृष्ठ अपेक्षाओं तथा एस.एल.डी.सी. को उपलब्ध कराये गये अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आधार पर फलो, वोल्टता व स्विचों/ट्रांसफॉर्मर टैप्स आदि टेलीमीटर ऊर्जा प्रणाली पैरामीटर को प्रणालियां प्रदान कराएंगे। यथास्थिति, एस.एल.डी.सी. के लिए फलो अप आंकड़े सुकर बनाने के लिए सहबद्ध संचार प्रणाली संयोजन करार में एस0टी0यू0 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट संबंधित अभिकरण द्वारा स्थापित की जाएगी। सभी अभिकरण एस0टी0यू0 के समन्वय से अपने-अपने प्रयोजन पर तथा संयोजन करार में यथाविनिर्दिष्ट एस0एल0डी0सी0 पर अपेक्षित सुविधाएं प्रदान कराएगा।

3.13 प्रणाली अभिलेखन उपकरण :

- (1) डाटा अर्जन/बाधा अभिलेखित्र/घटना लॉगर/खराबी दूढ़ने वाला (जिसमें तुल्यकालन उपकरण भी सम्मिलित हैं) अभिलेखन आंकड़े प्रणाली के सक्रिय कार्य निष्पादन को अभिलेखित करने के लिए आई.ए.एस.टी.एस. में प्रदान किये जाएंगे।
- (2) सभी उपयोगकर्ता व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तय समय अनुसूची के अनुसार संयोजन करार में यथाविनिर्दिष्ट सभी अपेक्षित अभिलेखन उपकरण प्रदान कराएंगे।

3.14 प्रचलनात्मक सुरक्षा के लिए उत्तरदायित्व :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता प्रत्येक संयोजन बिन्दु के लिए स्थल उत्तरदायित्व अनुसूचियों में यथा उपदर्शित सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे।

3.15 स्थल उत्तरदायित्व अनुसूचियां :

- (1) स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची, संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें परियोजना या संयोजन, जिसमें सुरक्षा उत्तरदायित्व भी सम्मिलित है, के निष्पादन से पूर्व प्रत्येक की स्वामित्व जिम्मेदारियों के ब्यौरे होंगे।
- (2) स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची असंगत संयोजन करार के अनुसरण में संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार की जाएगी जिसमें प्रत्येक संयोजन बिन्दु पर स्थापित संयंत्र तथा साधित्र की मद के लिए निम्नलिखित विवरण होगा :-
 - (i) संयंत्र/उपकरण का स्वामित्व।
 - (ii) संयंत्र/उपकरण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायित्व।
 - (iii) संयंत्र/उपकरण के परिवालन हेतु उत्तरदायित्व।
 - (iv) संयंत्र/उपकरण के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायित्व।
 - (v) संयोजन बिन्दु पर किसी व्यक्ति की सुरक्षा से संबंधित मामलों हेतु उत्तरदायित्व।
- (3) स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची को तैयार करने में उपयोग किये जाने वाले प्रारूप सिद्धान्त व प्राथमिक प्रक्रिया, इन विनियमों की अधिसूचना में तीन (3) माह के भीतर राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा तैयार किये जाएंगे तथा अनुपालन हेतु प्रत्येक उपयोगकर्ता व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान किये जाएंगे।

किन्तु राज्य पारेषण यूटिलिटी को उपरोक्त प्रारूप, सिद्धान्तों व प्रक्रियाओं से संबंधित सूचना अपनी इन्टरनेट वेबसाइट पर देनी होगी।

- (4) आई.ए.एस.टी.एस. से जुड़ी व जुड़ने की योजना बना रहे सभी अभिकरण, आई.ए.एस.टी.एस. से संयोजित किये जा रहे उत्पादक स्टेशनों या उपस्टेशनों/लाईनों के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से पूर्व एस.एल.डी.सी. को वास्तविक समय मेजे जाने के लिए एस.एल.डी.सी. द्वारा विनिर्दिष्ट आर.टी.यू. व अन्य संसूचना उपकरण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3.16 एकल लाईन डायग्राम :

- (1) राज्य पारेषण यूटिलिटी जो, संयोजित उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक संयोजन बिन्दु के लिए एक लाईन-डायग्राम प्रस्तुत करना होगा।

परन्तु, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त सूचना राज्य मार प्रेषण केन्द्र को भी प्रस्तुत करनी होगी।

- (2) एकल लाईन डायग्राम में सभी उच्च टेन्शन (एच.टी.) संयोजित उपकरण, सभी बाहरी सर्किट्स से संयोजन सम्मिलित है तथा इनका संख्याकरण, नामावली बनाना, लेबलिंग भी किया जाएगा। डायग्राम से संबंधित संयंत्र का नक्शा सर्किट संयोजन, रेटिंग, नामावली संख्याकरण, आशयित है।
- (3) किसी उपस्कर को परिवर्तित करने के प्रस्ताव की स्थिति में संबंधित उपयोगकर्ता को आवश्यक परिवर्तनों की सूचना देगा। परिवर्तन लागू हो जाने पर, संबंधित उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एकल लाईन डायग्राम को उचित रूप से अद्यतन किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति राज्य पारेषण यूटिलिटी व एस.एल.डी.सी. को उपलब्ध कराई जाएगी।

3.17 स्थल सामान्य रेखाचित्र :

- (1) प्रत्येक संयोजन बिन्दु हेतु एक स्थल सामान्य रेखाचित्र तैयार किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी:-

- (i) स्थल नक्शा,
- (ii) विद्युत नक्शा,
- (iii) संरक्षण/नियंत्रण का विवरण, तथा
- (iv) सामान्य सेवाएं रेखाचित्र

आवश्यक विवरण, अभिकरणों द्वारा एस.टी.यू. को प्रदान किये जाएंगे।

- (2) प्रत्येक संयोजन बिन्दु पर अपनी प्रणाली/सुविधा के संबंध में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता द्वारा विस्तृत रेखाचित्र बनवाए जाएंगे तथा उनकी एक प्रति क्रमशः संबंधित उपयोगकर्ता व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध कराई जाएगी।
- (3) स्थल सामान्य रेखाचित्र के मामले में यदि, संयोजन बिन्दु पर अपनी प्रणाली/सुविधा के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी या उपयोगकर्ता द्वारा यह पाया जाता है कि यह आवश्यक है तो ऐसे परिवर्तन का विवरण, यथाशीघ्र दूसरे पक्ष को उपलब्ध कराया जाएगा।

3.18 स्थल पहुंच, स्थल परिचालक कार्यकलापों व अनुरक्षण मानकों की प्रक्रिया :

- (1) संयोजन करार, आई.ए.एस.जी.एस./अनुज्ञप्तिधारी/उपयोगकर्ता के परिक्षेत्र पर एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के उपस्कर या विपर्ययेन हेतु स्थल पहुंच, स्थल परिचालन कार्यकलापों व अनुरक्षण मानकों के लिए आवश्यक प्रक्रिया भी इंगित करेगा।
- (2) संयोजन स्थल का स्वामी उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, उन दूसरे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या उपयोगकर्ता को अपेक्षित सुविधाएं व उचित पहुंच प्रदान कराएगा जिनका संस्थापन, परिचालन, अनुरक्षण इत्यादि के लिए संयोजन स्थल पर उपस्कर का संस्थापन होना प्रस्तावित है।
- (3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या उपयोगकर्ता को आज़ापक पहुंच उपलब्ध है तथा संयोजन स्थल पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता के हितों की रक्षा के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों व उपयोगकर्ताओं के मध्य लिखित प्रक्रियाएं व करार विकसित किये जाएंगे।

3.19 आई.ए.एस.टी.एस. को अन्तर्राष्ट्रीय संयोजन :

आई.ए.एस.टी.एस. को अन्तर्राष्ट्रीय संयोजन हेतु प्रक्रिया तथा इसके लिये करार, प्राधिकारी व ऊर्जा मन्त्रालय (एम.ओ.पी.) के साथ परामर्श कर एस.टी.यू. द्वारा किया जाएगा।

3.20 राज्य ग्रिड की परिसम्पत्तियों की अनुसूची :

प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक आयोग को वार्षिक रूप से एस.टी.यू. पारेषण की परिसम्पत्तियों की एक अनुसूची प्रस्तुत करेगा जो कि उस वर्ष 31 मार्च को राज्य ग्रिड की संरचना उसके स्वामित्व को इंगित करते हुए है जिस पर एस.एल.डी.सी. की नियंत्रण जिम्मेदारी है।

अध्याय 4-परिचालन संहिता

4.1 उद्देश्य :

राज्य ग्रिड के समेकित परिचालन का प्राथमिक उद्देश्य, समस्त राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में फैले सारे विद्युत ऊर्जा नेटवर्क की संपूर्ण परिचालन अर्थव्यवस्था विश्वसनीयता में वृद्धि करना है।

4.1.1 परिचालन नीति :

- (1) सहभागी यूटिलिटी एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे तथा राज्य ग्रिड के लाभकारी व संतोषजनक परिचालन हेतु सर्वदा अच्छे परिचालक तरीके अपनाएंगे।
- (2) राज्य का सम्पूर्ण परिचालन, राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.) से पर्यवेक्षित होगा। एस.एल.डी.सी. की भूमिका अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार होगी।
- (3) सभी राज्य संघटक, समेकित परिचालन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने तथा दायित्वों की समान भागीदारी हेतु इस परिचालक संहिता का पालन करेंगे।
- (4) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य ग्रिड को प्रबंधित करने के लिए विस्तृत आंतरिक परिचालक प्रक्रियाओं का एक समुच्चय विकसित, प्रलेखित व अनुरक्षित करेगा।

इन आंतरिक परिचालक प्रक्रियाओं में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:-

(i) ब्लैक स्टार्ट प्रक्रिया

(ii) लोड शैडिंग प्रक्रिया

(iii) आइलैंडिंग प्रक्रिया

(iv) कोई अन्य प्रक्रिया जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उचित समझी जाए।

परन्तु, ऐसी प्रक्रियाएं, राज्य संघटकों के साथ परामर्श कर विकसित की जाएंगी तथा एस.जी.सी. से एकरूप होंगी ताकि एस.जी.सी. की अपेक्षाओं का पालन हो सके।

साथ ही यह भी कि ऐसी प्रक्रियाएं, आयोग के अनुमोदन हेतु तीन (3) माह के भीतर प्रस्तुत की जाएंगी।

- (5) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों, ऊर्जा संयंत्रों, 132 के0वी0 व उससे ऊपर के कोई अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों व उपयोगकर्ताओं के नियन्त्रण केन्द्रों सहित राज्य भार प्रेषण केन्द्र के नियन्त्रण कक्षों की योग्य व पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा चौबीस घण्टे चौकसी की जाएगी।

4.2 प्रणाली सुरक्षा पहलू :

- (1) सभी राज्य संघटकों का यह प्रयास होगा कि वे सदैव एक-दूसरे के साथ समकालिक घटनाओं में अपनी-अपनी ऊर्जा प्रणाली और ऊर्जा केन्द्रों का ऐसे प्रचालन करेंगे जिससे कि एक समकालिक प्रणाली में राज्य के भीतर सम्पूर्ण प्रणाली को परिचालित किया जा सके।
- (2) ग्रिड का कोई भी भाग राज्य ग्रिड के शेष भाग से जान-बूझकर अलग नहीं किया जाएगा, सिवाय -(1) आपातकालीन या ऐसी दशा में जिसमें इसे अलग किये जाने से सम्पूर्ण ग्रिड को रोका जा सकेगा

व/या जो ऊर्जा प्रदाय को पहले बनाए रखने के लिए समर्थ हो सकेगा, (2) जब महंगे उपकरणों की अधिक क्षति सन्निकट हो तथा अलग किये जाने से इससे बचा जा सके, (3) जब ऐसे पृथक किये जाने का अनुदेश विशेषकर एस.एल.डी.सी. द्वारा दिया गया हो। ग्रिड की सम्पूर्ण तुल्यकालिता यथाशीघ्र बनाए रखी जाएगी। यदि परिस्थितियां इसकी अनुमति देती हों, प्रतिस्थापना प्रक्रिया का पर्यवेक्षण पृथक रूप से विरचित परिचालन प्रक्रियाओं के अनुसार एस.एल.डी.सी. द्वारा किया जाएगा।

- (3) राज्य ग्रिड का कोई भी महत्वपूर्ण तत्व किसी भी समय जान-बूझकर काम करते समय खोला नहीं जाएगा या हटाया नहीं जाएगा, सिवाय इस प्रकार का अनुदेश विनिर्दिष्टतः एस.एल.डी.सी. द्वारा दिया जाए या एस.एल.डी.सी. की विनिर्दिष्ट व पूर्वानुमति हो। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रिड तत्वों की सूची जिस पर उपरोक्त अनुबन्ध लागू होंगे, एस.एल.डी.सी. द्वारा संघटकों के परामर्श से तैयार किये जाएंगे तथा एस.एल.डी.सी. में उपलब्ध होंगे। यदि आपातकालीन परिस्थिति में ग्रिड के किन्हीं महत्वपूर्ण तत्वों को खोलना/हटाना आवश्यक है, तो इसकी संसूचना घटना के तुरन्त पश्चात् एस.एल.डी.सी. को दी जाएगी।
- (4) राज्य ग्रिड के किन्हीं तत्वों की किसी भी प्रकार की ट्रिपिंग चाहे वह हाथ से हो या स्वचालित हो, की सूचना यथाशीघ्र अर्थात् घटना के दस मिनट के भीतर राज्य भार प्रेषण केन्द्र/अभिकरण द्वारा एस.एल.डी.सी. को दी जाएगी। कारण (अवधारित किये जाने तक) तय प्रतिस्थापन पर लगने के समय की सूचना भी दी जाएगी। तत्वों को यथास्थिति में लाने के लिए यथाशीघ्र सभी युक्तियुक्त प्रयास किये जाएंगे।
- (5) सभी उत्पादक यूनिटें जो 500 एम.डब्ल्यू. या उससे ऊपर की हैं, अपने स्वामित्व, आकार तथा प्रकार को ध्यान में रखे बिना, के पास सदैव सामान्य प्रचालन में अपने गवर्नर होंगे। यदि 50 मे.वा. से अधिक किसी उत्पादन यूनिट में सामान्य प्रचालन में अपने गवर्नर के बिना प्रचालित किये जाने की अपेक्षा की जाती है, तो एस.एल.डी.सी. तत्काल कारण व ऐसे प्रचालन की अवधि के बारे में सलाह देगा। सभी गवर्नर्स 3 प्रतिशत व 6 प्रतिशत के बीच में लटके हुए होंगे।
- (6) भार नियंत्रक स्वचालित टर्बाइन रन अप प्रणाली (ए.टी.आर.एस.) टर्बाइन पर्यवेक्षण नियंत्रण, समन्वित नियंत्रण प्रणाली आदि के भीतर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किसी भी रीति की सामान्य गवर्नर कार्यवाही को रोकने में नहीं किया जाएगा। कोई भी खराब बैंड व/या विलम्ब जान-बूझकर नहीं किया जाएगा।
- (7) सभी उत्पादक यूनिटें जो अपनी अधिकतम निरन्तर दर (एम.सी.आर.) के 100 प्रतिशत तक प्रचालित की जाती हैं, जब प्रणाली खराब होने के कारण फ्रीक्वेन्सी में कमी आती है, पांच प्रतिशत तक अतिभार को लगातार वहन करने में सामान्य समर्थ होगी (तथा किसी भी रूप में रोकी नहीं जाएगी)। ऐसी उत्पादक यूनिटें जो अपनी एम.सी.आर. के 100 प्रतिशत से ऊपर तक परिचालित की जाती हैं फ्रीक्वेन्सी के अकस्मात् कम होने पर अपनी एम.सी.आर. के 105 प्रतिशत तक चलने में समर्थ होंगी (तथा इससे रोकी नहीं जाएगी)। उपरोक्त के अनुसार उत्पादन में वृद्धि के पश्चात् उत्पादन यूनिटें प्रति मिनट लगभग एक प्रतिशत की दर पर अपने मूलस्तर पर कार्य करेंगी, यदि बढ़ाए गये स्तर पर निरन्तर प्रचालन कायम नहीं रहता है। उपरोक्त अपेक्षाओं का पालन न करने वाली 50 मेगावाट आकार की कोई भी उत्पादक यूनिट एस.एल.डी.सी. की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही (क्षेत्रीय ग्रिड के समकालिक) परिचालन में रखेगी। तथापि, संघटक को अन्य उत्पादक यूनिटों पर अतिरिक्त स्पिनिंग रिजर्व को बनाए रखने पर उसमें तत्स्थानी कमी कर सकती है।
- (8) गवर्नर सैटिंग अर्थात् सभी उत्पादक यूनिटों के लिए आउटपुट में वृद्धि या कमी करने के लिए अनुपूरक नियंत्रण अपने प्रकार या आकार के ध्यान में रखे बिना चार्जिंग के लिए तय दर प्रतिमिनट प्रतिशत या विनिर्माताओं की सीमाओं के अनुसार होगी। तथापि, फ्रीक्वेन्सी 49.5 एच.जेड. से कम होती है तो सभी लागत भारित उत्पादक यूनिटें अपनी क्षमता के अनुसार तीव्र दर पर अतिरिक्त भार उठावेंगी।

- (9) आपात कालीन या महंगे उपस्कर की हानि को रोकने के सिवाय, कोई भी संघटक एस.एल.डी.सी. को पूर्व सूचना दिये बिना या उसकी सहमति के बिना एक सौ से अधिक (100) मेगावाट तक अपनी उत्पादन यूनिट आउटपुट में अचानक कमी नहीं करेगा, विशेष कर जब फ्रीक्वेंसी कम हो रही हो या 49.0 एच.जेड. से कम हो। इसी प्रकार कोई भी संघटक एस.एल.डी.सी. को पूर्व सूचना दिये बिना या उसकी सहमति के बिना एक सौ (100) से अधिक मेगावाट तक अपने भार में अचानक कमी नहीं करेगा।
- (10) सभी उत्पादक यूनिटों के पास समुचित सैटिंग के साथ प्रचालन में स्वचालित वोल्टता रेगुलेटर होंगे। विशेषकर यदि 50 मेगावाट से अधिक की उत्पादन यूनिटों से सेवा में अपनी ए.वी.आर. के बिना प्रचालित किये जाने की अपेक्षा की जाती है तो एस.एल.डी.सी. को कारण तथा अवधि के बारे में तत्काल सूचना दी जाएगी व उसकी अनुमति प्राप्त की जाएगी। उत्पादन यूनिटों ए.वी.आर. में ऊर्जा प्रणाली स्थायीकारी (पी.एस.एस.) (जहां प्रदान किया जाए) समय-समय पर एस.टी.यू. द्वारा उस प्रयोजन के लिए तैयार की गयी योजना के अनुसार अपने-अपने उत्पादन यूनिट स्वामी द्वारा पर्याप्त रूप से प्राप्त किया जाएगा। एस.टी.यू., पी.एस.एस. की जांच करने की अनुज्ञा देगा जब कभी समझा जाए, ट्यूनिंग करेगा।
- (11) संरक्षण के उपबन्ध तथा रिले सैटिंग का समन्वय आर.पी.सी. की संरक्षण समिति द्वारा पृथकतः अंतिम रूप से दी जाने वाली योजना के अनुसार सम्पूर्ण राज्य ग्रिड में आवधिक रूप से किया जाएगा।
- (12) सभी राज्य संघटक यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे कि ग्रिड फ्रीक्वेंसी सदैव 49.0-50.5 एच.जेड. बैंड के भीतर रहे तथा फ्रीक्वेंसी रेंज ऐसी होगी जिससे आई.ई.सी. विनिर्देशों की पुष्टि करने वाले स्टीम टर्बाइन को निरन्तर व सुरक्षित रूप से प्रचालित किया जा सके।
- (13) आर.पी.सी. द्वारा पृथक रूप से अंतिम रूप दी गयी योजना के अनुसार, राज्यग्रिड के फेल व पृथक्करण की संभावित परिणति होने वाली फ्रीक्वेंसी घटत को रोकने के लिए जहां-कहीं लागू हो, अपनी-अपनी प्रणाली में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता स्वचालित निम्न फ्रीक्वेंसी व डी.एफ./डी.टी. रिले आधारित लोड शेडिंग/आईलैंडिंग योजना प्रदान करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि आकस्मिकता के समय उत्पादक यूनिटों की कास्केड ट्रिपिंग रोकने के लिए प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।
- (14) उपयोगकर्ता व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उप विनियम (13) में उल्लिखित अण्डर फ्रीक्वेंसी व डी.एफ./डी.टी. रिले आधारित लोड शेडिंग/आईलैंडिंग योजनाएं सदैव चलती रहें :
परन्तु, राज्य भार प्रेषण केन्द्र की पूर्व सहमति के तीव्र आकस्मिकता होने पर रिलेज को अस्थायी रूप से सेवा से पृथक रखा जाएगा।
- (15) राज्य पारेषण यूटिलिटी, अण्डर फ्रीक्वेंसी रिलेज का समय-समय पर निरीक्षण करेगी तथा इसकी रिपोर्ट राज्य भार प्रेषण केन्द्र को देगी। केन्द्र, अण्डर फ्रीक्वेंसी रिले व/या डी.टी./डी.एफ. रिले परिचालन का रिकॉर्ड रखेगा।
- (16) सभी राज्य संघटक वोल्टता अचानक कम होने व प्रपाती जैसी परिस्थितियों से बचने के लिए ऊर्जा प्रणाली में प्रणाली संरक्षण स्कीम (जिसमें अंतर ट्रिपिंग तथा रन बैक भी सम्मिलित है) की पहचान को सुकर बनाएंगे, उसका संस्थापन करेंगे तथा उन्हें लगाएंगे। ऐसी स्कीमों को एस.टी.यू. द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा तथा उन्हें जारी रखा जाएगा। यदि इनमें से कोई काम नहीं करता है तो एस.एल.डी.सी. को तुरन्त सूचित किया जाएगा।
- (17) ग्रिड में आंशिक/पूर्णतः विफल होने से उबरने के लिए प्रक्रियाएं तैयार की जाएंगी तथा उन्हें खण्ड 4.8 के अधीन अपेक्षाओं के अनुसार आवधिक रूप से अद्यतन रखा जाएगा। इन प्रक्रियाओं का सुसंगत विश्वसनीय व शीघ्र मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रीय संघटकों द्वारा अनुसरण किया जाएगा।

- (18) प्रत्येक राज्य संघटक ग्रिड की विश्वसनीयता तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक डाटा/जानकारी के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक रूप से तथा अन्य संघटकों/एस.एल.डी.सी. के साथ पर्याप्त तथा विश्वसनीय संसूचना सुविधा प्रदान करेंगे। जहां कभी संभव हो, महत्वपूर्ण मार्गों, जैसेकि ए.एल.डी.सी. से एस.एल.डी.सी. पर सम्प्रेषण हेतु प्रचुरता व वैकल्पिक मार्ग बनाए रखे जाएंगे।
- (19) क्षेत्रीय संघटक किसी ग्रिड बाधा/घटना के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए एस.एल.डी.सी. को सूचना/आंकड़े, जिसमें बाधा अभिलेखन/परिणामिक घटना, अभिलिखित आउटपुट आदि भी सम्मिलित हैं, भेजेंगे। राज्य संघटक ग्रिड की विश्वसनीयता तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए एस.एल.डी.सी. द्वारा अपेक्षित किन्हीं आंकड़ों/जानकारी को नहीं रोकेगा।
- (20) सभी राज्य संघटक यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे कि ग्रिड वोल्टेज सदैव निम्नलिखित रेंज के भीतर रहे:-

वोल्टेज- (के.वी.आर.एम.एस.)		
सामान्य	अधिकतम	न्यूनतम
400	420	360
220	245	200
132	145	120
66	73	60

4.3 प्रचालन प्रयोजन हेतु मांग प्राक्कलन :

4.3.1 परिचय :

- (1) यह खण्ड एक्टिव ऊर्जा व रिएक्टिव ऊर्जा के लिए मांग प्राक्कलन हेतु एस.एल.डी.सी. की प्रक्रियाओं व उत्तरदायित्वों को विहित करता है।
- (2) मांग प्राक्कलन वर्तमान वर्ष के लिए दैनिक/साप्ताहिक/मासिक आधार पर किया जाना होता है।
- (3) एस.एल.डी.सी. समय-समय पर ऐतिहासिक डाटा व मौसम पूर्वानुमान से स्वयं अपनी मांग का आकलन करेगा।
- (4) जबकि परिचालन प्रयोजनों के लिए मांग-प्राक्कलन प्रारम्भ में दैनिक/साप्ताहिक/मासिक आधार पर किया जाना होता है, एस.एल.डी.सी. पर क्रियाविधि व सुविधाएं, दैनिक परिचालन उपयोग हेतु ऑनलाईन आकलन की सुविधा शीघ्र संचालित की जाएगी।

4.3.2 उद्देश्य :

- (1) इस प्रक्रिया का उद्देश्य एक समय विशेष के लिए मांग का आकलन करने के लिए एस.एल.डी.सी. को सक्षम बनाना है।
- (2) मांग आकलन, परिचालन योजना उद्देश्यों हेतु प्रणाली अध्ययन संचालित करने के लिए एस.एल.डी.सी. को सक्षम बनाने के लिए हैं।

4.3.3 प्रक्रिया :

- (1) एस.एल.डी.सी. परिचालक उद्देश्यों के लिए दैनिक/साप्ताहिक/मासिक/वार्षिक मांग आकलन (एम, डब्ल्यू, एम.वी.ए.आर. व एम.डब्ल्यू.एच.) हेतु कार्य प्रणाली/क्रियाविधि विकसित करेगा तथा इसके लिए राज्य संघटकों का उत्तरदायित्व तय करेगा। इन आकलनों की प्राप्ति हेतु यह संबंधित तत्वों के मध्य सूचना के आदान-प्रदान हेतु अपनाये जाने वाली प्रक्रियाएं व समय लाइनें भी उपलब्ध करवाएगा।
- (2) आकलन हेतु डाटा में लोड शेडिंग, पावर कट इत्यादि भी सम्मिलित होंगे। एस.एल.डी.सी., मांग आकलन के लिए ऐतिहासिक डाटा बेस भी रखेगा।

4.4 मांग प्रबन्धन :

4.4.1 प्रस्तावना :

यह खण्ड अपर्याप्त उत्पादन क्षमता की दशा में, बाहरी अंतर संयोजनों से ऐसे अंतरण जो मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध नहीं हो रहे हों या ग्रिड के किसी भाग पर ब्रेकडाउन या प्रचालन संबंधी समस्याओं (जैसे फ्रीक्वेंसी, वोल्टता स्तर या थर्मल अधिकतम भार) की दशा में मांग की कटौती को प्रभावी बनाने एस.एल.डी.सी. द्वारा किये जाने वाले उपबंधों से संबंधित है।

4.4.2 मैनुअल मांग विसंयोजन :

- (1) जब कभी प्रणाली फ्रीक्वेंसी 49.5 एच.जेड. से कम हो, संघटक अपनी-अपनी निकासी अनुसूचियों के भीतर ग्रिड से अपनी कुल निकासी को निर्बन्धित करने का प्रयास करेंगे। जब फ्रीक्वेंसी 49.0 एच.जेड. से कम हो जाए तब अधिक निकासी में कमी करने के लिए राज्य में अपेक्षित लोडिंग की जाएगी।
- (2) कतिपय आकस्मिकताओं व/या प्रणाली की सुरक्षा को खतरे की दशा में एस.एल.डी.सी. कतिपय मात्रा तक निकासी में कमी करने के लिए उपयोगकर्ता को निर्देश देगा।
- (3) प्रत्येक राज्य संघटक ऐसी व्यवस्था करेंगे जो सामान्य व/या आकस्मिक परिस्थिति के अधीन एस.एल.डी.सी. द्वारा अनुमोदित मैनुअल विसंयोजन मांग करने में समर्थ होगी।
- (4) एस.एल.डी.सी. द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमति दिये बिना, ग्रिड से संघटक निकासी कम करने के उपाय वापस नहीं किये जाएंगे जब तक कि फ्रीक्वेंसी वोल्टेज निम्न स्तर पर रहती है।

4.5 आवधिक रिपोर्ट्स :

4.5.1 साप्ताहिक रिपोर्ट :

एस.एल.डी.सी. द्वारा राज्य के सभी संघटकों को एक साप्ताहिक रिपोर्ट जारी की जाएगी तथा इसमें पिछले सप्ताह के लिए राज्य ग्रिड का प्रदर्शन सम्मिलित होगा। ऐसी साप्ताहिक रिपोर्ट्स न्यूनतम 12 सप्ताह के लिए एस.एल.डी.सी. की वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगी। साप्ताहिक रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:-

- (i) फ्रीक्वेंसी विवरण,
- (ii) वयनित उपस्टेशनों का वोल्टेज विवरण,
- (iii) मांग व पूर्ति स्थिति,
- (iv) मुख्य उत्पादन व पारेषण,
- (v) पारेषण अवरोध।
- (vi) एस.जी.सी. के सतत/पर्याप्त अपालन की सार्थकता।

4.5.2 अन्य रिपोर्ट्स :

- (1) एस.एल.डी.सी. एक त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें अवरोध पैदा करने के उत्तरदायी अमिकरणों, विभिन्न अमिकरणों द्वारा की गयी विभिन्न कार्यवाहियों के विवरण के साथ, सुरक्षा मानकों व सेवा की गुणवत्ता की अपेक्षाओं, यदि कोई हैं, को पूरा न कर पाने के कारण, प्रणाली अवरोध सम्मिलित होंगे।
- (2) एस.एल.डी.सी., सूचना/रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएगा जिसे आई.ए.एस.टी.एस. के निर्विघ्न संचालन हेतु एस.टी.यू. द्वारा मांगा जा सकता है।

4.6 परिचालन संपर्क :

4.6.1 प्रस्तावना :

- (1) इस भाग में कुल ग्रिड प्रणाली पर परिचालन व/या घटनाओं के सम्बन्ध में सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु अपेक्षार्य सम्मिलित हैं जिनका निम्नलिखित पर प्रभाव रहा है या प्रभाव होगा—
 - (i) राज्य ग्रिड,
 - (ii) राज्य में आई.ए.एस.टी.एस.,
 - (iii) राज्य संगठक की प्रणाली।
- (2) उपरोक्त सामान्य रूप से यह अधिसूचित करने के सम्बन्ध में है कि क्या होने की सम्भावना है या क्या हुआ है न कि इसके होने के कारणों को।
- (3) परिचालक सम्पर्क कार्य, परिचालन स्टाफ को सूचना के तुरन्त अन्तरण की सुविधा हेतु एस.एल.डी.सी. व राज्य संगठकों का एक आज्ञापक अन्तर्निर्मित अधिक्रमिक कार्य है। यह निर्णय लेने व कार्यवाही के अनुकूलन हेतु अपेक्षित निर्विष्टों को सहसम्बन्धित करेगा।

4.6.2 परिचालनात्मक सम्पर्क हेतु प्रक्रिया :

- (1) राज्य ग्रिड पर परिचालन व घटनाएं:
 - (a) राज्य ग्रिड पर किसी परिचालन से पहले एस.एल.डी.सी. प्रत्येक राज्य संघटक को सूचित करेगा, जिसकी प्रणाली एक परिचालनात्मक प्रभाव अनुभव कर सकती है या करेगी तथा किये जाने वाले परिचालन का विवरण देगा।
 - (b) राज्य ग्रिड किसी घटना के तुरन्त पश्चात् एस.एल.डी.सी. प्रत्येक राज्य संघटक को सूचना देगा, जिसकी प्रणाली, घटना के कारण परिचालनात्मक प्रभाव अनुभव कर सकती है या करेगी तथा घटना में क्या हुआ है, इसका विवरण देगा न कि कारणों का।
- (2) संघटक की प्रणाली में परिचालन व घटनाएं:
 - (a) संघटक की प्रणाली में कोई परिचालन होने से पूर्व, संघटक एस.एल.डी.सी. को सूचना देगा, यदि राज्य ग्रिड कोई परिचालनात्मक प्रभाव अनुभव कर सकता हो या करेगा, तथा किये जाने वाले परिचालन का विवरण देगा।
 - (b) संघटक की प्रणाली पर किसी घटना के तुरन्त पश्चात् संघटक एस.एल.डी.सी. को सूचना देगा, यदि राज्य ग्रिड कोई परिचालनात्मक प्रभाव अनुभव कर सकता हो या करेगा तथा घटना में क्या हुआ, इसका विवरण देगा न कि कारणों का।

4.7 आउटटेज नियोजन :

4.7.1 परिचय :

- (1) इस भाग में, राज्य प्रणाली परिचालन परिस्थितियों व उत्पादन एवं मांग के सन्तुलन को ध्यान में रखते हुए समन्वित व अनुकूलक तरीके से राज्य ग्रिड के तत्वों हेतु आउटटेज अनुसूची की तैयारी के लिए प्रक्रिया बताई गयी है (इन अनुबन्धों के अधीन सम्मिलित किये गये ग्रिड के तत्वों की सूची तैयार की जाएगी व एस.एल.डी.सी. व ए.एल.डी.सी. के पास उपलब्ध होगी)।
- (2) उत्पादन आउटपुट व पारेषण प्रणाली, सुरक्षा मानक प्राप्त करने के लिए आउटटेज को हिसाब में लेते हुए, पर्याप्त होनी चाहिए।
- (3) वार्षिक आउटटेज योजना, एस.एल.डी.सी. द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम रूप से बनाई जाएगी तथा वर्ष के दौरान मासिक व त्रैमासिक रूप से इसकी समीक्षा की जाएगी।

4.7.2 उद्देश्य :

- (ए) सभी उपलब्ध संसाधनों पर विचार करते हुए व पारेषण अवरोधों तथा सिंचाई अपेक्षाओं का हिसाब लगाते हुए, राज्य ग्रिड के लिए एक समन्वित उत्पादन आउटटेज कार्यक्रम प्रस्तुत करना।
- (बी) ऊर्जा व एनर्जी की प्रणाली आवश्यकताओं में यदि कहीं कमी या बेशी है तो उसे न्यूनतम करना तथा सुरक्षा मानकों के भीतर परिचालन में सहायता करना।
- (सी) ग्रिड परिचालन पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले राज्य ग्रिड के तत्वों पारेषण आउटटेज को अनुकूल बनाना, किन्तु उत्पादन आउटटेज अनुसूची, एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/उपयोगकर्ता प्रणाली को हिसाब में रखते हुए तथा प्रणाली सुरक्षा मानक बनाए रखते हुए—

यह भाग एस.एल.डी.सी., ए.एल.डी.सी., पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों/उपयोगकर्ताओं, आई.ए.एस.जी.एस. व एस.टी.यू. सहित सभी राज्य संघटकों पर लागू होता है।

4.7.3 परिधि :

यह भाग सभी राज्य संघटकों, एस.एल.डी.सी., ए.एल.डी.सी. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/उपयोगकर्ता, आई.ए.एस.जी.एस. व एस.टी.यू. पर लागू होगा।

4.7.4 आउटटेज योजना प्रक्रिया :

- (1) एस.एल.डी.सी., सभी राज्य संघटकों द्वारा दी गयी आउटटेज अनुसूची के विश्लेषण, प्रारूप वार्षिक आउटटेज अनुसूची तैयार करने व प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी तक अगले वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक आउटटेज योजना को अन्तिम रूप देने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) सभी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/उपयोगकर्ता, आई.ए.एस.जी.एस. व एस.टी.यू., एस.एल.डी.सी. को प्रत्येक 31 अक्टूबर तक अगले वित्तीय वर्ष के लिए लिखित में अपने प्रस्तावित आउटटेज कार्यक्रम उपलब्ध करावेंगे। इनमें प्रत्येक उत्पादन यूनिट/लाइन/आई.सी.टी. को पहचान, प्रत्येक आउटटेज हेतु अधिमान्य तिथि तथा जहां-कहीं नम्यता हो वहां सर्वप्रथम प्रारम्भ तिथि व अंतिम समाप्ति की तिथि का समावेश होगा।
- (3) एस.एल.डी.सी. तब, आर.पी.सी. सचिवालय द्वारा दिये गये राज्य हेतु प्रारूप आउटटेज योजना, अनुकूल रूप में उपलब्ध संसाधन व सुरक्षा मानकों को बनाए रखने का हिसाब रखते हुए राज्य ग्रिड के लिए प्रत्येक वर्ष की 15 जनवरी तक अगले वित्त वर्ष हेतु एक प्रारूप आउटटेज कार्यक्रम लाएगा। ऐसा आवश्यक प्रणाली अध्ययन करने के पश्चात् किया जाएगा तथा, यदि आवश्यक हो, तो आउटटेज कार्यक्रम को पुनः अनुसूचित किया जाएगा। उत्पादन व भार आवश्यकता के मध्य पर्याप्त संतुलन, आउटटेज कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए, सुनिश्चित किया जाएगा।
- (4) अंतिम आउटटेज योजना की सूचना, आर.पी.सी. सचिवालय द्वारा तैयार, राज्य के लिए अंतिम आउटटेज योजना पर विचार करने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष विलम्बतः 15 फरवरी तक क्रियान्वयन हेतु सभी राज्य संघटकों को दी जाएगी।

- (5) उपरोक्त वार्षिक आउटटेज योजना की, सभी पक्षों के साथ समन्वय कर, त्रैमासिक व मासिक आधार पर एस.एल.डी.सी. द्वारा समीक्षा की जाएगी तथा जहां-कहीं आवश्यक हो, समाशोधन किया जाएगा।
- (6) प्रणाली में आपात स्थिति में जैसेकि उत्पादन में हानि, प्रणाली को प्रभावित करने वाला पारेषण का ब्रेकडाउन, ग्रिड के व्यवधान व प्रणाली का पृथक्करण होने पर एस.एल.डी.सी., नियोजित आउटटेज के पूर्ण होने से पहले पुनः अध्ययन संचालित करा सकता है।
- (7) एस.एल.डी.सी., निम्नलिखित में से किसी परिस्थिति में, सांविधिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, नियोजित आउटटेज को आस्थगित करने हेतु अधिकृत है:-
 - (i) बड़े ग्रिड व्यवधान (राज्य में पूर्ण ब्लैक आउट),
 - (ii) प्रणाली पृथक्करण,
 - (iii) संघटक प्रणाली में ब्लैक आउट,
 - (iv) प्रणाली में कोई अन्य घटना जिससे, प्रस्तावित आउटटेज द्वारा प्रणाली सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है :

परन्तु, राज्य भार प्रेषण केन्द्र यथा शीघ्र आउटटेज योजना में संशोधन हेतु उपयुक्त कारणों के साथ, संशोधित आउटटेज योजना के संबंध में संबंधित राज्य संघटक को सूचित करना होगा।

- (8) विस्तृत उत्पादन व पारेषण आउटटेज कार्यक्रम, नवीनतम वार्षिक आउटटेज योजना पर आधारित होना चाहिए (सभी अद्यतन समाशोधन के साथ)।
- (9) प्रत्येक राज्य संघटक, एक आउटटेज के उपयोग से पहले, एस.एल.डी.सी. से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करेगा।

4.8 बहाली प्रक्रियाएं :

- (1) आंशिक अथवा पूर्ण ब्लैक आउट के अन्तर्गत राज्यग्रिड की बहाली हेतु विस्तृत योजनाएं व प्रक्रियाएं, एस.एल.डी.सी. द्वारा, सभी राज्य संघटकों के साथ परामर्श कर, विकसित की जाएंगी तथा वार्षिक रूप से समीक्षा/अद्यतन की जाएंगी।
- (2) राज्य के भीतर प्रत्येक संघटक की प्रणाली के आंशिक/पूर्ण ब्लैक आउट के पश्चात् बहाली हेतु विस्तृत योजनाओं व प्रक्रियाओं को एस.एल.डी.सी. के साथ समन्वय कर संबंधित संघटक द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रक्रियाओं की प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष में एक बार समीक्षा, पुष्टि की जाएगी व/या संशोधन किया जाएगा। निम्न-निम्न उपस्टेशनों के लिए प्रक्रियाओं के कृत्रिम परीक्षण, एस.एल.डी.सी. को सूचना देकर, प्रत्येक छः माह में न्यूनतम एक बार संघटक द्वारा कराये जाएंगे।
- (3) ब्लैक स्टार्ट सुविधा वाले उत्पादक स्टेशनों, अन्तर्राज्यिक/अन्तरक्षेत्रीय जोड़ों, समकालिक बिंदुओं व प्राथमिक रूप से बहाल किये जाने वाले आवश्यक भारों की सूची एस.एल.डी.सी. द्वारा तैयार की जाएगी व उसके पास उपलब्ध होगी।
- (4) ब्लैक आउट के पश्चात् बहाली प्रक्रिया के दौरान ग्रिड की तीव्रतम सम्भावित बहाली प्राप्त करने के लिए वोल्टेज व फ्रीक्वेंसी हेतु आवश्यक सुरक्षा मानकों में कमी के साथ परिचालन हेतु एस.एल.डी.सी. को अधिकार है।
- (5) बहाली प्रक्रिया हेतु आवश्यक सभी सम्प्रेषण मार्ग, ग्रिड में सामान्य कार्य की बहाली तक केवल परिचालनात्मक संसूचना हेतु उपयोग किये जाएंगे।

4.9 घटना की सूचना :

4.9.1 प्रस्तावना :

इस भाग में सभी राज्य संघटकों व एस.एल.डी.सी./ए.एल.डी.सी. को प्रणाली में रिपोर्ट करने योग्य घटनाओं की लिखित में रिपोर्ट करने की प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं।

4.9.2 उद्देश्य :

इस भाग का उद्देश्य घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए सतत् दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु रिपोर्ट करने हेतु अपनाया जाने वाला मार्ग व आपूर्ति की जाने वाली सूचना रिपोर्ट की जाने वाली घटनाओं का विवरण देना है।

4.9.3 परिधि :

इस भाग में सभी संघटक, एस.एल.डी.सी. व ए.एल.डी.सी. सम्मिलित हैं।

4.9.4 उत्तरदायित्व :

- (1) यह एस.एल.डी.सी./ए.एल.डी.सी. का उत्तरदायित्व होगा कि वे राज्य संघटकों/एस.एल.डी.सी. को घटना की रिपोर्ट करें।
- (2) सभी राज्य संघटक व ए.एल.डी.सी. अनुवीक्षण, रिपोर्टिंग व घटना के विश्लेषण हेतु एस.एल.डी.सी. को सभी आवश्यक डाटा के संकलन व रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी होंगे।

4.9.5 रिपोर्ट योग्य घटनाएं :

एस.एल.डी.सी./राज्य संघटक से रिपोर्टिंग करने के लिए निम्नलिखित कोई एक घटना की अपेक्षा की जाती है :-

- (i) सुरक्षा मानकों का उल्लंघन,
- (ii) ग्रिड अनुशासनहीनता,
- (iii) एस.एल.डी.सी. के अनुदेशों का अपालन,
- (iv) प्रणाली आइलैंडिंग/प्रणाली स्प्लिट,
- (v) राज्य ब्लैक आउट/आंशिक प्रणाली ब्लैक आउट,
- (vi) आई.एस.टी.एस. के किसी तत्व पर संरक्षण विफलता,
- (vii) ऊर्जा प्रणाली अस्थिरता, तथा,
- (viii) राज्य ग्रिड के किसी तत्व के ट्रिप होने पर।

4.9.6 रिपोर्ट करने की प्रक्रिया :

- (1) एस.एल.डी.सी. को राज्य संघटकों द्वारा घटना की लिखित रिपोर्टिंग :

कोई घटना होने पर जो कि प्रारम्भ में मौखिक रूप से राज्य संघटक या एक ए.एल.डी.सी. द्वारा एस.एल.डी.सी. को रिपोर्ट की गयी थी, संघटक/ए.एल.डी.सी., इस भाग के अनुसार ए.एल.डी.सी. को एक लिखित रिपोर्ट देगा।

- (2) एस.एल.डी.सी. द्वारा राज्य संघटकों को घटनाओं की लिखित रिपोर्टिंग :

कोई घटना होने पर जो कि प्रारम्भ में मौखिक रूप से एस.एल.डी.सी. द्वारा संघटक/ए.एल.डी.सी. को रिपोर्ट की गयी थी, एस.एल.डी.सी., इस भाग के अनुसार संघटक/ए.एल.डी.सी. को एक साप्ताहिक रिपोर्ट देगा।

- (3) लिखित रिपोर्ट का प्रारूप :

यथास्थिति एस.एल.डी.सी. या एक राज्य संघटक/ए.एल.डी.सी. को एक लिखित रिपोर्ट भेजी जाएगी तथा यह घटना के निम्नलिखित विवरण के साथ मौखिक अधिसूचना की पुष्टि करेगी:-

- (i) घटना का समय व तिथि,
 - (ii) अवस्थान,
 - (iii) प्रत्यक्ष रूप से अंतर्वलित संयंत्र व/या उपकरण,
 - (iv) घटना का विवरण व कारण,
 - (v) पूर्वगामी परिस्थितियाँ,
 - (vi) मांग और/या बाधित उत्पादन (एम.डब्ल्यू में) व बाधित अवधि,
 - (vii) सभी सुसंगित प्रणाली डाटा जिसमें बाधा, अभिलिखित घटना, घटना लॉगर, डी.ए.एस. आदि सहित अभिलेख करने वाले उपकरणों के अभिलेखों की प्रतियाँ सम्मिलित हैं,
 - (viii) समय पर ट्रिप होने के अनुक्रम,
 - (ix) रिले फ्लैग्स का विवरण, तथा
 - (x) उपवारात्मक उपाय।
- (4) उत्पादक क्षमता को प्रभावित करने वाली घटनाएँ या 1000 एम.डब्ल्यू से अधिक भार, यथास्थिति, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या उपयोगकर्ता द्वारा आयोग को लिखित में तुरन्त रिपोर्ट की जाएंगी।

घटना का संक्षिप्त विवरण, विस्तार व संभावित कारणों सहित एक संक्षिप्त दस्तावेज, ऐसी घटना होने के 24 घण्टों के भीतर आयोग को भेजा जाएगा।

अध्याय 5-अनुसूची व प्रेषण संहिता

5.1 प्रस्तावना :

इस अध्याय में सम्मिलित हैं—

- (i) अनुसूची व प्रेषण में विभिन्न राज्य संघटकों व एस.एल.डी.सी. के मध्य उत्तरदायित्वों का सीमांकन।
- (ii) अनुसूची व प्रेषण हेतु प्रक्रिया।
- (iii) रिएक्टिव ऊर्जा व बोल्टेज नियंत्रण तंत्र।
- (iv) सम्पूरक वाणिज्यिक तंत्र (परिशिष्ट-1 में) जो कि उस तिथि से लागू होगा जो कि राज्य के भीतर ए.बी.टी. के परिचय हेतु आयोग द्वारा निर्धारित की जाए।

5.2 उद्देश्य :

यह संहिता, राज्य के आई.ए.एस.जी.एस./एस.एल.डी.सी./राज्य के फायदाग्राहियों के मध्य सूचना के प्रवाह की पद्धतियों के साथ दैनिक आधार पर संबंधित संघटकों को शुद्ध निकासी व राज्य के भीतर उत्पादक स्टेशनों (आई.ए.एस.जी.एस.) के अनुसूचीकरण हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का विवरण प्रदान करती है। प्रत्येक आई.ए.एस.जी.एस. द्वारा क्षमता की उद्घोषणा प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया तथा प्रत्येक लाभार्थी द्वारा निकासी अनुसूची, प्रत्येक आई.ए.एस.जी.एस. के लिए प्रेषण अनुसूची व प्रत्येक लाभार्थी के लिए निकासी अनुसूची तैयार करने हेतु एस.एल.डी.सी. को सक्षम करने हेतु आरक्षित है। यह रिएक्टिव ऊर्जा मूल्य निर्धारण हेतु तंत्र के साथ-साथ अनुसूची से विचलित होने के लिए वाणिज्यिक व्यवस्था के साथ आई.ए.एस.जी.एस. व लाभार्थियों को, यदि आवश्यक हो, वास्तविक समय प्रेषण/निकासी अनुदेश पुनः अनुसूचीकरण जारी करने की कार्यविधि भी प्रदान करता है। इस अध्याय में समावेशित उपबंध, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 30 व 31 के अधीन एस.एल.डी.सी. को प्रदत्त शक्तियों से कोई भेदभाव किये बिना हैं।

5.3 परिधि :

यह संहिता एस.एल.डी.सी./ए.एल.डी.सी., आई.ए.एस.जी.एस., पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों/एस.टी.यू. व राज्य ग्रिड में अन्य फायदाग्राहियों पर लागू होगी।

5.4 उत्तरदायित्वों का सीमांकन :

- (1) राज्य ग्रिड एक विनियोजित ऊर्जा मूल के रूप में परिचालित किया जाएगा (विकेन्द्रीकृत अनुसूचीकरण व प्रेषण के साथ) जिसमें उपयोगकर्ताओं को पूर्ण स्वायत्तता होगी तथा उपयोगकर्ताओं की अपने संबंधित ए.एल.डी.सी. के माध्यम से निम्नलिखित हेतु पूर्ण जिम्मेदारी होगी:-
 - (i) अपने स्वयं के उत्पादन का अनुसूचीकरण/प्रेषण (अपनी अंतःसंयोजित अनुज्ञप्तियों सहित),
 - (ii) अपने ग्राहकों की मांग विनियमित करना,
 - (iii) आई.ए.एस.जी.एस. से अपनी निकासी का अनुसूचीकरण (संबंधित संयंत्र की अपेक्षित क्षमता में अपने भाग के भीतर),
 - (iv) किन्हीं द्विपक्षीय आपसी विनियम की व्यवस्था करना, तथा
 - (v) निम्नलिखित मार्गदर्शकों के अनुसार राज्य ग्रिड से अपनी शुद्ध निकासी को विनियमित करना।
- (2) प्रत्येक फायदाग्राहियों की प्रणाली सैद्धांतिक रूप से नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में समझी तथा प्रचलित की जाएगी। आई.ए.एस.जी.एस. से अनुसूचित निकासी के बीजीय संकलन तथा किसी द्विपक्षीय अंतरविनियम प्रत्येक लाभार्थी की निकासी अनुसूची को प्रदान करेगा तथा इसे दैनिक आधार पर अग्रिम में अवधारित किया जाएगा। जबकि लाभार्थियों से साधारणतः अपने उत्पादन व/या ग्राहकों को विनियमित करने की आशा की जाएगी जिससे कि उपरोक्त अनुसूची के निकट क्षेत्रीय ग्रिड से उनकी वास्तविक निकासी को बनाए रखा जा सके तथा कठोर नियंत्रण आज्ञापक न हो। लाभार्थी अपने स्वविवेक से, निकासी अनुसूची से विचलित हो सकते हैं जब तक कि विचलन अनुज्ञेय सीमा से परे हास हो जाने पर प्रणाली पैरामीटर का कारण नहीं बनता व/या अस्वीकार्य लाईन लोडिंग को प्रेरित नहीं करता।
- (3) उपरोक्त लचीलेपन का प्रस्ताव इस दृष्टि से किया गया है कि सभी लाभार्थियों के पास राज्य ग्रिड से वास्तविक कुल निकासी को मिनट प्रति मिनट ऑन लाईन विनियमित करने के लिए सभी अपेक्षित सुविधाएं नहीं हैं। तथापि, कुल निकासी अनुसूची से विचलन की अनुसूचित अंतरविनियम (यू.आई.) तंत्र के माध्यम से पर्याप्त कीमत तय की जानी है, जिसके लिए कीमत, आयोग द्वारा अन्तर्राज्यीय ए.बी.टी. प्रारम्भ किये जाने की तिथि से लागू होगी।
परन्तु, यह कि लाभार्थी अपने ए.एल.डी.सी. के माध्यम से अपनी-अपनी निकासी अनुसूचियों के भीतर ग्रिड से उनकी कुल निकासी को निर्बन्धित करने का सदा प्रयास करेंगे, जब कभी प्रणाली की फ्रीक्वेंसी 49.5 एच.जेड. से निम्न हो जाए। फ्रीक्वेंसी के 49.0 एच.जेड. से निम्न हो जाने पर, अधिक निकासी में कमी करने के लिए संबंधित लाभार्थियों की अपेक्षित लोड शेडिंग की जाएगी।
- (4) एस.एल.डी.सी./एस.टी.यू. अपने-अपने राज्यों के लिए अग्रिम में योजना के लिए उनको समर्थ बनाने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन मांग प्राक्कलन के बारे में हमेशा प्रयोग करेगा कि कैसे ग्रिड से अधिक निकासी लिये बिना अपने ग्राहक के भार को पूरा करेंगे।
- (5) आई.एस.जी.एस., एस.एल.डी.सी. से प्राप्त अध्यापेक्षा के आधार पर लाभार्थियों/ए.एल.डी.सी. द्वारा उनको दी गयी दैनिक अनुसूचियों के अनुसार ऊर्जा उत्पादन तथा अपने उत्पादन केन्द्रों के पर्याप्त प्रचलन तथा रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होगा जिससे कि ये केन्द्र बेहतर सम्भव दीर्घकालिक उपलब्धता और मितव्ययता की पूर्ति कर सकें।
- (6) जबकि आई.ए.एस.जी.एस. से सामान्य रूप से यह आशा की जाएगी कि वे उनको दी गयी दैनिक सलाह अनुसूचियों के अनुसार ऊर्जा का उत्पादन करें तथा कड़ाई से अनुसूचियों का पालन करना आवश्यक नहीं है। राज्य को अनुज्ञात छूट के आधार पर आई.ए.एस.जी.एस. संयंत्र तथा प्रणाली के हालात पर निर्भर करते हुए दी गयी अनुसूचियों से भी विचलन कर सकेगा। विशेषकर वे अभाव की दशा में भी दी गयी अनुसूची से परे उत्पादन करने के लिए अनुज्ञात होंगे तथा प्रोत्साहित करेंगे।

तथापि, जब कभी राज्य के भीतर आयोग द्वारा ए.बी.टी. प्रारम्भ की जाएगी, एक्स ऊर्जा संयंत्र उत्पादन अनुसूचियों से विचलन की कीमत यू.आई. तंत्र के माध्यम से पर्याप्त रूप से तय की जाएगी:

परन्तु, यह कि जब फ्रीक्वेन्सी 50.5 से अधिक है तो वास्तविक कुल इन्जेक्शन उस समय के लिए अनुसूचित प्रेषण से अधिक नहीं होगा और, जब फ्रीक्वेन्सी 50.5 एच.जेड. है तब आई.ए.एस.जी.एस. (अपने स्वविवेक से) बढ़ी हुई फ्रीक्वेन्सी को निर्बन्धित करने के लिए एस.एल.डी.सी. से सलाह का इंतजार किये बिना फ्रीक्वेन्सी को कम कर सकेगा। जब फ्रीक्वेन्सी 49.5 एच.जेड. से कम होती है तो सभी आई.ए.एस.जी.एस. पर (व्यस्ततम ड्यूटी करने वालों के सिवाय) उत्पादन को उस स्तर पर बढ़ाया जाएगा जिस स्तर पर वह एस.एल.डी.सी. से सलाह किये बिना कायम रख सकता है।

- (7) तथापि, उपरोक्त में किसी के होते हुए भी एस.एल.डी.सी., आकस्मिकता अर्थात् लाईन/ट्रांसफॉर्मर की अधिक लोडिंग, असामान्य वोल्टता प्रणाली सुरक्षा को घमकी की दशा में ए.एल.डी.सी./आई.ए.एस.जी.एस. को अपनी निकासी/उत्पादन में वृद्धि करने/कमी करने का निर्देश दे सकेगा। ऐसे निर्देशों पर शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी। यदि स्थिति पर तुरन्त कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है और एस.एल.डी.सी. के पास विश्लेषण करने के लिए कुछ समय है तो वह इस बात की जांच करेगा कि क्या ऐसी स्थिति अनुसूचियों से विचलन के कारण उत्पन्न दृष्टि या अल्पकालीन खुली पहुंच की अनुसरण में किसी ऊर्जा प्रवाह के कारण उत्पन्न हुई है। कोई ऐसी कार्यवाही करने से पहले उपरोक्त अनुक्रम में पहले उसे दूर किया जाएगा जिससे प्रारम्भिक रूप से दीर्घकालिक ग्राहकों को आई.ए.एस.जी.एस. से अनुसूचित प्रदाय प्रभावित होगा।
- (8) ऐसे उत्पादन तथा पारेषण प्रणाली के सभी आउटलेजों के लिए, जिससे राज्य ग्रिड पर प्रभाव पड़ेगा, सभी संघटक एक-दूसरे के साथ समन्वय करेंगे तथा एस.एल.डी.सी. (सभी अन्य मामलों में) के माध्यम से अग्रिम में पर्याप्त रूप से कल्पित आउटलेज के लिए तथा ग्रिड समन्वय समिति (जी.सी.सी.) द्वारा पृथक् रूप से तैयार प्रक्रियाओं के अनुसार ग्रिड समन्वय समिति (जी.सी.सी.) के माध्यम से समन्वय करेगा। विशेषकर, आई.ए.एस.जी.एस./आई.एस.जी.एस. अंश के निर्बंधन, जो फायदाग्राही पर लगाए जा सकते हैं (और जो एक वाणिज्यिक विविधा हो सकेगी) की योजना बेहतर रीति से पूर्ति करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की जाएगी।
- (9) राज्य संघटक, आई.ए.एस.जी.एस./आई.एस.जी.एस. परियोजनाओं (उचित सरकार/आयोग द्वारा आवंटन के आधार पर, जहां लागू हो) अनुसूचित निकासी पैटर्न, टैरिफ, संदाय निर्बंधनों आदि में राज्य के अंशों की पहचान करने के लिए पृथक् संयुक्त/विपक्षीय करार करेंगे। ऐसी सभी करार अनुसूची और राज्य ऊर्जा लेखांकन में किये जाने के लिए एस.एल.डी.सी. में फाईल किये जाएंगे। दीर्घकालिक/अल्पकालिक आधार पर अनुसूचित अंतर विनिमय के लिए संघटकों के बीच द्विपक्षीय कोई भी करार अंतर विनिमय अनुसूची को भी विनिर्दिष्ट करेगा जिसे एस.एल.डी.सी. के पास अग्रिम में सम्यक् रूप से फाईल किया जाएगा।
- (10) सभी संघटकों को अनुसूचियों से अर्थात् अंतर विनिमय से फ्रीक्वेन्सी लिंकड भार प्रेषण और विचलन की कीमत की संकल्पना का पालन करना चाहिए (कीमत, राज्य के भीतर ए.बी.टी. के प्रारम्भ होने की तिथि से)। संघटकों की सभी उत्पादन यूनिटें जब तक एस.एल.डी.सी./ए.एल.डी.सी. द्वारा अन्यथा सलाह न दी जाए, एक संभव सीमा तक एस.एल.डी.सी. द्वारा जारी किये गये स्थायी फ्रीक्वेन्सी लिंकड भार प्रेषण मार्गदर्शन सिद्धान्तों के अनुसार सामान्य रूप से प्रचलित किये जाने चाहियें।
- (11) आई.ए.एस.जी.एस. के लिए यह आवश्यक होगा कि वह निष्ठापूर्वक संयंत्र क्षमताओं, अर्थात् उनके बेहतर निर्धारण के अनुसार, को घोषित करे। यदि यह आशंका है कि वे अपनी घोषित क्षमता के आधार पर दी गयी अनुसूचियों से विचलित करने के लिए अनुध्यात संयंत्र क्षमता को जान-बूझकर अधिक/कम घोषित करते हैं (और इस प्रकार से असम्यक् क्षमता प्रभार या अनुसूची से विचलन के लिए भार के रूप में धन कमाते हैं) तो एस.एल.डी.सी., आई.ए.एस.जी.एस. से आवश्यक बैंकअप आंकड़ों की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकेगा।
- (12) एस.टी.यू. वास्तविक कुल एम.डब्ल्यू.एच. अंतर विनिमय और एम.डब्ल्यू.ए. निकासी को अभिलिखित करने के लिए राज्य संघटकों या अन्य पहचाने गये स्थानों के बीच सभी अंतर संयोजनों पर विशेष ऊर्जा मीटर लगाएगा। लगाए जाने वाले मीटरों का प्रकार, मीटरिंग स्कीम, मीटरिंग क्षमता, जांच तथा व्यास मापन अपेक्षाएं तथा मीटरित आंकड़ों का प्रसार व संग्रहण, अधिनियम की धारा 54 (2) (डी) के अधीन प्राधिकारी द्वारा जारी मीटरों के संस्थापन व परिचालन हेतु विनियमों के अनुसार किया जाएगा। सभी संबंधित

इकाईयां (जिनके परिसर में विशेष ऊर्जा मीटर लगाए गये हैं) एस.टी.यू./एस.एल.डी.सी. के साथ पूर्ण सहयोग करेंगी तथा साप्ताहिक मीटर रीडिंग लेने व पारेषित करने के लिए एस.एल.डी.सी. को आवश्यक सहायता देगी।

- (13) एस.एल.डी.सी. उपरोक्त मीटर रीडिंग के आधार पर, 15 मिनट बाद प्रत्येक आई.ए.एस.जी.एस. के वास्तविक कुल एम.डब्ल्यू.एच. इन्जेक्शन और प्रत्येक फायदाग्राही की वास्तविक कुल निकासी की संगणना के लिए तथा राज्य ऊर्जा लेखा तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा। एस.एल.डी.सी. के द्वारा की गयी सभी संगणनाएं जांच और सत्यापन के लिए सभी संघटकों हेतु 15 दिनों की अवधि के लिए खुली रहेंगी। यदि किसी गलती/लोप का पता चलता है तो एस.एल.डी.सी. तत्काल पूरी जांच करेगा और त्रुटियों को दूर करेगा।
- (14) एस.एल.डी.सी. जांच के लिए जारी किये जाने वाले प्रेषण तथा कुल निकासी अनुसूचियों से वास्तविक रूप से विचलन का आवधिक रूप पुनर्विलोकन करेगा चाहे कोई भी संघटक अनुचित कार्य या दुरभिसंधि संगलिप्त होता है। यदि ऐसे किसी कार्य का पता चलता है तो मामले को अन्वेषण/कार्यवाही के लिए एस.टी.यू. को रिपोर्ट किया जाएगा।
- (15) यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास ऐसा आपूर्ति क्षेत्र है जिसमें आई.ए.एस.जी.एस. अवस्थित है, उसका आई.ए.एस.जी.एस. में प्रमुख शेरर है तो संबंधित पक्ष मार संबंधित एस.एल.डी.सी. को आई.ए.एस.जी.एस. के अनुसूचीकरण करने की जिम्मेदारी को समानुदेशित करने के लिए परस्पर करार (प्रचलनात्मक सुविधा के लिए) कर सकेंगे। ऐसे मामलों में एस.एल.डी.सी. की भूमिका संबंधित फायदाग्राहियों की कुल निकासी अनुसूचियों का अवधारण करते समय आई.ए.एस.जी.एस. के कारण ऊर्जा के अंतरराज्यिक विनिमय के लिए अनुसूची पर विचार करने हेतु सीमित होगी।

5.5 अनुसूची तथा प्रेषण प्रक्रिया :

- (1) सभी प्रदेशान्तर्गत उत्पादक स्टेशन (आई.ए.एस.जी.एस.) व अन्तरराज्यिक उत्पादक स्टेशन (आई.एस.जी.एस.) जिनमें आउटपुट में एक से अधिक फायदाग्राही का आवंटित/संविदागत शेरर है, सूचीबद्ध किये जाएंगे। परन्तु यह कि फायदाग्राहियों के मध्य आई.एस.जी.एस./आई.ए.एस.जी.एस. में राज्य के आवंटित शेरर का विभाजन उस अनुपात में होगा जो कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए।
- (2) प्रत्येक फायदाग्राही ऐसे सभी केन्द्रों के लिए (दिन के लिए अनुमानित एक ऊर्जा संयंत्र एम.डब्ल्यू. क्षमता) ग (केन्द्र की क्षमता में फायदाग्राही का अंश) तक मेगावाट प्रेषण के लिए हकदार होंगे। हाइड्रो विद्युत केन्द्रों की दशा में, (ट्रिप के लिए एम.डब्ल्यू.एच. उत्पादन क्षमता) ग (स्टेशनों की क्षमता में फायदाग्राहियों का अंश) के बराबर दैनिक एम.डब्ल्यू.एच. प्रेषण तक भी सीमित होंगे।
- (3) प्रत्येक दिन 10:00 बजे तक आई.ए.एस.जी.एस. अगले दिन अर्थात् आगामी दिन 00:00 बजे से 24:00 बजे तक के लिए एस.एल.डी.सी. को स्टेशनवार एक्स ऊर्जा संयंत्र मेगावाट और अनुमानित एम.डब्ल्यू.एच. क्षमता की सलाह देगा।
- (4) आर.एल.डी.सी. द्वारा दिये गये विभिन्न आई.एस.जी.एस. में राज्य को हकदारी व प्रत्येक फायदाग्राही की तत्स्थानी एम.डब्ल्यू. व एम.डब्ल्यू.एच. हकदारों के साथ आई.ए.एस.जी.एस., एस.एल.डी.सी. की अनुमानित क्षमताओं की उपरोक्त जानकारी अगले दिन के लिए प्रत्येक दिन एस.एल.डी.सी. द्वारा अनुपालन किया जाएगा तथा 11:00 बजे सभी फायदाग्राहियों को इसके संबंध में सलाह दी जाएगी। फायदाग्राही इसका अनुमानित मार पैटर्न और अपनी स्वयं की उत्पादन क्षमता जिसमें द्विपक्षीय आदान-प्रदान भी सम्मिलित है, कर पुनर्विलोकन करेंगे तथा एस.एल.डी.सी. को प्रत्येक के आई.ए.एस.जी.एस. के लिए उनकी निकासी अनुसूची के बारे में 1:00 बजे दोपहर तक सलाह देगा जिसमें वे द्विपक्षीय आदान-प्रदान, अनुमोदित अल्पकालीन द्विपक्षीय आदान-प्रदान तथा द्विपक्षी अंतर विनिमय के आगे के दिन के लिए खुली पहुंच तथा अनुसूचीकरण हेतु संयुक्त अनुरोध करेंगे।
- (5) परन्तु, यह कि अन्तरराज्यिक संयोजनों के माध्यम से संयंत्रवार निकासी/द्विपक्षी विनिमय हेतु फायदाग्राही की हकदारी, यदि परिचालनात्मक रूप से सुविधाजनक व शोध्य है, तो यह एस.एल.डी.सी. द्वारा एक साथ निर्धारित की जाएगी।

- (6) फायदाग्राही एस.एल.डी.सी. को ऐसे स्थायी आदेश भी देंगे कि एस.एल.डी.सी. फायदाग्राहियों के लिए निकासी सूची के लिए स्वयं विनिश्चय कर सकेगी।
- (7) प्रत्येक दिन 6:00 बजे तक, आर.एल.डी.सी. द्वारा सूचित रूप में राज्य हेतु प्रेषण अनुसूची तथा शुद्ध निकासी अनुसूची पर विचार करने के पश्चात् एस.एल.डी.सी.-
 - (i) अगले दिन के लिए, विभिन्न घण्टों हेतु एम.डब्ल्यू में प्रत्येक आई.ए.एस.जी.एस. को एक्स ऊर्जा संयंत्र "प्रेषण अनुसूची" के बार में बतलाएगा। सभी फायदाग्राहियों को दी गयी एक्स ऊर्जा संयंत्र निकासी अनुसूची की अंतिम सलाह एक्स ऊर्जा संयंत्र ऊर्जा केन्द्रवार प्रेषण अनुसूची को बताएगी।
 - (ii) अगले दिन के लिए, विभिन्न घण्टों के लिए प्रत्येक ग्राही हेतु "कुल निकासी अनुसूची" को बताएगा। पारेषण हानियों में कटौती करने के पश्चात् (अनुमानित) सभी आई.ए.एस.जी.एस./आई.एस.जी.एस. के लिए स्टेशनवार एक्स ऊर्जा संयंत्र निकासी अनुसूची तथा द्विपक्षीय अंतर विनिमय के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय ग्रिड की निकासी अनुसूची के बारे में बताएंगे।
- (8) जब आई.ए.एस.जी.एस., एस.एल.डी.सी. के लिए उपरोक्त दैनिक प्रेषण अनुसूचियों को अंतिम रूप देते समय एस.एल.डी.सी. यह सुनिश्चित करेगा कि यह प्रचालनात्मक रूप से युक्तियुक्त है, विशेषकर अनियंत्रित घटती/बढ़ती दरों तथा अधिकतम व न्यूनतम उत्पादन केन्द्रों के बीच अनुपात के अनुसार है। 200 मेगावाट प्रति घण्टे की अनियंत्रित दर आई.ए.एस.जी.एस. तथा राज्य संघटकों के लिए साधारणतः स्वीकार्य होनी चाहिए। सिवाय उन हाइड्रो विद्युत उत्पादन केन्द्रों के जो तीव्र दर पर अनियंत्रित बढ़ती/घटती दर के लिए समर्थ हो सकेंगे।
- (9) फायदाग्राही/आई.ए.एस.जी.एस. स्टेशनवार निकासी अनुसूची तथा द्विपक्षीय अंतर विनिमय/अनुमानित क्षमताओं, यदि कोई हों, में किये जाने वाले किन्हीं उपांतरणों/परिवर्तनों के बार में एस.एल.डी.सी. को सायं 9:00 बजे तक सूचित करेंगे।
- (10) ऐसी जानकारी की प्राप्ति पर एस.एल.डी.सी. संबंधित संघटकों से परामर्श करने के पश्चात् प्रत्येक फायदाग्राही को अंतिम "निकासी अनुसूची" तथा प्रत्येक आई.ए.एस.जी.एस. को अंतिम प्रेषण अनुसूची रात 11:30 बजे तक जारी करेगा।
- (11) और, अगले दिन के लिए पहले से पता अधिशेषों के आधार पर, संघटक द्विपक्षीय आदान-प्रदान के लिए व्यवस्था कर सकेंगे, ऐसी व्यवस्थाओं के लिए अनुसूचियों के बार में एस.एल.डी.सी. को रात 9:00 बजे तक सूचित किया जाएगा, जो 11:30 बजे रात्रि तक अंतिम प्रेषण/निकासी अनुसूचियों को जारी करते समय इन तय करारों की गणना में लेगा, परन्तु जो पारेषण अवरोधों को बढ़ावा नहीं देंगे व आर.एल.डी.सी. को जिन पर आपत्ति नहीं होगी।
- (12) उपरोक्त निकासी तथा प्रेषण अनुसूचियों को अंतिम रूप देते समय, एस.एल.डी.सी. यह भी जांच करेगा कि ऊर्जा प्रवाह के परिणाम स्वरूप किन्हीं पारेषण अवरोधों में वृद्धि नहीं होती है। यदि किसी अवरोध का पता चलता है, एस.एल. संबंधित संघटकों को सूचना देते हुए अपेक्षित सीमा तक अनुसूचियों को संतुलित करेगी। ऊर्जा की अनुसूचित मात्रा में किसी भी परिवर्तन को, जो बहुत तेजी से होता है या अस्वीकार्य वृहद् उपायों में सम्मिलित होता है, एस.एल.डी.सी. उपयुक्त रैम्प में संपरिवर्तित कर सकेगा।
- (13) यूनिट के प्रबलित आउटेटज की दशा में, एस.एल.डी.सी. पुनरीक्षित घोषित क्षमता के आधार पर अनुसूचियों को पुनरीक्षित करेगा। पुनरीक्षित घोषित क्षमता और पुनरीक्षित अनुसूचियां उस समय ब्लॉक को जिसमें आई.ए.एस.जी.एस. द्वारा पुनरीक्षण किये जाने की एक बार सलाह दी जाती है, गणना में लेते हुए छठे समय ब्लॉक से प्रभावी हो जाएगी।
- (14) ग्रिड राज्य पारेषण उपयोगिता या किसी अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, जो उत्पादन में आवश्यक कमी करने के लिए प्रदेशान्तर्गत पारेषण (एस.एल.डी.सी. द्वारा यथा प्रमाणित) में अन्तर्वलित हों, के स्वामित्वाधीन किसी पारेषण प्रणाली, सहबद्ध स्विचगार्ड और उपकेन्द्रों में किसी अवरोध, आउटेटज, असफलता तथा परिसीमा के कारण ऊर्जा के निकास में अवरोध की दशा में, एस.एल.डी.सी. अनुसूचियों को पुनरीक्षित करेगा जो ऐसे समय ब्लॉक, जिसमें ऊर्जा के निकास में अवरोध पहली बार उत्पन्न हुए

हों, की गणना करते समय छठे ब्लॉक से प्रभावी हो जाएंगे और ऐसे घटना के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तथा पांचवें समय ब्लॉक के दौरान ए.आई.एस.जी.एस. का अनुसूचित उत्पादन वास्तविक उत्पादन के बराबर किये जाने के लिए पुनरीक्षित किया गया समझा जाएगा तथा फायदाग्राहियों की अनुसूचित निकासी को उनकी वास्तविक निकासी के बराबर किये जाने के लिए पुनरीक्षित किया गया समझा जाएगा।

- (15) किसी ग्रिड बाधा की दशा में सभी ए.आई.एस.जी.एस. का अनुसूचित उत्पादन तथा सभी फायदाग्राहियों का अनुसूचित निकासी ग्रिड बाधाओं द्वारा प्रभावित सभी समय ब्लॉकों के लिए उनके वास्तविक उत्पादन/निकासी के बराबर किये जाने के लिए पुनरीक्षित की गयी समझी जाएगी। ग्रिड बाधा तथा उसकी अवधि का प्रमाणन एस.एल.डी.सी. द्वारा किया गया समझा जाएगा।
- (16) आई.ए.एस.जी.एस. द्वारा घोषित क्षमता का पुनरीक्षण तथा दिन की शेष अवधि के लिए फायदाग्राहियों द्वारा अध्यपेक्षा की अग्रिम सूचना के साथ अनुज्ञात की जाएगी। ऐसे मामलों में, पुनरीक्षित अनुसूचियां/घोषित क्षमताएं उस समय ब्लॉक, जिसमें एस.एल.डी.सी. में एक बार पुनरीक्षण करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ हो, को गणना में लेते हुए आठवें समय ब्लॉक से प्रभावी हो जाएंगे।
- (17) यदि किसी समय बिंदु पर, एस.एल.डी.सी. समझता है कि बेहतर प्रणाली ऑपरेशन के हित में अनुसूचियों का पुनरीक्षण किये जाने की आवश्यकता है तो वह स्वयं ऐसा कर सकेगा और ऐसे मामलों में, पुनरीक्षित अनुसूचियां उस समय ब्लॉक, जिसमें एस.एल.डी.सी. द्वारा एक बार अनुसूची को पुनरीक्षित किया गया है, को गणना में लेते हुए, छठे समय ब्लॉक से प्रभावी हो जाएंगी।
- (18) तुच्छ पुनरीक्षण को हतोत्साहित करने के लिए एस.एल.डी.सी. अपने एकमात्र विलेख से पूर्व अनुसूची/क्षमता के दो प्रतिशत से अन्यून अनुसूची/क्षमता प्रभारों को स्वीकार करने से इन्कार कर सकेगा।
- (19) प्रचालन दिन के 24 घण्टे की समाप्ति के पश्चात् दिन के दौरान अंतिम रूप से लागू अनुसूची (उत्पादन की प्रेषण अनुसूची) में तथा फायदाग्राहियों की निकासी अनुसूची में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए एस.एल.डी.सी. द्वारा जारी की जाएगी। ये अनुसूचियां वाणिज्यिक लेखांकन के आधार पर होंगी। प्रत्येक ए.आई.एस.जी.एस. के लिए औसत एक्ट बस क्षमता को एस.एल.डी.सी. की सलाह के आधार पर निकाला जाएगा।
- (20) एस.एल.डी.सी. सभी उपरोक्त जानकारी, अर्थात् उत्पादन केन्द्रों द्वारा केन्द्रवार अनुमानित एक्स ऊर्जा संयंत्र क्षमता सलाह, फायदाग्राहियों द्वारा विवेचित निकासी अनुसूचियों, एस.एल.डी.सी. द्वारा जारी सभी अनुसूचियों तथा उपरोक्त के सभी पुनरीक्षणों/अद्यतनों का प्रलेखन करेगा।
- (21) एस.एल.डी.सी. द्वारा जारी अनुसूचीकरण तथा अंतिम अनुसूचियों की प्रक्रिया किसी जांच/सत्यापन के लिए 5 दिनों के लिए सभी संघटकों हेतु खुली रहेंगी। यदि किसी त्रुटि/लोप का पता लगता है तो एस.एल.डी.सी. तत्काल उस की पूरी जांच करेगा तथा उसे दूर करेगा।
- (22) आई.ए.एस.जी.एस. द्वारा उपलब्धता घोषणा करते समय एक मेगावाट और एक मेगावाट घण्टे सभी हकदारियों तथा अध्यपेक्षाओं का प्रस्ताव किया जा सकेगा तथा अनुसूचियों को 0.7 मेगावाट के प्रस्ताव के लिए निकटतम दशमलव में पूर्णांकित किया जाएगा।

5.6 रिएक्टिव ऊर्जा तथा वोल्टता नियन्त्रण :

- (1) रिएक्टिव ऊर्जा प्रतिकर को यथासंभव रिएक्टिव ऊर्जा खपत को स्थानीय रूप में रिएक्टिव उत्पादन करने वालों द्वारा सामान्य रूप से आदर्शतः प्रदान किया जाना चाहिए। अतः फायदाग्राहियों से आशा की जाती है कि सामान्य ए.वी.आर. प्रतिकर/उत्पादन प्रदान करें जिससे कि वे ई.एच.वी. ग्रिड से विशेषकर निम्न वोल्टता की दशा में ए.वी.आर. की निकासी न कर सकें। तथापि वर्तमान परिसीमाओं पर विचार करते हुए, इसके लिए जोर नहीं दिया जा रहा है। फायदाग्राहियों द्वारा ए.वी.आर. निकासियों को हतोत्साहित करने के बजाए आई.एस.टी.एस. के ए.वी.आर. विनियमों की निम्नलिखित रूप में कीमत तय की जाएगी:-

- (i) फायदाग्राही ए.वी.आर. निकासी के लिए तब संदाय करेंगे, जब मीटरिंग बिन्दु पर वोल्टता 97 प्रतिशत से कम हो।
- (ii) फायदाग्राही को ए.वी.आर. रिटर्न के लिए संदत्त किया जाएगा, जब वोल्टता 97 प्रतिशत से कम हो।
- (iii) फायदाग्राही को ए.वी.आर. निकासी के लिए तब संदाय किया जाएगा, जब वोल्टता 103 प्रतिशत से अधिक है।
- (iv) फायदाग्राही ए.वी.आर. रिटर्न के लिए तब संदत्त करेंगे, जब वोल्टता 103 प्रतिशत से अधिक है:

परन्तु यह कि आई.ए.एस.जी.एस. से सीधे मिलने वाली अपनी स्वयं की लाईन पर फायदाग्राही द्वारा वी.ए.आर. निकासी/रिटर्न के लिए कोई प्रभार/संदाय नहीं किया जाएगा।

- (2) ए.वी.आर.के. लिए प्रभार/संदाय उस तिथि से प्रवृत्त होगा व उस नाममात्र पैसा/के.वी.आर. दर पर होगा जैसाकि समय-समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और ए.वी.आर. अंतर विनिमय के लिए फायदाग्राही तथा राज्य पूल खाते के बीच होंगी।
- (3) उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी, एस.एल.डी.सी. ग्रिड की सुरक्षा की दशा में या किसी उपकरण की सुरक्षा को खतरे की दशा में अपने ए.वी.आर. निकासी/इंजेक्शन में कमी करने के लिए फायदाग्राही को निर्देश दे सकेगा।
- (4) साधारणतः फायदाग्राही, जब वोल्टता 95 प्रतिशत से नीचे रेटिंग की जाती है, अंतरविनिमय पर ए.वी.आर. निकासी को कम करने का प्रयास करेगा और ए.वी.आर. को तब वापस नहीं करेगा जब वोल्टता 105 प्रतिशत से अधिक हो जाती है। अपने-अपने निकासी बिन्दु पर आई.सी.टी. टैप को एस.एल.डी.सी. को फायदाग्राही के अनुरोध के अनुसार ए.वी.आर. अंतर विनिमय का नियंत्रण करने के लिए परिवर्तित किया जाएगा, किन्तु यह सब युक्तियुक्त अंतरालों पर किया जाएगा।
- (5) संपूर्ण ग्रिड के सभी 400 के.वी.एस. तथा लाईन रिएक्टर्स की स्विचिंग इन/आउट एस.एल.डी.सी. के अनुदेशों के अनुसार की जाएगी। सभी 400/200/132 के.वी. आई.सी.टी. पर टैप परिवर्तन भी एस.एल.डी.सी. के अनुदेशों पर ही किया जाएगा।
- (6) आई.ए.एस.जी.एस., एस.एल.डी.सी. के अनुदेशों के अनुसार, अपने-अपने उत्पादन यूनिटों की क्षमता सीमाओं के भीतर रिएक्टिव ऊर्जा को उत्पादित/आमेलित करेगा अर्थात् जो उस समय अपेक्षित सक्रिय उत्पादन को बंद किये बिना है। ऐसे वी.ए.आर. उत्पादन/सम्मेलन के लिए उत्पादन कंपनियों से कोई संदाय नहीं लिया जाएगा।
- (7) दो फायदाग्राहियों के बीच उनके स्वामित्वाधीन (संयुक्त या एकल) अंतर संयोजन लाईन पर प्रत्यक्ष वी.ए.आर. विनिमय से साधारणतः क्षेत्रीय ग्रिड के वोल्टता प्रोफाइल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तदनुसार ऐसी लाईनों पर ए.वी.आर. विनिमय से प्रबंधन/नियंत्रण तथा वाणिज्यिक उठाई-धराई प्रत्येक अलग-अलग मामले के आधार पर निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार होगी:-
 - (i) दो संबंधित फायदाग्राही अंतर संयोजन लाईन पर उनके बीच वी.ए.आर. विनिमय के लिए कोई प्रभार/संदाय के लिए परस्पर करार नहीं कर सकेंगे।
 - (ii) दो संबंधित फायदाग्राही ए.आई.एस.टी.एस. के साथ वी.ए.आर. विनिमय के लिए आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट पहचान या अंतर के लिए उनके बीच वी.ए.आर. विनिमय के लिए संदाय दर/स्कीम को स्वीकार करने पर परस्पर सहमत नहीं हो सकेंगे।
 - (iii) यदि संबंधित फायदाग्राहियों के बीच असहमति होने की दशा में (अर्थात् एक पक्षकार वी.ए.आर. विनिमय के लिए प्रभार/संदाय करना चाहता है और दूसरा पक्षकार उस स्कीम से इन्कार करना चाहता है) तो अनुसूची-2 में यथा विनिर्दिष्ट स्कीम लागू होगी। प्रति के.वी.आर. एच. दर ए.आई.एस.टी.एस. के बीच और वी.ए.आर. विनिमय के लिए आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दर होगी।

- (iv) ऐसे वी.ए.आर. विनिमय की संगणना तथा संदाय से दो फायदाग्राहियों के बीच तय पारस्परिक करार प्रभावित होगा।

परिशिष्ट-1

[विनियम 5.1 (iv) निर्दिष्ट]

सम्पूरक वाणिज्यिक तंत्र

(उस तिथि से लागू जो अन्तरराज्यीय ए.बी.टी. के प्रारम्भ होने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित की जाए)

- (1) फायदाग्राही आयोग की सुसंगत अधिसूचनाओं तथा आदेशों के अनुसार, अनुसूचित प्रेषण के लिए संयंत्र उपलब्धता और ऊर्जा प्रभारों के तत्स्थानी क्षमता प्रभार अपने-अपने आई.ए.एस.जी.एस. को संदाय करेंगे। इस प्रभारों के लिए बिलों को मासिक आधार पर प्रत्येक फायदाग्राही को अपने-अपने आई.ए.एस.जी.एस. द्वारा जारी किया जाएगा।
- (2) सभी फायदा ग्राहियों से उपरोक्त दो प्रभारों की राशि की प्रतिपूर्ति दी गयी प्रेषण अनुसूची के अनुसार उत्पादन के लिए आई.ए.एस.जी.एस. को पूर्णतः की जाएगी। प्रेषण अनुसूची से विचलन की दशा में, संबंधित आई.ए.एस. जी.एस. को एम.आई. तंत्र के माध्यम से अधिक उत्पादन के लिए अतिरिक्त संदत्त किया जाएगा। दी गयी प्रेषण अनुसूची से नीचे किये जा रहे वास्तविक उत्पादन की दशा में, जब व जहां आयोग द्वारा अनुमोदित होने पर संबंधित आई.ए.एस.जी.एस. उत्पादन में कमी के लिए यू.आई. तंत्र के माध्यम से पुनः संदाय करेगा।
- (3) प्रत्येक आई.ए.एस.जी.एस./आई.एस.जी.एस. से केन्द्रवार एक्स ऊर्जा संयंत्र प्रेषण अनुसूचियों के संकलन तथा प्रत्येक फायदाग्राही के किसी द्विपक्षीय अन्तर विनिमय के पारेषण हानियों के लिए समायोजित किया जाएगा और इस प्रकार संगणित कुल निकासी अनुसूची की तुलना फायदाग्राही की वास्तविक कुल निकासी के साथ की जाएगी। अधिक निकासी की दशा में, फायदाग्राही से अधिक ऊर्जा के लिए यू.आई. तंत्र के माध्यम से संदाय करने की अपेक्षा की जाती है। कम निकासी की दशा में, निकासी न की गयी ऊर्जा के लिए यू.आई. तंत्र के माध्यम से फायदाग्राही को पिछला संयंत्र किया जाएगा।
- (4) जब संघटक से अनुरोध प्राप्त होता है तब एस.एल.डी.सी. राज्य के भीतर या राज्य की सीमाओं के आस-पास अवस्थित विक्रेता/क्रेता और अनुसूचित अन्तर विनिमय की व्यवस्था करने वाले संघटक की सहायता करेगा। एस.एल.डी.सी. केवल सुसाध्य बनाने वालों के रूप में कार्य करेगा (न कि व्यापारी/ब्रोकर के रूप में) और दो पक्षकारों के बीच हुए करार के अधीन दायित्व माना जाएगा सिवाय:-
 - (i) यह अभिनिश्चित करते हुए कि किसी अन्य संघटक की ऊर्जा प्रणाली के संघटक ऐसे अन्तर विनिमय/व्यापार द्वारा अधिक प्रभाव पड़ेगा।
 - (ii) संबंधित संघटकों के लिए अन्तर विनिमय अनुसूचियों में तय अन्तर विनिमय/व्यापार को समामेलित करेंगे।
- (5) राज्य संघटकों व आर.ई.ए. द्वारा वास्तविक निकासी/इन्जैक्शन्स के आधार पर राज्य ऊर्जा लेखा व यू.आई. प्रभार विवरण साप्ताहिक रूप से तैयार किये जाएंगे तथा इन्हें पिछले रविवार के तुरन्त पश्चात् के रविवार की अर्द्धरात्रि पर समाप्त होने वाले सात दिन की अवधि हेतु सोमवार तक सभी संघटकों को जारी किया जाएगा। यू.आई. प्रभारों के संदाय को उच्च पूर्विकता देनी होगी तथा संबंधित संघटक एस.एल.डी.सी. द्वारा प्रचालित राज्य यू.आई. पूल खाते में जारी विवरण के सात दिन के भीतर उपदर्शित रकम का संदाय करेंगे। उस अभिकरण जिसे यू.आई. प्रभारों के मददे धन प्राप्त करना है, को तब पांच कार्यदिवस के भीतर राज्य यू.आई. पूल खाते से संदत्त किया जाएगा।

- (6) एस.एल.डी.सी. ऐसे सभी संघटकों को, जिनके पास कम/उच्च वोल्टता की स्थिति के अन्तर्गत रिएक्टिव ऊर्जा की कुल निकासी/इंजैक्शन है, वी.ए.आर. प्रमारों के लिए साप्ताहिक विवरण भी जारी करेगा। इन संदायों को भी उच्च पूर्विकता दी जाएगी तथा संबंधित संघटक जारी विवरण के सात दिन के भीतर एस.एल.डी.सी. द्वारा प्रचालित राज्य रिएक्टिव खाते में उपदर्शित रकम का संदाय करेंगे। ऐसे संघटक को जिसे वी.ए.आर. प्रमारों के मददे धन प्राप्त करना है। पांच कार्य दिवस के भीतर राज्य रिएक्टिव खाते में से संदत्त किया जाएगा।
- (7) यदि उपरोक्त यू.आई. तथा वी.ए.आर. को प्रति दो दिन, अर्थात् संदायों में जारी विवरण से नौ दिन में बाद से अनाधिक तक विलम्ब किया जाता है तो व्यतिक्रमी संघटक को विलम्ब के लिए प्रत्येक दिन के लिए 0.04 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करना होगा। इस प्रकार एकत्रित ब्याज को ऐसे संघटकों को संदत्त किया जाएगा जिन्हें उस संदाय की रकम प्राप्त करनी थी, जो विलम्ब से प्राप्त हुई थी। लगातार संदाय में व्यतिक्रम, यदि कोई हो, को उपचारात्मक कार्यवाही आरम्भ करने के लिए एस.टी.यू. को एस.एल.डी.सी. द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा।
- (8) प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक सभी वी.ए.आर. प्रमारों का संदाय करने के पश्चात् राज्य रिएक्टिव खाते में रखे अधिशेष धन एस.एल.डी.सी. प्रचालकों के प्रशिक्षण के लिए और वैसे ही प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा जो अपने-अपने राज्य ग्रिडों के प्रचालन में सुधार करने/कारगर बनाने में सहायता करेगा जैसा समय-समय पर अपने एस.टी.यू. द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।
- (9) यदि राज्य ग्रिड की वोल्टता प्रोफाइल में उस सीमा तक सुधार होता है कि सप्ताह के लिए राज्य वी.ए.आर. प्रमार खातों से कुल संदाय उस सप्ताह के लिए संदत्त की जा रही कुल रकम से अधिक है और यदि राज्य रिएक्टिव खातों में घाटे को पूरा करने के लिए कोई अतिशेष नहीं है तो उपरोक्त खाते में उपलब्ध कुल धन के अनुसार आनुपातिक रूप से धन में कमी की जाएगी।
- (10) एस.एल.डी.सी., जी.सी.सी. की बैठक में राज्य यू.आई. लेखा व राज्य रिएक्टिव ऊर्जा लेखा का पूर्ण विवरण तिमाही आधार पर रखेगा।
- (11) सभी 15 मिनट के ऊर्जा आंकड़े (कुल अनुसूचित, वास्तव में मीटरित तथा यू.आई.) को निकटतम 0.01 एम. डब्ल्यू.एच. से पूर्णांकित किया जाएगा।

परिशिष्ट-2

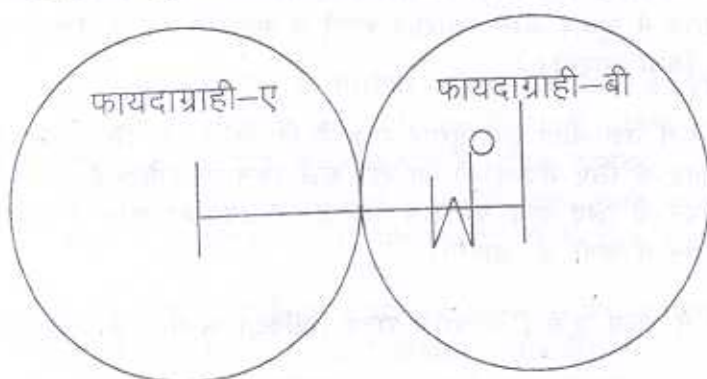
[विनियम 5.6 (7) (iii) निर्दिष्ट]

फायदाग्राही के स्वामित्व वाली लाइनों पर रिएक्टिव ऊर्जा विनियमों हेतु भुगतान

केस-1:-

फायदाग्राही-ए के स्वामित्व वाली अन्तः संयोजक लाईनें

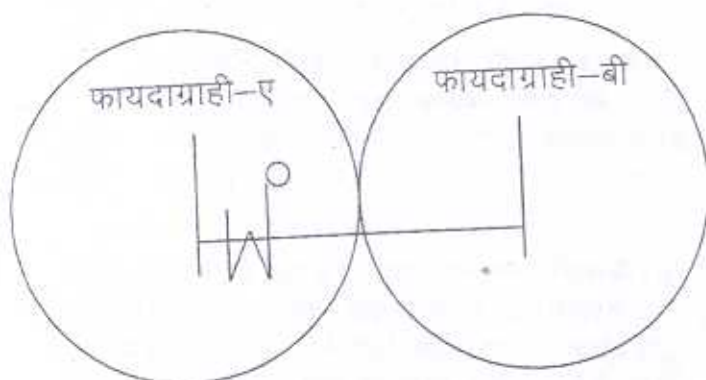
मीटरिंग बिन्दु: फायदाग्राही-बी का उपस्टेशन



केस-2:-

राज्य-बी के स्वामित्व वाली अन्तः संयोजक लाईनें

मीटरिंग बिन्दु: फायदाग्राही-ए का उपस्टेशन



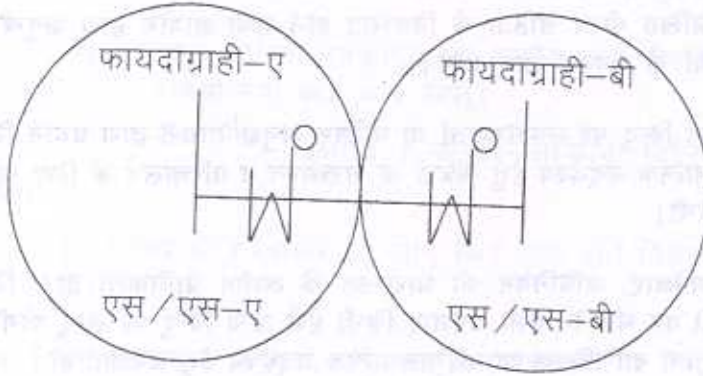
फायदाग्राही-बी को फायदाग्राही-ए निम्नलिखित के लिए भुगतान करता है :-

- (i) 97 प्रतिशत से निम्न वोल्टेज होने पर फायदाग्राही-ए से प्राप्त शुद्ध वी.ए.आर.एच. तथा
- (ii) 103 प्रतिशत से अधिक वोल्टेज होने पर फायदाग्राही-ए को आपूर्ति की गयी शुद्ध वी.ए.आर.एच.

केस-3:-

अन्तः संयोजक लाईन संयुक्त रूप से फायदाग्राही-ए व फायदाग्राही-बी के स्वामित्व में है

मीटरिंग बिन्दु: फायदाग्राही-ए व फायदाग्राही-बी के उपस्टेशन



एस/एस-ए से एक्सपोर्टेड कुल वी.ए.आर.एच. जबकि वोल्टेज < 97 प्रतिशत = $\times 1$

एस/एस-ए से एक्सपोर्टेड कुल वी.ए.आर.एच. जबकि वोल्टेज > 103 प्रतिशत = $\times 2$

एस/एस-ए से एक्सपोर्टेड कुल वी.ए.आर.एच. जबकि वोल्टेज < 97 प्रतिशत = $\times 3$

एस/एस-ए से एक्सपोर्टेड कुल वी.ए.आर.एच. जबकि वोल्टेज > 103 प्रतिशत = $\times 4$

i) फायदाग्राही-बी, फायदाग्राही-ए को निम्नलिखित के लिए संदाय करते हैं :-

$\times 1$ या $\times 3$ जो भी आकार में छोटा है।

ii) फायदाग्राही-ए, फायदाग्राही-बी को निम्नलिखित के लिए संदाय करते हैं :-

$\times 2$ या $\times 4$ जो भी आकार में छोटा है।

टिप्पणी:-

- 1) कुल वी.ए.आर.एच. या कुल संदाय सकारात्मक या नकारात्मक हो सकेगा।
- 2) यदि $\times 1$ सकारात्मक है व $\times 3$ नकारात्मक है या इसके विपरीत है तो उपरोक्त (i) के अधीन कोई संदाय नहीं होगा।
- 3) यदि $\times 2$ सकारात्मक है व $\times 4$ नकारात्मक है या इसके विपरीत है तो उपरोक्त (ii) के अधीन कोई संदाय नहीं होगा।

अध्याय 6-मीटरिंग संहिता

6.1 मीटरिंग अपेक्षाएं :

- (1) राज्य पारेषण उपयोगिता एक मीटरिंग संहिता विकसित करेगी तथा इसे, इन विनियमों की अधिसूचना से साठ (60) दिन के भीतर अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

किन्तु यह कि ऊपर लिखित मीटर संहिता के विकसित होने तथा आयोग द्वारा अनुमोदित होने तक प्रचलित सुसंगत विधियों के उपबंध लागू होंगे।

- (2) मीटरिंग संहिता संयोजन बिन्दु पर उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान किये जाने वाले वाणिज्यिक व परिचालनात्मक उद्देश्य हेतु मीटरों के संस्थापन व परिचालन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं व मानक उपबंधित करेगी।

परन्तु, यह कि ऐसी अपेक्षाएं, अधिनियम की धारा-55 के अधीन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये अनुसार होंगी। साथ ही यह भी कि, ऐसी अपेक्षाएं किसी ऐसे अन्य बिन्दु पर लागू होंगी जो कि, ऐसे मीटरों द्वारा प्रगृहीत सूचना वाणिज्यिक या परिचालनात्मक उद्देश्य हेतु अपेक्षित होने पर उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की ऊर्जा प्रणाली के आंतरिक होगा।

- (3) आयोग, राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत मीटरिंग संहिता की समीक्षा करेगा तथा या :-

- (i) ऐसी शर्तों या आशोधनों के साथ मीटरिंग संहिता को अनुमोदित करेगा जिन्हें आयोग उचित समझे, या
- (ii) यदि मीटरिंग संहिता, अधिनियम या इन विनियमों या अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (एच) के अधीन विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड के अनुरूप नहीं है तो लिखित में कारण अभिलिखित कर इसे निरस्त करेगा तथा राज्य पारेषण उपयोगिता को एक संशोधित प्रारूप प्रस्तुत करने का निर्देश देगा।

- (4) राज्य पारेषण उपयोगिता, अपने इन्टरनेट वेबसाइट में मीटरिंग संहिता की प्रति डालेगी तथा ऐसी कीमत पर जो इसे प्रत्युत्पादित करने के लिए उचित हो, पर इसके लिए निवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, लागू संहिता की एक प्रति उपलब्ध कराएगी।

- (5) मीटरिंग संहिता, मीटरिंग के स्वामित्व व इसके अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी, संबंधित अभिकरण अर्थात् उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की स्पष्ट रूप से पहचान करेगी।

- (6) मीटरिंग संहिता में निम्नलिखित सम्मिलित होगा व उसका वर्णन होगा :-

- (i) मीटरों की अवस्थिति व संस्थापना से संबंधित उपबंध;
- (ii) मीटरों के लिए विशिष्टताएं व शुद्धता सीमाएं;
- (iii) मीटरों से संकलित डाटा के अभिलेखन, संकलन, अन्तरण, प्रसंस्करण व भण्डारण से संबंधित अधिकार, उत्तरदायित्व व प्रक्रियाएं;
- (iv) मीटरिंग डाटा के स्वामित्व से संबंधित उपबंध;
- (v) उपरोक्त शुद्धता सीमा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संबंधित अभिकरण द्वारा अपनायी जाने वाली अंशघोशन प्रक्रिया;

- (vi) मीटरों का उचित कार्यावस्था में रख-रखाव, मीटरों की सुरक्षा, बदले गये/नये मीटरों का परीक्षण, मीटरों की सीलिंग व मीटरों के परीक्षण से संबंधित प्रक्रिया;
- (vii) मीटरों पर पहुंच के अधिकारों से संबंधित उपबंध;
- (viii) मीटरों में अन्तर, त्रुटिपूर्ण उपकरण व मीटर विफलता को संबोधित करने की प्रक्रिया;
- (ix) मीटरिंग से संबंधित मामलों पर विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया;
- (x) राज्य पारेषण उपयोगिता या आयोग द्वारा मीटरिंग संहिता में सम्मिलित करने हेतु उचित समझा गया कोई अन्य पहलू।

अध्याय 7-अन्तर-राज्यिक विनियम

7.1 प्रस्तावना :

- (1) इन लिंक्स के परिचालन हेतु लागू किये जाने वाले विशेष प्रतिफल इस अध्याय में नियत किये गये हैं।
- (2) इस अध्याय के अनुबन्ध, परिचालन आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए एस.टी.यू. (एस.एल.डी.सी. के परिचालक के रूप में) द्वारा अनुपूरित किये जा सकते हैं। अन्य अन्तर-राज्यिक लिंक्स के परिचालन में आने पर इनके संशोधन/अद्यतन की भी आवश्यकता होगी। कुछ समय पश्चात् यह उत्तरदायित्व एस.टी.यू. को अंतरित कर दिया जाएगा तथा एस.जी.सी. से यह अध्याय वापस ले लिया जाएगा।
- (3) वर्तमान अन्तर-राज्यिक लिंक्स क्योंकि उत्तर क्षेत्रीय ग्रिड के साथ एक कालिक ए.सी. लिंक्स हैं, राज्य व उत्तरी ग्रिड के मध्य ऊर्जा अंतर परिवर्तन, राज्य व अन्य क्षेत्रीय संघटकों के सापेक्ष भार उत्पादन पर निर्भर करता है।

7.2 आई.ए.एस.जी.एस. का अनुसूचीकरण :

- (4) सभी आई.ए.एस.जी.एस. को राज्य के एस.एल.डी.सी. के माध्यम से अनुसूचित किया जाएगा। भले ही अन्य राज्यों में उनके फायदाग्राही हों। दूसरे शब्दों में, एक आई.ए.एस.जी.एस. केवल मेजबान एस.एल.डी.सी. से ही वार्तालाप करेगा। अन्य राज्यों के फायदाग्राहियों के आवंटन हेतु मेजबान एस.एल.डी.सी., एन.आर.एल.डी.सी. के माध्यम से संबंधित आर.एल.डी.सी. के साथ, उनके मध्य तय की गयी रीतियों के अनुसार वार्तालाप करेगा। इसके बाद संबंधित आर.एल.डी.सी., संबंधित फायदाग्राही के एस.एल.डी.सी. से वार्ता करेगा और फिर एन.आर.एल.डी.सी. से पुनः संपर्क करेगा।
- (5) एस.एल.डी.सी., यदि संभव हो तो फूल्ड आधार पर वोल्टेज स्तरवार, राज्य के भीतर पारेषण हानियों का आकलन व प्रभाजन करेगा तथा 0.1 एम.डब्ल्यू. के रिजोल्यूशन के साथ फायदाग्राही की निकासी अनुसूची व अन्तर-राज्यिक अनुसूची के निर्धारण के उद्देश्य हेतु राज्य के बाहर अन्तर-राज्यिक पारेषण हानियां उनमें जोड़ेगा।

7.3 अनुसूचीकरण के उत्तरदायित्व का सीमांकन :

- (1) एस.एल.डी.सी., अन्य राज्यों/क्षेत्रों के साथ राज्य के अन्तर परिवर्तनों को अनुसूचित करेगा।
- (2) एस.एल.डी.सी., अन्तर-राज्यिक लिंक्स पर एक पर्याप्त सुरक्षा मार्जिन रखते हुए, अनुसूचित इम्पोर्ट सीमित कर, एन.आर. ग्रिड का ऊर्जा विनियम अनुसूचित करेगा। यह अन्तर-राज्यिक टाईज पर ऊर्जा प्रवाह को मॉनीटर भी करेगा तथा ओवर लोडिंग की दशा में एन.आर.एल.डी.सी. से कुछ ऊर्जा प्रवाह अपवर्तित/कम करने का निवेदन कर सकता है। यदि अपेक्षित सहायता तत्काल नहीं मिलती है या सम्भव नहीं है तो एस.एल.डी.सी. अपने स्वयं के क्षेत्र में कोई आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश देगा।

- (3) यह आशा की जाती है कि सामान्य अनुक्रम में उपलब्ध सभी पारेषण तत्वों के साथ राज्य व एन.आर. ग्रिड के मध्य कोई पारेषण अवरोध नहीं होंगे। यदि कोई अवरोध पैदा होते हैं तो आवश्यक होने पर एस.एल.डी.सी., एन.आर.एल.डी.सी. के साथ समन्वय करेगा।

7.4 अनुसूचीकरण तथा यू.आई. लेखांकन के लिए अन्तरापृष्ठ :

- (1) वर्तमान राज्य सीमाओं की एक सूची उनकी क्षमताओं, वोल्टेज, विशिष्टताओं इत्यादि के साथ एस.एल.डी.सी. द्वारा तैयार की जाएगी तथा निरंतर अद्यतन की जाएगी जिससे अन्तर-राज्यिक विनियम का अनुसूचीकरण, मीटरिंग व यू.आई. लेखांकन के लिए अन्तर-राज्यिक लिंक्स की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित हो सके।
- (2) यू.आई. के अन्तर-राज्यिक विनियम, एन.आर. में यू.आई. दर पर होंगे। अन्तर-राज्यिक विनियम हेतु भुगतान, राज्य व क्षेत्रीय यू.आई. पूल एकाउन्ट के मध्य होगा। परन्तु, अन्तर-राज्यिक ए.बी.टी. की संस्थापना के पश्चात् राज्य पूल एकाउन्ट परिचालित होने तक वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी।
- (3) अन्तर क्षेत्रीय अनुसूचियों से लिंकवार/अनुसूचियों को विभाजित करने का प्रयास नहीं किया जाएगा।

अध्याय 8-राज्य ग्रिड संहिता का प्रबन्धन

8.1 एस.जी.सी. का प्रबन्धन :

- (1) राज्य ग्रिड संहिता (एस.जी.सी.) को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। एस.जी.सी. में कोई संशोधन भी केवल आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (2) राज्य ग्रिड संहिता की, प्रत्येक 12 (बारह) माह में कम से कम एक बार ग्रिड समन्वय समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी।
- (3) इस समीक्षा के पूर्ण हो जाने पर ग्रिड समन्वय समिति निम्नलिखित से सम्बन्धित सूचना प्रदान करते हुए राज्य पारेषण उपयोगिता को एक रिपोर्ट भेजेगी :-
 - (i) समीक्षा का परिणाम;
 - (ii) राज्य ग्रिड संहिता में कोई प्रस्तावित संशोधन।
- (4) राज्य पारेषण उपयोगिता, उपविनियम (3) में उल्लिखित रिपोर्ट आयोग को भेजेगी।
- (5) एस.जी.सी. तथा इसके संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा तथा आयोग द्वारा जारी विनियमों हेतु अपनायी जाने वाली निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिसूचित किया जाएगा।
- (6) एस.जी.सी. में संशोधनों/परिशोधनों तथा कठिनाईयों के दूर करने के अनुरोध आवधिक विचार, परामर्श व निबटारे के लिए आयोग के सचिव को सम्बोधित किये जाएंगे।
- (7) एस.जी.सी. की व्याख्या से सम्बन्धित कोई शंका या विवाद आयोग के सचिव को सम्बोधित किये जाएंगे तथा आयोग द्वारा स्पष्टीकरण अन्तिम तथा सभी सम्बन्धितों पर आबद्ध समझा जायेगा।

8.2 संशोधन की शक्ति :

आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किन्हीं उपबन्धों को परिवर्तित, परिशोधित या संशोधित कर सकता है।

8.3 कठिनाइयां दूर करने की शक्ति :

यदि इन विनियमों के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है तो आयोग एक सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसे उपबन्ध बना सकता है जो कि कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

आयोग की आज्ञा से

आनन्द कुमार,
सचिव

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 जून, 2007 ई0 (आषाढ़ 02, 1929 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, कोटद्वार (गढ़वाल)

11 मई, 2007 ई0

संख्या उपनियम/ठे0पं0/06-07-नगरपालिका परिषद्, कोटद्वार (गढ़वाल) द्वारा अपनी सीमान्तर्गत अपने वर्तमान ठेकेदारी पंजीकरण उपनियम सं0-6, 10, 12, 14 व 21, जो कि निम्न वर्णित सूची के कॉलम 1 में उ0प्र0 न0पा0 अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) सूची-1 जे0(डी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बनाये गये हैं तथा वर्तमान में लागू हैं, में संशोधन की प्रस्तावना की गई है। निम्न वर्णित सूची के कॉलम में सम्बन्धित उपनियम बिन्दुओं के अनुसार कॉलम 2 में उल्लिखित शुल्क की दरों में अपने प्रस्ताव सं0-3, दि0 26-6-2006 के अनुसार संशोधन की प्रस्तावना की गयी थी, जिसका प्रारूप समस्त प्रभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से दैनिक "शाह टाइम्स" दि0 29-12-2006 के अंक में प्रकाशित किये गये थे। ठेकेदारी पंजीकरण उपनियमों सं0-6, 10, 12, 14 व 21 में संशोधन की प्रस्तावना की गई, जो कि म्यु0 ऐक्ट 1916 की धारा 301 (1) के अनुरूप समस्त प्रभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ एवं सुझाव हेतु दैनिक समाचार पत्र "शाह टाइम्स" में दिनांक 29-12-2006 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी, निर्धारित समयान्तर्गत केवल एक आपत्ति प्राप्त हुई, जो कि बोर्ड की बैठक दिनांक 22-3-2007 के प्र0सं0-3 में प्रस्तुत की गयी, बोर्ड द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर विचार एवं निर्णय उपरान्त निरस्त किया गया। अतः प्रस्तावित संशोधित उपनियमों को उक्त अधिनियम की धारा 298 (2) सूची-1 जे0 (डी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड शासकीय साधारण गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ठेकेदारी पंजीकरण उपनियम सं0	वर्तमान दरें	संशोधित दरें
1	2	3
उपनियम सं0 6 ठेकेदारों का पंजीकरण		
(1) "क" श्रेणी ठेकेदार	1,00,000/- या उससे अधिक लागत के कार्य	5,00,000/- या उससे अधिक लागत के कार्य
(2) "ख" श्रेणी ठेकेदार	50,000/- से अधिक किन्तु 1,00,000/- से कम लागत के कार्य	2,00,000/- से अधिक किन्तु 5,00,000/- से कम लागत के कार्य
(3) "ग" श्रेणी ठेकेदार	50,000/- से कम लागत के कार्य	2,00,000/- से कम लागत के कार्य

1 2 3
उपनियम सं0 6 में उल्लिखित "ग" श्रेणी के लिए अधिशासी अधिकारी स्वविवेकानुसार जांच व परीक्षण कर सकता है, के पश्चात् निम्न परिवर्द्धन किया गया।

"इसके अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी ठेकेदार को पंजीकरण हेतु अपनी हैसियत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।" "ए" श्रेणी ठेकेदार को 5.00 लाख, "बी" श्रेणी ठेकेदार को 3.00 लाख तथा "सी" श्रेणी ठेकेदार को 1.00 लाख रुपये से कम राशि मान्य नहीं होगी।

उपनियम सं0 10 पंजीकरण शुल्क

(1) "क" श्रेणी ठेकेदार	250/-	10,000/-रु0
(2) "ख" श्रेणी ठेकेदार	200/-	7,500/-रु0
(3) "ग" श्रेणी ठेकेदार	100/-	5,000/-रु0

उपनियम सं0 12 स्थाई प्रतिभूति हेतु

(1) "क" श्रेणी ठेकेदार	10,000/-	50,000/-रु0
(2) "ख" श्रेणी ठेकेदार	5,000/-	30,000/-रु0
(3) "ग" श्रेणी ठेकेदार	2,500/-	15,000/-रु0

उपनियम सं0 14 पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु

(1) "क" श्रेणी ठेकेदार	250/-	2,500/-रु0
(2) "ख" श्रेणी ठेकेदार	200/-	1,500/-रु0
(3) "ग" श्रेणी ठेकेदार	100/-	1,000/-रु0

उपनियम सं0 14 की द्वितीय पंक्ति में उल्लिखित "प्रत्येक वित्तीय वर्ष" के स्थान पर "प्रत्येक तीसरे वित्तीय वर्ष बाद" संशोधित किया गया।

उपनियम सं0 21 निविदा प्रपत्र का मूल्य

रु0 25,000/- से कम	100/-	अपमार्जित
रु0 25,000/- से 50,000/- तक	150/-	अपमार्जित
रु0 50,000/- से 1,00,000/- तक	250/-	2,00,000/-से कम 250/- रु0
रु0 1,00,000/- से 3,00,000/- तक	500/-	2,00,000/-से 5,00,000/- 500/- रु0
रु0 3,00,000/- से अधिक	1,000/-	5,00,000/-से अधिक 1,000/- रु0

ह0 (अपठित)

अध्यक्ष,

नगरपालिका परिषद, कोटद्वार (गढ़वाल)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/249-भाग 8-2007 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।